सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

07 मार्च, 2017

षोडश विधान सभा मंगलवार, तिथि 07 मार्च, 2017 ई0

पंचम सत्र 16 फाल्गुन, 1938(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

प्रश्नोत्तर काल ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ बोलने लगे)

(व्यवधान)

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम अपने स्थान पर खड़े हो गये)

पहले अल्प-सूचित प्रश्न होने दीजिये न ! उनपर तो चर्चा होगी न ! अब आप सबलोग स्थान ग्रहण कर लीजिये । आप ही लोगों का प्रश्न है । इन सब मामलों को उठाने का वक्त निर्धारित है नियमावली में, यह सब बात उठाइयेगा ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : समय पर उठाते हैं । जीरो आवर में उठायेंगे, खाली बताना चाहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपने सहयोगी अब्दुल जलील मस्तान जी को अभी तक बर्खास्त नहीं किया है, इसके विरोध में काली पट्टी बाँधकर हमलोग आये हैं, फिर आग्रह भी सरकार से कर रहे हैं । सरकार अविलम्ब कार्रवाई करे ।

महोदय, मैं रात भर गर्दनीबाग धरना स्थल पर था, रात भर वहाँ मुझे मच्छर काटता रहा । वहाँ निषाद विकास मंच के तहत मछुआरा की माँगों को लेकर, अनुसूचित जाति की माँग को लेकर मुकेश सहनी के साथ हजारों लोग और लगभग दो दर्जन लोग अनशन पर हैं । हम सरकार से माँग करते हैं कि मुकेश सहनी जो मछुआरों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, सरकार अविलम्ब संज्ञान ले, कार्रवाई करे ।

अध्यक्ष : अब अल्प-सूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-10 (श्री संजय सरावगी)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, क- वस्तुस्थिति यह है कि प्रथम एडुकेशन फॉन्डेशन के द्वारा बच्चों को Sampling के माध्यम से चिन्हित कर गृह-आधारित मूल्यांकन किया जाता है । इस मूल्यांकन के आधार पर बिहार राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा पर प्रतिवेदन प्रति वर्ष प्रकाशित होता है । यह प्रतिवेदन शिक्षा के गुणवत्ता पर सूचक की तरह होता है जिसका अध्ययन कर विभाग द्वारा शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार में विभिन्न हस्तक्षेप किये जाते हैं ।

ख- प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा निम्नांकित प्रयास किये जा रहे हैं :-

1. मिशन गुणवत्ता कार्यक्रम अंतर्गत वर्ग-1 एवं 2 के बच्चों के पठन-पाठन के लिए नामित शिक्षक की व्यवस्था ।

2. वर्ग-3 से 5 के बच्चों का दक्षता के आधार पर समूह निर्माण एवं समूह शिक्षण की व्यवस्था ।

3. वर्ष 2016-17 से मासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया प्रारंभ ।

4. यूनिसेफ के सहयोग से बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार के लिए राज्य के चयनित 5 जिला क्रमश: वैशाली, भोजपुर, गया, नवादा एवं पटना शहरी के एक-एक प्रखंड/वार्ड में पायलट आधार पर कार्य प्रारंभ किये गये हैं ।

5. स्कूल रेडिनेश प्रोग्राम अंतर्गत वर्ग-1 में नए नामांकित होने वाले बच्चों के लिए चहक कार्यक्रम का राज्य के प्रत्येक जिले के एक-एक प्रखंड के एक-एक संकुल के सभी विद्यालयों में क्रियान्वयन की तैयारी अंतिम चरण में है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब तो मंत्री जी दिये नहीं । मेरा प्रश्न यह था कि प्रथम ने, ए0एस0ई0आर0 ने जो सर्वेक्षण किया और यह कम्पनी बहुत प्रमाणिक कम्पनी है, बिहार सरकार ने भी इसको 2014 में हायर किया था, यूनिसेफ भी किया था और इसके रिपोर्ट को इकोनोमिक सर्वे ऑफ इंडिया भी मान्यता देती है, मैंने यह पूछा था कि क्या बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले वर्ग-3 के 21 प्रतिशत बच्चों को हिन्दी के अक्षर का ज्ञान नहीं है ? 33 प्रतिशत वर्ग-3 के बच्चे को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का ज्ञान नहीं है और कक्षा-5 के 71 प्रतिशत बच्चों को....

अध्यक्ष : संजय जी, जो आप बता रहे हैं, वह सब प्रश्न में लिखा हुआ है । मंत्री जी जवाब दिये।

श्री संजय सरावगी : स्वीकारात्मक है, यह तो बोले नहीं ।

अध्यक्ष : सुन लीजिये न ! अंत में आपने पूछा है कि अगर यह सही है तो गुणात्मक सुधार के लिये सरकार कौन काम कर रही है ?

श्री संजय सरावगी : सर, तीसरे खंड का उत्तर मंत्री जी दिये लेकिन पहले और दूसरे खंड का उत्तर नहीं दिये ।

अध्यक्ष : स्वाभाविक रूप से पहले और दूसरे खंड के हिसाब से कुछ कमी है तब न सुधार की बात कह रहे हैं ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, सरकार स्वीकारात्मक और अस्वीकारात्मक कहती है लेकिन न स्वीकारात्मक कहे, न अस्वीकारात्मक कहे और न आंशिक स्वीकारात्मक कहे । इसका मतलब हमलोग यह मानते हैं.....

अध्यक्ष : आप तो सुधार चाहते हैं न !

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, हम यह मानते हैं कि सरकार इसको स्वीकार कर रही है अगर सरकार गौण है तो !

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री संजय सरावगी : वही पूछ रहे हैं । माननीय मंत्री जी बड़ा-बड़ा भाषण चार दिन पहले दे रहे थे।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये न ! मंत्री जी तो रोज भाषण देते रहते हैं ।

श्री संजय सरावगी : बिहार के जो भविष्य हैं, जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र हैं, 2010 में, मैं केवल एक मिनट आपका समय चाहूंगा.....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिये न !

श्री संजय सरावगी : वही पूरक ही पूछ रहा हूँ । 2010 में वर्ग-5 के बच्चे जो दूसरे क्लास का पाठ पढ़ सकते थे, वह 2010 में 57 प्रतिशत थे और 2016 में इसकी संख्या घटकर 38 प्रतिशत हो गई । मतलब प्रत्येक साल अध्यक्ष महोदय, शिक्षा की गुणवत्ता का सरकारी विद्यालयों में ह्रास हो रहा है । वर्ग-3 के बच्चे जो कक्षा-2 के स्तर का घटाव नहीं जानते हैं, 2010 में 56 प्रतिशत था जो 2016 में बढ़कर 80 प्रतिशत हो गया है । कहने का मतलब है कि जो हमारे बिहार के भविष्य हैं जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, इतना जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है.....

अध्यक्ष : आप शिक्षा विभाग के डिमांड के दिन इसपर बोल लीजियेगा न ! अभी पूरक पूछिये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है कि जो इतना स्तर गिर गया है शिक्षा का बिहार में और भविष्य चौपट हो रहा है, सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, इसपर सीधे बतावे ।

अध्यक्ष : सरकार ने तो 5 उपाय बताया है ।

श्री संजय सरावगी : क्या उपाय बताया है ?

अध्यक्ष : इसका मतलब कि आपने सुना नहीं । वर्ग 1, 2 और 3 के लिये जो सरकार कर रही है, वर्ग 5 के लिये जो सरकार कर रही है, यूनिसेफ के साथ जो कर रही है, वह सब मंत्री जी ने बताया । एक बार मंत्री जी, फिर बता दीजिये ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता जायज है । पिछली सरकारों ने इस प्रदेश में मूलभूत संरचनाओं का विकास किया । माननीय सदस्य प्रथम के रिपोर्ट पर बात कह रहे हैं, यह बात सत्य है कि पहले विद्यालयों में हमारे बच्चे नहीं थे । आज यह सौभाग्य है बिहार का, बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहॉं मात्र 1 प्रतिशत बच्चे स्कूल से बाहर हैं । हमने इस प्रदेश में मिशन गुणवत्ता लाया है, इसलिये कि हमें कहीं न कहीं लगता है कि गुणवत्ता की कमी है । इसीलिये सरकार ने मिशन गुणवत्ता लाया है और जो सदस्य ने बात को उठाया है, निश्चित रूप से इनकी चिन्ता का हम सम्मान करते हैं और सरकार भी मानती है कि कहीं न कहीं गुणवत्ता में कमी है और इसीलिये मिशन गुणवत्ता लाकर इन 5-6 प्वायंट्स को हमने बताया है कि हम किस तरह से

प्रदेश में गुणवत्ता लाना चाहता हैं । ये जो रिपोर्ट 2010 का दे रहे हैं, 2010 में बच्चों की संख्या स्कूल में 25 प्रतिशत से ज्यादा थी जो बाहर थे, अब वे बच्चे स्कूल में आये हैं तो निश्चित रूप से गुणवत्ता को बहाल करने के लिये हम प्रयासरत हैं । हमने जो कार्यक्रम बताया है कि इन कार्यक्रम के माध्यम से हम गुणवत्ता बहाल करना चाहते हैं ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, सरकार जो बोल रही है कि कार्यक्रम लाया है, जो यूनिसेफ के साथ चल रहा है, यह तो कोई अभी दो महीने से नहीं ला रहे हैं, पहले से यह कार्यक्रम चल रहा है । उसके बाद भी प्रत्येक साल, जो रिपोर्ट है, प्रमाणिक रिपोर्ट है कि प्रत्येक साल शिक्षा के गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है तो सरकार क्या कोई नया कदम इसमें उठाना चाहती है ? अध्यक्ष महोदय, पूरा बिहार का भविष्य चौपट हो रहा है और सरकार कान बंद करके सोयी हुई है । कैसे चलेगा ?

अध्यक्ष : संजय जी, अब आप पुराने सदस्य हो गये । एक प्रश्न पर अपना भाषण तो नहीं दीजिये, पूरक पूछिये ।

श्री संजय सरावगी : वही तो पूछ रहे हैं ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को प्रथम का रिपोर्ट मिल गया, उसपर इन्होंने प्रश्न किया । प्रश्न के बाद हम जो जानकारी दे रहे हैं उसको सदस्य लेना नहीं चाह रहे हैं कि सरकार ने क्या कहा, ये कह रहे हैं कि यूनिसेफ से तो बहुत पहले से चल रहा है ।

पहली बार सरकार ने प्राइमरी में एसेसमेंट टेस्ट का प्रावधान किया है, वह पिछले वित्तीय वर्ष 2016 से शुरू हुआ है कि हरेक बच्चे जो प्रारंभिक विद्यालय में हैं, उनका हम एसेसमेंट टेस्ट करेंगे जैसा प्राइवेट स्कूल में होता है, हाफ ईयरली और ईयरली टेस्ट लेंगे । अभिभावकों को बुलायेंगे जैसे पैरेन्ट्स-टीचर मीटिंग्स होता है, उसके माध्यम से लोगों को बतायेंगे कि आपके बच्चे, क्योंकि स्कूल में बच्चों को रोकने का अधिकार हमारे पास नहीं है लेकिन हम उनके पिता को यह कह सकते हैं और टीचर को कि आपके विद्यालय में ये बच्चे पढ़ रहे थे, उनके मानसिक स्तर और उनका इंगलिश, हिन्दी और मैथ कितना इम्प्रुव किया है । यह एक नया इंटरफेरेंस है सरकार का प्रारंभिक में, यूनिसेफ के साथ भी जो हमलोग कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके भी दायरा को बढ़ाया है, चहक का कार्यक्रम 2016 में शुरू हुआ है । बहुत से कार्यक्रम यूनिसेफ के साथ हमलोग क्वालिटी एजुकेशन इम्प्रुव करने से पहले से करते रहे हैं लेकिन प्राइमरी सेक्टर में यह सब इनिशियल इनिसियेटिव है, 2016 में शुरू हुआ है ।

टर्न-2/आजाद/07.03.2017

अध्यक्ष : श्री नन्दकिशोर यादव ।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, विषय गंभीर हो गया है । महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं । सदन इस बात का गवाह है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में इस बात की घोषणा की थी कि जो गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको हम सरकारी स्कूलों में भर्त्ती करायेंगे और बड़े पैमाने पर अभियान चलायेंगे । जैसा माननीय मंत्री ने स्वयं भी अभी स्वीकार किया है कि केवल एक प्रतिशत बच्चे स्कूल से बाहर हैं । महोदय, सवाल यह खड़ा होता है और माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि पहली बार एसैसमेंट टेस्ट ये शुरू करने वाले हैं। महोदय, प्रश्न तो यह है कि क्या माननीय मुख्यमंत्री उस समय जब बच्चों को स्कूल में दाखिला कराने का अभियान चला रहे थे तो क्या इस बात का विचार नहीं किया कि बच्चों के पढ़ाई की गुणात्मक सुधार की कोशिश की जायेगी, एक सवाल खड़ा होता है महोदय । दूसरा प्रश्न यह है कि अंधाधुंध केवल नामांकन करने की कोशिश की गई, बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देने का प्रयास नहीं किया गया, शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो, इसका कोई कोशिश नहीं किया गया ? तीसरा प्रश्न यह है कि अगर पहली बार इस रिपोर्ट के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री पहली सरकार का नेतृत्व कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं तो क्या 10 साल तक उस समय के मुख्यमंत्री ने कोई इसका प्रयास नहीं किया, क्या उस समय के शिक्षा मंत्री ने गरीब के बच्चों को भगवान भरोसे स्कूल में नामांकन करा दिया, इसका जवाब माननीय मंत्री महोदय दें । महोदय, एक सवाल और है कहीं यह तो नहीं है कि जो दलों के अन्दर खींचतान हैं, ये कांग्रेस के मंत्री हैं और ये वाहवाही लूटना चाहते हैं, नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, कृपया इसका भी जवाब दें ?

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : सर, इतना काफी सीनियर पूर्व मिनिस्टर हैं, हम इनके कार्य प्रणाली को फोलो करने की कोशिश करते हैं लेकिन विचारधारा अलग-अलग है । माननीय पूर्व मंत्री जी को कहा, ये सदन के वरीय नेता हैं, मैंने कहा कि सरकार ने पहली बार एसैसमेंट कराया हाफ ईयरली, पहले हमारे पास बच्चों को रोकने का अधिकार नहीं था, हम फाईनल टेस्ट लेते थे और उसके बाद लड़कों को प्रोमोट करते थे लेकिन पहली बार हमलोगों ने हाफईयरली एसैसमेंट को इनसियेट किया है प्राईमरी सेक्शन में, हमलोगों ने मोडल क्वेश्चन पेपर, अन्सर पेपर सभी विद्यालयों में भेजा है और उसके माध्यम से इनसियेट कर रहे हैं । यह तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि हमारे मुखिया हैं महागठबंधन के लीडर, कैप्टेन का ही क्रेडिट और डिसक्रेडिट होता है । इन्होंने पहले मूलभूत संरचनाओं को विकास किया । पहले जो बच्चे स्कूल से बाहर थे, उनको विद्यालय में लाया । अब प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे बहाल हो, यह सरकार पहल कर रही है । यह सब जो हमलोगों ने एसैसमेंट किया है, उसके माध्यम से इस प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रयासरत हैं ।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, जब बच्चों को स्कूल में लाने में 10 साल लग गये इस सरकार को तो गुणवतापूर्ण शिक्षा बच्चों को देने में कितना साल लगेंगे, माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें ?

अध्यक्ष : चलिये, अब तारांकित प्रश्न । माननीय सदस्य मुन्द्रिका प्रसाद राय । शिक्षा विभाग।

तारांकित प्रश्न सं0-899(श्री मुन्द्रिका प्रसाद राय)

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्हीं अनुमण्डलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है, जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है । सारण जिलान्तर्गत पानापुर एवं इसुआपुर प्रखण्ड, मढ़ौरा अनुमण्डल के क्षेत्रान्तर्गत है, जहां पूर्व से ही अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में एच0आर0 कॉलेज, अमनौर संचालित है । प्रखण्डवार सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है । जिन प्रखण्डों में डिग्री कॉलेज संचालित नहीं है, वहां विश्वविद्यालयों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत अध्ययन केन्द्र खोला जा रहा है ।

श्री मुन्द्रिका प्रसाद राय : महोदय, एक अनुमंडल में एक एच0आर0 कॉलेज, अमनौर है । अनुमंडल में चार विधान सभा क्षेत्र है और चारों को कहीं भी वहां के बच्चों को पढ़ने जाने के लिए इतनी दूरी तय करनी पड़ती है । सबसे बड़ी बात यह है कि एक डिग्री कॉलेज में संकाय अनुसार सीट लीमीट है तो बच्चे कहां पढ़ने जायं, जब तक इस अनुमंडल में दूसरा डिग्री कॉलेज नहीं खोली जायेगी ?

अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए, आप क्या चाहते हैं ?

श्री मुन्द्रिका प्रसाद राय : महोदय, हम चाहते हैं कि पूरा प्रखंड जो है, वहां से अनुमंडल की 40 कि0मी0 दूरी है । हम चाहते हैं कि पानापुर प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज खोला जाय । यदि सरकार चाहती है तो निश्चित तौर पर हमारा यह मांग है कि इतनी दूरी को देख करके वहां पर एक डिग्री कॉलेज खोला जाय ।

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : महोदय, प्रखंडवार डिग्री कॉलेज खोलने का प्रावधान नहीं है लेकिन हमारे बच्चे-बच्चियां वहां पर हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए सरकार ने पिछले साल निर्णय किया है दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की व्यववस्था की जायेगी, जहां पर प्लस-टू के स्कूल,कॉलेज हैं, वहां पर हम इसका यूनिट खोलेंगे और इसके लिए हमलोग 200-250 खोला है । अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो जिस प्रखंड में ये कह रहे हैं, जहां पर महाविद्यालय नहीं होता है, वहां पर हम इसकी व्यवस्था कराते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है । तारांकित प्रश्न सं0-900, माननीय सदस्य श्री सरोज यादव ।

तारांकित प्रश्न सं0-900(श्री सरोज यादव)

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी बबूरा एवं विशुनपुर पंचायत के छात्र/छात्रा बबूरा उच्च विद्यालय में पढ़ने जाते हैं । बबूरा उच्च विद्यालय, पश्चिमी बबूरा पंचायत में अवस्थित है । छात्र/छात्राओं को 2-3 कि0मी0 तक जाना पड़ता है । पूर्वी बबूरा पंचायत में दो मध्य विद्यालय हैं, मध्य विद्यालय, फुहाँ जो भवन सहित 40 डिसमिल में बना हुआ है और दूसरा मध्य विद्यालय, कोहला रामपुर जिसके पास भूमि 0.1 एकड़ ही है । उसी प्रकार विशुनपुर पंचायत में दो उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बन्धु छपरा जिसे 10 डिसमिल जमीन है एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बिनगांवाँ जिसके पास भूमि 0.04 एकड़ है ।

विभागीय संकल्प संख्या-1021 दिनांक 07.05.2013 के आलोक में प्रश्नगत विद्यालय प्रावधानित शर्त को पूरा नहीं करते हैं ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, हम हाईस्कूल की बात कर रहे हैं, हमारा सरकार का भी सपना है कि हर पंचायत में हाईस्कूल खोलवाया जायेगा, मगर दोनों जो हमने बोला विशुनपुर पंचायत एवं एक पूर्वी बबूरा पंचायत, ये दोनों पंचायत में कहीं भी हाइस्कूल नहीं है । बच्चे-बच्चियों को पढ़ने जाने में काफी कठिनाई होती है और ....

अध्यक्ष : सरोज जी, आपकी बात को सरकार ने माना है लेकिन उसने कहा है कि जो उत्क्रमण के लिए क्राईटेरिया है, पैरामीटर्स है, इन दोनों पंचायतों में विद्यालयों के पास उतनी भूमि नहीं है, इसलिए नहीं कर पा रही है । सरकार ने यही कहा है ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, दोनों जगह भूमि है । अगर कहा जाय माननीय मंत्री जी द्वारा हम भूमि भी दिलवाने का प्रयास करेंगे ।

अध्यक्ष : जरूर । सरकार ने कहा है अगर उसके लिए जितनी रिक्वायर्ड, जितनी अपेक्षित भूमि का रकबा है, उतनी जमीन उपलब्ध करवाईयेगा तो सरकार विचार करेगी ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, एक और भी है ख्वासपुर हाईस्कूल में 10प्लस टू हो गया 2010 में ही, मगर आज तक उस स्कूल में अभी तक पढ़ाई आरंभ, शुरूआत नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : उसको आप अलग से दे दीजियेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-901(श्री जनार्दन मांझी)

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, शम्भुगंज के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बैदपुर पंचायत के मध्य विद्यालय, सिलौटा को मानक के अनुरूप जमीन उपलब्ध नहीं है । ऐसी परिस्थिति में मध्य विद्यालय, सिलौटा को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है ।

श्री जनार्दन मांझी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां एक ऐसा विद्यालय है, जो सबसे शंभुगंज प्रखंड से बहुत दूरी पर है और बच्चे का वहां एडमिशन नहीं हो पाता है, अदर्स विद्यालय में जाकर के ....

अध्यक्ष : सब बात तो सरकार ने कहा है, केवल जमीन के बारे में कह रही है, आप उनको जमीन उपलब्ध करा दीजिए ।

श्री जनार्दन मांझी : जमीन वहां उपलब्ध है, अगर कोई रिपोर्ट आया है तो वह गलत आया है ।

अध्यक्ष : आप दे दीजियेगा ।

श्री जनार्दन मांझी : जी, हां दे देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-902(श्री श्याम रजक)

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा,मंत्री : महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । 14 रिक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसपर माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 नं0-12513/2014 सूरज कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में दायर याचिका के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन रहने के कारण चयन की प्रक्रिया स्थगित है । ज्ञात हो कि तत्काल राज्य के नेत्रहीन उच्च विद्यालय, कदमकुँआ, पटना में दो नियमित, दो पुनर्नियोजित और दो मानदेय पर कुल मिलाकर 6 शिक्षक कार्यरत है । राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय, दरभंगा में 3 संविदा शिक्षक कार्यरत हैं ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो आज शिक्षक बहाल हैं संविदा के आधार पर, क्या वे ब्रेल लिपि से प्रांगत है, ब्रेल लिपि को उनको ज्ञान है, क्योंकि जो हमारे नेत्रहीन दिव्यांग बच्चे हैं, उनको ब्रेललिपि से पढ़ाया जाता है और उसकी जॉच होती है तो क्या उसमें जो इन्होंने संविदा पर दो या छः बहाल किया है और जो वहां पर प्राचार्य हैं, वे संगीत के ज्ञाता हैं, जबकि वहां पर विषयवार कोई शिक्षक नहीं है । क्या ब्रेललिपि के आधार पर वहां पर पढ़ाई कराना चाहते हैं ?

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा,मंत्री : महोदय, शिक्षक की कमी तो निश्चित रूप से है और इसलिए नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, लेकिन वह जो मामला है, वह माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, जब तक उच्च न्यायालय का डिसिजन नहीं आता है, तब तक जो शिक्षक है, उसी से काम चला रही है विभाग । जब तक माननीय उच्च न्यायालय का डिसिजन आ जायेगा, शिक्षक की बहाली निश्चित रूप से होगी ।

टर्न-3/शंभु/07.03.17

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि जो भी संविदा पर बहाल किये हैं तो संविदा पर ब्रेल लिपि जानने वाले जो लोग हैं, जिनको प्रमाण पत्र प्राप्त है- ऐसे शिक्षकों को क्यों नहीं संविदा पर बहाल कर सकते हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य का कंसर्न या चिंता है कि आप संविदा पर बहाल कर रही हैं या अभी जो काम कर रही हैं या जिनकी नियुक्ति आप करनेवाली हैं, चूंकि वहां पर ब्रेल लिपि जो दिव्यांगों के लिए बनायी गयी है, उसके जानकार लोगों की नियुक्ति हो रही है या नहीं अथवा वैसे जानने वाले लोग हैं कि नहीं- माननीय सदस्य यह जानना चाह रहे हैं। इसके बारे में कोई सूचना नहीं है तो लेकर दीजिएगा ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा,मंत्री : महोदय, मैं सूचना लेकर के माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूँगी।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, एक चीज और इसी से जुड़ा हुआ है। जो बच्चों का नामांकन होता है उसके लिए नामांकन कमिटी बनी हुई है और नामांकन कमिटी में नेत्र विशेषज्ञ डाक्टर को होना चाहिए और इन्होंने कमिटी में हड्डी रोग विशेषज्ञ को रखा है। अब हड्डी रोग विशेषज्ञ नेत्रहीन का जॉच कैसे करके नामांकन करायेगा ? क्या उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : यह तो सही बात है इसको देखवा लीजिएगा।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा,मंत्री : जी, मैं देखवा लूँगी।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, उसपर क्या जवाब दिये ?

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा,मंत्री : महोदय, जो माननीय सदस्य का पूरक प्रश्न है वह मेन प्रश्न में नही है इसीलिए मैं इसको देखवा करके जवाब भेजवा दूंगी।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, मंत्री महोदया सदन को गुमराह कर रही हैं। महोदय, वह कह रही हैं कि मेन प्रश्न में नहीं है, वह मेन प्रश्न में है।

अध्यक्ष : छोड़िए न वह बात हो गयी। आप पूछ लीजिए न।

श्री नन्दकिशोर यादव : महोदय, मूल सवाल तो वही है न। आपने भी इंगित किया है जब सात पद रिक्त हैं और अनुबन्ध पर बहाल करने का प्रावधान है। अनुबन्ध पर बिना ब्रेल लिपि जाने हुए लोगों की बहाली कर दी गयी तो बाकी जो रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों पर उस लिपि के जाननेवाले लोगों की बहाली सरकार कब तक कराना चाहती है ? क्या हाईकोर्ट ने अनुबन्ध की बहाली पर भी रोक लगाया है और यह बहाली कब तक सरकार करेगी ? यह जो विसंगति है, जो लोग दिव्यांग बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं उनकी बहाली प्राचार्य के पद पर, संगीत शिक्षक की बहाली प्राचार्य के पद पर यह सब जो विसंगति हो गयी है, अनियमितता हो गयी है उसको कब तक दूर करके- हाईकोर्ट के निर्णय जब आयेंगे तब आयेंगे, लेकिन रिक्त पदों पर अनुबन्ध पर बहाली कब तक सरकार करायेगी, इसका जवाब दीजिए।

अध्यक्ष : अनुबंध पर बहाली शीघ्र कर ली जाय, यह कह रहे हैं माननीय सदस्य।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा,मंत्री : सर, रिक्त पद तो है ही और उसपर नियुक्ति के लिए विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया था जो मामला हाईकोर्ट में लंबित हो गया है।

अध्यक्ष : आप नहीं समझ रही हैं । वह तो नियमित नियुक्ति की बात है न!

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा,मंत्री : जी।

अध्यक्ष : ये कह रहे हैं कि यदि नियमित बहाली हाईकोर्ट के द्वारा रोक दी गयी है तो तब तक अनुबन्ध पर तो आप बहाल कर सकती हैं। इसमें तीन बात आयी है, यह अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए, हम समझते हैं कि इसपर सारा सदन सहमत होगा, एक तो उसमें जो भी शिक्षक आएं वे ब्रेल लिपि के जानकार हों क्योंकि वे यदि नहीं जानकार हैं तो वहां वे पढ़ा ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात अगर उसके मैनेजिंग कमिटी में किसी डाक्टर या चिकित्सक का होना है तो वे नेत्र रोग विशेषज्ञ जाना चाहिए और तीसरी बात कि अगर नियमित नियुक्तियों में उच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगी है तो तत्काल पढ़ाई बाधित नहीं हो इसके लिए अनुबन्ध वाली नियुक्ति की प्रक्रिया तेज की जाय । ये तीनों बात है आप तीनों को देख लीजिए।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा,मंत्री : जी, निश्चित रूप से ये तीनों काम करवाकर के माननीय सदस्य को मैं बता दूंगी।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, यह विद्यालय मेरे घर से 1 कि0मी0 की दूरी पर है और बराबर मैं जाता हूँ।

अध्यक्ष : यह प्रश्न आप श्याम जी को दिये थे।

श्री संजय सरावगी : महोदय, पिछली बार मैं भी प्रश्न लाया था। महोदय, यहां दो विद्यालय एक ही कैंपस में है- एक नेत्रहीन और एक मूक बधिर दोनों की स्थिति नारकीय है। बहाली तो ठीक है, होना चाहिए लेकिन मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ यह मानवता की भी बात है- एक राज्य स्तरीय उच्च अधिकारी को उस विद्यालय को- बहुत विद्यालय नहीं पूरे राज्य में- एक उच्च स्तरीय पदाधिकारी को जो राज्य स्तर का हो, कम से कम वहां भेज दें और वहां की स्थिति देख लें और जॉच करा दें। इतनी नारकीय स्थिति है।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा,मंत्री : ठीक है महोदय, मैं देखवा लूँगी।

तारांकित प्रश्न सं0-903(श्री(मो0)आफाक आलम)

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद पटना से प्राप्त सूचना अनुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रखंडों में एक बालिका छात्रावास संचालित करने का प्रावधान है। पूर्णियां जिला अन्तर्गत कसबा प्रखंड के कलानंद उच्च विद्यालय गढ़बनैली में बालिका छात्रावास स्वीकृत एवं संचालित है।

श्री मो0 आफाक आलम : वहां कलानंद उच्च विद्यालय, के0डी0 गर्ल्स हाईस्कूल है। महोदय, मेरा कहना है कि के0डी0 गर्ल्स हाईस्कूल है और वहां काफी छात्राएं पढ़ती हैं, दूर दराज से आती हैं सब बच्ची उसको रहने का वहां कोई साधन नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि वहां छात्रावास बना देने से सभी बच्ची, गरीब बच्ची है वह लोग वहां छात्रावास में रहेगी। यह मांग हम कर रहे हैं।

तारांकित प्रश्न सं0-904(श्रीमती गुलजार देवी)

श्री विजय प्रकाश,मंत्री : उत्तर स्वीकारात्मक है। पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा इन स्थलों पर पूर्व में वृक्षारोपण नहीं कराया गया है। सभी स्थलों पर एक कतार में पौधा रोपण कार्य किया जा सकता है। आगामी वर्षों में योजना शुरू की जायेगी।

श्रीमती गुलजार देवी : मंत्री जी को धन्यवाद।

तारांकित प्रश्न सं0-905(श्री विजय कुमार सिन्हा)

अध्यक्ष : विजय कुमार सिन्हा जी, उत्तर दिया हुआ है, पूरक पूछिए।

श्री विजय कुमार सिन्हा : हमारा प्रश्न जो था कि लखीसराय जिलान्तर्गत अशोकधाम, घोसी कुंडी सहित लाल पहाड़ी सहित कई जगहों पर खुदाई से अनेक दुर्लभ मूर्तियां मिली है। जवाब दिया गया है कि उत्तर अस्वीकारात्मक है। राज्य सरकार द्वारा अब तक वहां उत्खनन का कोई कार्य नहीं कराया गया। महोदय, यह प्रमाण है कि एक महीना के लगभग अभी यहां से गये थे भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम और एस0एस0आइ0 के निदेशन पर नालन्दा संग्रहालय के पुरातत्व उपाधीक्षक एन0के0 सक्सेना- घोसी कुंडी पहाड़ी और आसपास के बस्तियों में जाकर निरीक्षण किये और महोदय देखा जाय कि ये सारी मूर्तियां वहां पर जो मिली है, कई मूर्तियां हैं और उसके बाद भी गुमराह किया जा रहा है इस तरह के प्रश्न के..........

अध्यक्ष : आप, अपना पूरक पूछ लीजिए।

श्री विजय कुमार सिन्हा : यह जो मूर्तियों की तस्करी हो रही है, चोरी हो रही है और कुछ लोग उसको संरक्षित कर रहे हैं तो घोसी कुंडी को जब संरक्षित करने का हमारा धरोहर है, भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है, कई वहां पर अवशेष है तो संग्रहालय की बात को अस्वीकार करना क्या माननीय मंत्री महोदय- ये सारा चित्र है, आपके माध्यम से......

अध्यक्ष : आप बैठिए न, मंत्री महोदय बता रहे हैं।

श्री शिवचन्द राम,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उसका उत्तर मैंने स्पष्ट रूप से देने का काम किया है- खुदाई जो हुई वह हमारे बिहार सरकार के अधीन नहीं है, वह भारत सरकार के अन्तर्गत आता है। इसके बाद भी माननीय सदस्य को हमने कहा है कि वहां जो मूर्तियां चोरी हुई उस मूर्ति की सूचना अभी तक विभाग के पास नहीं है। समय-समय पर एस0पी0साहब, डी0एम0साहब को हम बराबर पत्र विभाग से

देते रहे हैं कि कहीं भी अगर कोई मूर्ति उस प्रकार के पड़े हुए हैं, थाने के मलखाने में हो तो ऐसी मूर्ति की सूचना देकर संग्रहालय में रखें। माननीय सदस्य का कहना है कि संग्रहालय लखीसराय में नहीं है। हमने इनको उत्तर दिया है और उत्तर में कहा है कि मैं डी0एम0 लखीसराय को पत्र लिख चुका हूँ, 2 एकड़ जमीन का हमने मांग किया है और अतिशीघ्र हम वहां पर संग्रहालय का निर्माण करायेंगे। जो मूर्तियां जहां बची हुई है उन मूर्तियों को लेकर उस संग्रहालय में रखा जायेगा।

श्री विजय कुमार सिन्हा : महोदय, माननीय मंत्री जी कहे कि कोई चोरी की जानकारी नहीं है तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि सभी थाना से आप रिपोर्ट मंगा लें कि कितनी मूर्तियां तस्करी- करोड़ों की मूर्तियां

क्रमशः

टर्न-4/अशोक/07.03.17

श्री विजय कुमार सिन्हा : क्रमशः अभी हाल फिलहाल में सूर्यगढ़ा और लक्खीसराय थाना से, बालउत्तर में मूर्त्ति की चोरी हुई है, पेपर्स में भी निकला है, वहां से इस तरह से जवाब देकर गुमराह किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जो गये थे, जिला में संसदीय कार्य मंत्री जी भी थे ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा जी को पूरक प्रश्न पूछना चाहिए सरकार का तो स्पष्ट उत्तर हैं कि वहां बनायें सिर्फ जमीन उपलब्ध कराना हैं, जमीन इनके पास भी है, अगर ये अपनी ही जमीन दान में दे देंगे वहां पर माननीय मंत्री तुरत बनवा देंगे ।

अध्यक्षः श्रवण जी, इनके पास इतनी जमीन है यह सूचना आप तक कैसे पहुंची हैं ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : हुजूर, हम प्रभारी मंत्री हैं, सब सूचना उनका ग्रहण किये हुये पहले से।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, माननीय विजय बाबू ने चिन्ता व्यक्त की है कि काफी दुलर्भ मूर्तियां निकाली जा रही है, माननीय मंत्री जी ने सकारात्मक जवाब दिया है कि हम संग्रहालय बनायेंगे, प्रयास करेंगे । तब तक महोदय जब तक संग्रंहालय नहीं बनात हैं महेदय आये दिन अखबरों में देख रहा हूं राज्य के अन्दर मंदिरों से राम जानकी की मूर्त्ति, हनुमानजी की मूर्त्ति, शंकर भगवान की मूर्त्ति की बड़े पैमाने पर स्मगलिंग हो रही है, तस्करी हो रही है, यह चिन्ता का विषय है, हम सरकार से आग्रह करेंगे कि जब तक संग्रहालय नहीं बनता है तब तक तो वहां पर मूर्त्तिया निकाली गई हैं उसकी सरकार सुरक्षा की व्यवस्था कराये ताकि तस्करों को मौका नहीं मिले ।

अध्यक्ष : ठीक । सरकार इसको देख लेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-906(श्री विनोद कुमार सिंह)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : 1. स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार से जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कटिहार जिला के प्राणपुर प्रखंड में पत्थरवार पंचायत अंतर्गत प्रश्नगत विद्यालय हेतु महामहिम राज्यपाल के नाम से 4 एकड़ 93.5 डी0 भूमि निबंधित है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि विद्यालय द्वारा सम्बद्धता हेतु दिये गये आवेदन दिनांक 30.03.15 पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार को समिति के पत्रांक-7919 दिनांक 14.10.2015 द्वारा जांच हेतु भेजा गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय की जांच कर जांच प्रतिवेदन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मे पत्रांक-42 दिनांक-20.02.2016 के द्वारा प्राप्त है । विद्यालय द्वारा सम्बद्धता से संबंधित प्राप्त आवेदन पत्र एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सम्बद्धता विनियमावली, 2011 में निर्धारित मापदंडों के आलोक में प्रक्रियाधीन है । समीक्षोपरान्त नियमानुसार आवश्यक निर्णय लिया जायेगा । ऐसे जितने भी मामले हैं, उन्हें अगले तीन महीने में निष्पादित कर दिये जायेंगे।

श्री विनोद कुमार सिंह : महोदय, पूरक तो पूछने दिया जाय ।

अध्यक्ष : आपने पूछा ही नहीं ।

श्री विनोद कुमार सिंह : आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि 1992 में ही महामहिम गवर्नर के नाम से जमीन रजिस्ट्री की गई थी, 24-25 साल बीत जाने के बाद और वहां के कमिटी के द्वारा कई बार माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल, शिक्षा मंत्री जी को इसके लिए आवेदन दिया गया हैं ....

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री विनोद कुमार सिंह : पूरक मेरा यह है कि समय अवधि उसकी जानकारी माननीय मंत्री जी दें कि कब तक उसका एफिलियेशन ...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने तीन महीना तो बता दिया है, असल में बिना पूरक के आप संतुष्ट नहीं होते हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 907(श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला में केन्द्र प्रयोजित योजनान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास एस. एम. कॉलेज के निकट निर्मित एवं संचालित है एवं राज्य योजनान्तर्गत अति पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए जन नायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण जिला मुख्यालय में किया जा रहा है, जिसे मई, 2017 तक

पूर्ण हो जाने की सम्भावना है । वर्त्तमान में अनुमण्डल स्तर पर कोई छात्रावास निर्माण का प्रावधान नहीं है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह :अध्यक्ष महोदय, जिले में जो छात्रावास बनाये गये पिछड़ और अति पिछड़ा वर्ग के छात्राओं के लिए उसमें कितनी संख्या है, उसमें कितनी संख्या में बच्चे रहते हैं? अनुमण्डल स्तर पर चूंकि जिले में अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ वर्ग के बालिकाओं की संख्या कितनी है यह मंत्री जी सर्वे कराये होंगे तो उनको पता होगा कि कितने बच्चों के लिए वो वहां निरर्धारित किये हैं और अनुमण्डल स्तर पर सरकार इस प्रकार के छात्रावस बनाने का कोई निर्णय करेगी क्या ?

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : मैंने पहले ही कहा कि अनुमण्डल स्तर पर छात्रावास बनाने का कोई प्रावधान, अभी तक सरकार के पास कोई योजना नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार सिंह : माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि मोतिहारी में अति पिछड़ा छात्रावास और पिछड़ा छात्रावास बना हुआ है तो कब

अध्यक्ष : बना हुआ नहीं है, पूरा होने वाला है ।

श्री प्रमोद कुमार सिंह : पूरा नहीं होने वाला हैं, बना हुआ है । बना हुआ है, एक बना हुआ है और एक जन नायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास पूरा होने वाला है । तो जो बना हुआ है छात्रावास है वो पिछले दो-तीन साल बना है, लेकिन उसमें छात्र अभी तक नहीं रहे, अभी तक उसका चार्ज हैंडऔभर, टेकओभर पिछड़ा वर्ग विभाग के द्वारा नहीं हुआ तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि जो पिछड़ा छात्रावास बना हुआ है वह कब तक छात्रों के रहने लायक, उसका हैंडऔभर और टेकओभर करके चालू किया जायेगा और चालू किया जायेगा तो कब तक ? मंत्री जी इसका उत्तर दें ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, छात्रावास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और हैंडऔभर और टेकओभर की जो प्रक्रिया है,उसको मैं दिखलवा लेता हूँ और माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि दो से ढ़ाई महीने के अन्दर इसे हस्तानान्तरित करने की कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-908(डॉ शकील अहमद)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखंड के नया प्राथमिक विद्यालय रामनगर, बलौन भूमिहीन एवं भवनहीन है । विद्यालय पोषक क्षेत्र में किसी भूमि दाता से विद्यालय को भूमि प्राप्त नहीं हुई है । भूमि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक पहल की जा रही है।

कटिहार जिलान्तर्गत कदवा प्रखंड नया प्राथमिक विद्यालय,

शहाबुद्दीन मास्टर टोला, पंचगाछी विद्यालय के नाम से भूमि निबंधित है जो 8 फीट गड्ढा रहने के कारण ग्राम पंचायत राज, उनासी पंचगाछी द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत मिट्टी भराई कार्य किया जा रहा है । उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 सर्व शिक्षा अभियान के वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में राशि की मांग की गई है । राशि उपलब्ध होने के उपरांत भवन निर्माण का कार्य कराया जा सकेगा ।

डॉ शकील अहमद : नहीं, वजीरेमोहतरम, आपको वजीरे-एत्तसादियात ने इस बार 400 करोड़ रूपये ज्यादा दिये हैं, आपको इसका ज्ञान जरूर होगा । हमारे क्षेत्र में 30 ऐसे विद्यालय हैं जिनके पास जमीनें नहीं है, तो यह सिच्युएशन बहुत खराब है, और ग्डढे है और अाीी तकि नहीं भरे नहीं गये तो इससे तो काम चलेगा नहीं इसको बहुत सिरियसली, सी.ओ. से पूछा जाय कि वे जमीन का आवंटन कब करेंगे, उसकी समय सीमा क्या होगी ताकि आपको भी सही जानकारी वे दे सकें और सदन को और मुझकों सही जानकारी हो, आप सी.ओ. से बात कर लें और यह जमीन कब तक उपलब्ध होगी हैं, 30 ऐसे है , मैंने तो सिर्फ दो का ही प्रश्न पूछा है । मुझे समय सीमा बतायें ।

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न संख्या-909 ।

डॉ शकील अहमद : महोदय, मुझे वक्त बता दें सर प्लीज, दो महीने में, तीन महीने में वे गड्ढे भर दिये जायेंगे । बता दें प्लीज ।

अध्यक्ष : आपने तो प्रश्न पूछा नहीं था, आपने तो सुझाव दिया था कि सी.ओ. से बात कर लें। प्रश्न का जवाब होता है, सुझाव का जवाब क्या होगा ?

डॉ शकील अहमद : उस प्रश्न में ही निहित है, वे हमको बतायें कि वह समय क्या होगा, बच्चे दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और गड्ढे के वजह से वह नहीं बन पा रहा है या आवंटन के वजह से नहीं हो पा रहा है, उसकी जांच करा कर समय सीमा निर्धारित कर दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसको शीघ्र करा दीजियेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-909(श्री राजेन्द्र कुमार)</u>

श्री शिवचन्द्र राम,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर-1 स्वीकारात्मक ।

उत्तर-2 वस्तुस्थिति यह है कि स्टेडियम के गैलरी निर्माण में करीब 100 फीट लम्बाई में प्लास्टर, वाशिंग कार्ड गेट, ग्रील कार्य विवाद हो जाने के कारण बाकी हैं, जिसका सम्पूर्ण कार्य दो महीना के अन्दर पूरा करा लेना का आश्वासन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र, अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल-1, मोतिहारी के पत्रांक 301 दिनांक 28.02.2017 को दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार : महोदय, वहां निर्माण में कोई विवाद नहीं है, तकरीबन पांच वर्ष हो गया है और वहां लगातार आश्वासन पर आश्वासन, पूर्व में जो बना था वह टूट करके

क्षतिग्रस्त होकर खत्म हो गया और अभी भी कार्य लगभग 25 प्रतिशत बाकी है.. क्रमशः

टर्न-05/ज्योति
07-03-2017

श्री राजेन्द्र कुमार, क्रमशः और अभी भी कार्य लगभग 25 परसेंट बाकी है और यह पदाधिकारी के लापरवाही .....

अध्यक्ष : इन्होंने कहा कि 2 महीना में पूरा करेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार : लापरवाही है पदाधिकारी का और इस कार्य को बाधित करने में जो दोषी है उस पर माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से पूछना चाहेंगे कि जिसकी वजह से वह कार्य बाधित रहा उसपर कार्रवाई सुनिर्श्चित करना चाहते हैं ?

श्री शिवचन्द्र राम, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट हमने कहा है कि दो महीना का टाईम लिया गया है इसके बाद देखवा लेंगे कि दोष किसका है ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मोतिहारी जिला के चकिया और महेसी में 5-7 साल पहले ..

अध्यक्ष : वह चकिया का कैसे बतलायेंगे उनके पास सूचना ही नहीं होगी ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : चकिया गांधी मैदान और हाई स्कूल , मेहसी दोनों काम लंबित है अभी तक काम को पूरा नहीं किया गया है हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री से ..

अध्यक्ष : दोनों में एजेन्सी एक ही है क्या ?

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : अलग अलग एजेन्सी है, कौन एजेन्सी है लेकिन अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि इसको देखवा कर कार्रवाई करें ?

अध्यक्ष : ठीक है,मंत्री जी, देखवा लें ।

श्री शिवचंद्र राम , मंत्री : माननीय सदस्य लिखकर देंगे हम उसकी जॉच करवा देंगे ।

अध्यक्ष : लिखकर दे दें ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या 910</u> (श्री नितिन नवीन)

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है।

श्री नितिन नवीन : अध्यक्ष महोदय, सवाल को देखा जाय यह पूरी तरह समाज कल्याण विभाग का है स्वास्थ्य विभाग का विषय नहीं है । समाज कल्याण विभाग का है यह पूरे बेटी बचाओ अभियान और बच्चों का शिशु मृत्यु दर क्यों बढ़ रहा है बिहार में उसमें

शहरों में लड़कियों का क्यों बढ़ रहा है, यह विषय है समाज कल्याण विभाग का है, स्वास्थ्य विभाग का नहीं है ।

अध्यक्ष : ठीक है, अभी तो यह स्वास्थ्य विभाग को गया है ।

तारांकित प्रश्नसंख्या 911(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, 1- उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद ने पात्र संख्या-152, दिनॉक -23-02-17 एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), औरंगाबाद ने नवीनगर विधान सभा क्षेत्र के प्रश्नगत प्रखंड के कुल-17 विद्यालयों में से 4 विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन हो चुका है शेष 13 विद्यालयों में निदेश दिए जाने के पश्चात भी प्रबंध समिति का गठन नहीं होने के कारण विद्यालय प्रधान के विरुद्ध आरोप गठित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया है ।

13 विद्यालयों में से 8 विद्यालयों में नियोजित शिक्षक विद्यालय प्रधान है जिनके विरुद्ध विभागीय आदेश संख्या -502 दिनॉक 6-03-2017 के द्वारा उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, औरंगाबाद को अनुशासनिक कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया है । शेष 5 विद्यालयों के प्रधान से विभागीय पत्र संख्या-503 दिनॉक 06-03-2017 के द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया है । स्पष्टीकरण का उत्तर प्राप्त होते ही नियमानुसार विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जिन विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन नहीं हुआ और उसके विकास कार्य अवरुद्ध हुए उनपर कौन सा नियम कार्रवाई करने का है, वह कौन सा प्रावधान है और उसके अंतर्गत कौन सा दंड निर्धारित किया जाता है ?

अध्यक्ष : मंत्री जी ने आपको बताया कि कार्रवाई की जा रही है । आप केवल मंत्री जी से ससमय कार्रवाई करने के लिए कह दीजिये ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह पूरा सदन जानना चाहता है कि प्रबंध समिति गठन नहीं करने वाले पर कौन सी कार्रवाई की जाती है ?

(व्यवधान)

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जिस विद्यालय में प्रबंध समिति गठन किए वगैर विकास कार्य कर दिए गए हैं वैसे प्रधानध्यापकों पर माननीय मंत्री जी क्या कार्रवाई करना चाहते हैं ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : नहीं, नहीं । माननीय विधायकों के बिना कोई प्रबंध समिति का गठन जहॉ नहीं किया गया है और जहॉ पर विद्यालय के विकास कार्य किए गए है बिना अनुमति के उनपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी । वैसे प्रधानाध्यापक जिन्होंने बिना विधायक को विश्वास में लिए बिना कमिटी के निर्माण किए हुए ऐसे

प्रधानाध्यापक को निलंबित किया जायेगा, यह जो सदन का जो प्रावधान है, सदन का जो नियम है उसके अनुसार जो प्रधानाध्यापक काम नहीं कर रहे हैं वैसे कठोर से कठोर कदम उनके ऊपर सरकार उठायेगी।

श्री विनोद प्रसाद यादव: महोदय, इसकी समय सीमा क्या होगी आखिर माननीय मंत्री जी कितने दिनों में काम करायेंगे । समय सीमा क्या होगी ?

अध्यक्ष : अब अगर ज्यादा पूरक पूछियेगा तो इसकी कार्रवाई में व्यवधान होगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या 912 (श्री सिद्धार्थ)

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम के पत्रांक 1745, 16/17 दिनॉक 02-03-17 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत नौबतपुर प्रखंड में प्रति लाभार्थी कन्या के नाम से दो हजार मात्र की एकमुश्त राशि अनुदान के रुप में म्यूचुअल फंड में निवेश कर यू0टी0आई0 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2011-12 में 1680 एवं 2012-13 में 1511 बौण्ड निर्गत किया गया है । वर्तमान में इस योजना के तहत बी.पी.एल. परिवार की 0 से 3 वर्ष की कन्या के नाम से दो हजार रुपये की राशि प्रति कन्या एक मुश्त अनुदान के रुप में आई.डी.बी.आई. बैंक एवं यूको बैंक में सावधि जमा फिक्सड डिपोजीट स्कीम में कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलबध कराया जा रहा है ।

श्री सिद्धार्थ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह सूचित करना चाहूँगा कि इस योजना के लाभार्थियों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इनका लाभ नहीं मिला है मैं इनकी सूची बनाकर इनको प्रस्तुत कर दूँगा और मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि जो भी ऐसे लाभार्थी वंचित रह गए हैं उनको निश्चित रुप से भुगतान किया जाय ।

अध्यक्ष : देखवा लीजिये ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, मंत्री : ठीक है, निश्चित रुप से ।

तारांकित प्रश्न संख्या 913 (डा0 रामानुज प्रसाद)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, बिहार, पटना द्वारा शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिए प्राप्त अधियाचना के अन्तर्गत वर्ग-1 से 8 तक की पुस्तकें का मुद्रण बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कारपोरेशन लि0 द्वारा किया जाता है । तत्पश्चात् राज्य के सभी प्रखंडों में अधियाचना के अनुरुप परिवहन कर पुस्तकों की आपूर्ति की जाती है ।

निगम द्वारा अधियाचना के आलोक में वर्ग -1 से 8 तक राज्य के सभी जिला के प्रखंडों में 90 प्रतिशत पुस्तकें आपूर्ति कर दी गयी है। आपूर्ति

किए गए पाठ्य पुस्तकों के सेट की कुल संख्या- 1,79,24,115 है । यह संख्या छात्र-छात्राओं के औसत उपस्थिति के सापेक्ष पर्याप्त है । गौरतलब है कि भारत सरकार के उपक्रम एच.पी.सी.एल. से ससमय पर्याप्त कागज उपलब्ध नहीं कराने के कारण पाठ्य पुस्तकों के छपाई में एवं वितरण में विलम्ब हुआ ।

प्रखंड स्तर से उक्त पाठ्य पुस्तकों को विद्यालय में उपलब्ध कराया गया है जहॉ छात्र-छात्राओं के बीच इसे नि:शुल्क वितरित कराया गया है । पाठ्य-पुस्तकों के अभाव या कमी से पठन-पाठन में किसी प्रकार के व्यवधान होने की सूचना प्राप्त नहीं है ।

डा0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जो जवाब दिए हैं इनको बिल्कुल गलत जवाब बनाकर भेजा गया है अब केन्द्र सरकार दोषी है या राज्य सरकार दोषी है या राज्य सरकार के कर्मचारी दोषी है उसपर मंत्री जी इसकी जॉच कराके कार्रवाई करेंगें क्या? मैं इनके जवाब को चैलेंज करते हैं कि नहीं बंटे है पुस्तक जानकारी के आधार पर मैंने यह सवाल लाया है ?

अध्यक्ष : पूछ रहे हैं कि जॉच कराकर कार्रवाई करेंगे ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : हमने कहा कि ये टेक्स्ट बुक को पेपर की सप्लाई एच.पी.सी.एल., ट्रेडिशनली वह भारत सरकार के उपक्रम के माध्यम से किया जाता है यह प्रश्न पिछले विधान साभा सत्र में भी आया था इसपर हमने जवाब दिया था कि एच.पी.सी.एल. की कैपेसिटी जो है वह पहले की तरह अब नही रही है है वह बंद के कगार पर है इसलिए सरकार ने नया निर्णय लिया है इस वित्तीय वर्ष से कि बिहार के टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन द्वारा पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति की जाती है । पाठ्य पुस्तकों के लिए कागज का क्रय हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लि0 से किया जाता रहा है । हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लि. के द्वारा पर्याप्त संख्या में कागज की समसय आपूर्ति नहीं करने के कारण पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण में विलंब होता है और इसका परिणाम छात्र छात्राओं के बीच पाठ्य पुस्तकों के वितरण में विलंब होता है इस पृष्ठभूमि में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय स्तर पर खुली निविदा आमंत्रित कर टेक्स्ट बुक के आवरण एवं कागज खरीद ,की जाय ताकि शैक्षणिक सत्र अप्रैल से पहले पुस्तक सभी छात्र छात्राओं को प्राप्त हो सके ।

श्री नंद किशाोर यादव: महोदय, यह प्रश्न पहले भी आया था । मंत्री महोदय को लगा कि जब हम हाथ उठा रहे हैं तो उसका उत्तर देना उनको आवश्यक था । महोदय, मंत्री महोदय ने बड़े बड़े साफ साफ जवाब देकर बचने की कोशिश की । इन्होंने भारत सरकार के उपक्रम का जिक्र कर दिया । भारत सरकार के उपक्रम से कागज लेना कोई बाध्यता है क्या आपकी , पुस्तक निगम की बाध्यता है क्या ? कोई बाध्यता नहीं है। यह तो पुस्तक निगम पर निर्भर करता है कि वह कैसे कागज लेता है महोदय, मैं

जानना चाहता हूँ कि जब पिछले सदन में इस प्रश्न- जब मेरे द्वारा किए गए प्रश्न के जवाब मे माननीय मंत्री महोदय ने जवाब में इस बात को कहा था कि हमारी बाध्यता नहीं है और हम कागज की उपलब्धता के लिए दूसरा उपाय करेंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री महोदय ने इस सदन के अंदर आश्वासन दिया था कि कागज की कमी को दूर करने के लिए हम कोई सक्षम उपाय करेंगे अबतक उपाय क्यों नहीं किए गए, अब टेंडर किया जायेगा, यह निर्णय लेने का क्या औचित्य है ?

टर्न-06/7.3.2017/बिपिन

श्री अशोक चौधरी,मंत्रीः महोदय, इतने सीनियर लीडर हैं...

श्री नन्द किशोर यादवः अध्यक्ष महोदय, सीनियर से क्या मतलब है ? आपने जवाब दिया, आप जवाब दीजिए, क्यों नहीं किया आपने ?

श्री अशोक चौधरी,मंत्रीः जवाब दे रहे हैं, अरे सर, सुना जाएगा ?

श्री नन्द किशोर यादवः बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हैं ? नेतागिरी केवल करना चाहते हैं ?

श्री अशोक चौधरी,मंत्रीः आप नेतागिरी कर रहे हैं कि हम नेतागिरी कर रहे हैं ? आप पूरक पूछिये, हम जवाब दे रहे हैं न । आपका हम जवाब दे रहे हैं । आप ऐसे डिमॉरलाइज नहीं कर सकते हैं सरकार को । आप सीनियर मेम्बर हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप कहिएगा कि आप नेतागिरी कर रहे हैं । आप यह शब्द वापस लीजिए ।

(व्यवधान)

हम आपके पूरक का जवाब देंगे । बैठिये ।

(व्यवधान)

श्री अशोक चौधरी,मंत्रीः आप बैठिये । हम आपके पूरक का जवाब देंगे, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं ? आप ऐसी बात कहते हैं कि आप नेतागिरी कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, सरकार को भी प्रोटेक्ट करना है । लीडर हैं आप। ऐसी बात कर रहे हैं कि आप नेतागिरी कर रहे हैं !

श्री नन्द किशोर यादवः महोदय, लूट मचा हुआ है शिक्षा विभाग में । महोदय, पूरा शिक्षा विभाग बिहार को बदनाम करने का काम किया है ।

अध्यक्ष : ठीक है, जवाब होता है, आप बैठिये। जवाब दीजिए माननीय मंत्री जी।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी...

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः महोदय, जिस तरह का आचरण-व्यवहार कर रहे हैं महोदय ...

अध्यक्ष : जवाब दे रहे हैं ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलःमहोदय, नन्द किशोर यादव जी हमारे पार्टी के वरीय नेता हैं । सिनियर रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, महोदय । सवाल कर रहे हैं ...

अध्यक्ष : मंत्री जी, आप फिर जवाब दीजिए ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः यह बहुत दुःखद है महोदय ।

श्री अशोक चौधरी,मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सरकार के पक्ष को भी प्रोटेक्ट करना है । ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें जिससे कि सरकार, इस तरह के शब्द का प्रयोग करेंगे माननीय सदस्य कि हम नेतागिरी कर रहे हैं ? आप पूरक पूछिये, हम पूरक का जवाब देंगे । अगर आप सटिस्फायड नहीं हैं तो आप जांच कराइएगा । हम जवाब दे रहे हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय मंत्री जी, आप पूरक का जवाब दीजिए ।

श्री अशोक चौधरी,मंत्रीः महोदय, एच.पी.सी.एल. भारत सरकार का उपक्रम है । ट्रैडिशनली बिहार सरकार एच.पी.सी.एल. से कागज की सप्लाई लेता रहा है । एच.पी.सी.एल. बंद के कगार पर है । पिछले साल के वित्तीय वर्ष के लिए एच.पी.सी.एल. को टेंडर बिहार टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन ने दिया । हमने पिछले वित्तीय वर्ष में इस सदन में कहा कि हम इस ट्रैडिशन को चेंज कर रहे हैं और मार्च-अप्रील में पुस्तक का वितरण हो, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और इसीलिए इस बार हमलोगों ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय स्तर पर खुली निविदा आमंत्रित कर टेक्स्ट बुक एवं आवरण कागज खरीद की जाएगी ताकि शैक्षणिक सत्र अप्रैल शुरू होने से पहले पुस्तकें राज्य के सभी छात्र-छात्राओं को उपलब्ध हो जाए ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

(व्यवधान)

अब हो तो गया । तारांकित प्रश्न सं0- 914

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः महोदय, यह बिहार के बच्चों के भविष्य का सवाल है । महोदय, शिक्षा विभाग में महोदय, पिछले बार, महोदय 400करोड़ का घोटाला हुआ है । पुस्तक घोटाला बिहार में हुआ है महोदय । सरकार पुस्तक घोटाला को रोक नहीं पाई है महोदय, उसी का परिणाम है महोदय...

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य राज किशोर सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0: 914(श्री राज किशोर सिंह)

श्री अशोक चौधरी,मंत्रीः महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 171 दिनांक 23.2.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि गौरोल प्रखंड के राजकीयकृत राजगृही उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र/छात्राओं का पठन-पाठन तत्काल बगल के मध्य विद्यालय प्रेमराज में उपलब्ध 6 कमरों एवं विद्यालय के 03 कमरों अर्थात् कुल 09 कमरे में अध्यापन संचालित किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त 06 कमरा निर्माणधीन है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2010-11 में 03 अतिरिक्त वर्ग कक्ष, 01कम्प्यूटर कक्ष एवं 01 पुस्तकालय कक्ष की स्वीकृति प्राप्त है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान राशि प्राप्त होने के उपरांत निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा ।

वर्तमान में विद्यालय में 9 शिक्षक कार्यरत हैं । साथ ही पंचम चरण के तहत प्रश्नगत् विद्यालय में स्वीकृत पद के विरूद्ध उपलब्ध रिक्ति के अंतर्गत शिक्षकों का नियोजन सुनिश्चित किया जायेगा ।

श्री राज किशोर सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि कब तक हाई स्कूल का बच्चा मिड्ल स्कूल में पढ़ेगा और उसके कमरा में पढ़ेगा ? निर्माणाधीन पिछले 3-4 वर्षों से है । आखिर बनेगा कब तक ?

दूसरा, सात शिक्षक हैं या 9 शिक्षक हैं, 1600 बच्चा हो और 9 शिक्षक हो लेकिन पूर्णरूप से तो 3 ही कमरा बना है । हम दूसरे स्कूल में पढ़ाते हैं । सोचना चाहिए सरकार को और हमारे मंत्री तो काबिल मंत्री हैं । हम समझते हैं जरूर सोचेंगे इस पर । हमारे काबिल मंत्री हैं । इस पर गंभीरता से सोचेंगे और कोई समस्या का समाधान करेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0: 915(श्री अमित कुमार)

श्री चन्द्रिका राय,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, निगम के बेड़े में वातानुकूलित डिलक्स बस उपलब्ध नहीं है। अत: विषयांकित मार्ग पर निगम के बसों का परिचालन करना संभव नहीं है ।

श्री अमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, कोई भी बस वहां नहीं है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, अब डीलक्स ए.सी. से नीचे आ गए हैं, कोई बस चाह रहे हैं ।

श्री चन्द्रिका राय, मंत्री: विचार किया जाएगा ।

तारांकित प्रश्न सं0: 916(श्री वशिष्ठ सिंह)

श्री अशोक चौधरी,मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति है कि प्रश्नाधीन विद्यालय के अतिरिक्त अनेकों राजकीयकृत परियोजना विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं परन्तु विद्यालय के दैनिक एवं प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन हेतु विद्यालय विशेष में वरीयता के आधार पर प्रधानाध्यापक के नियमित पदस्थापन तक प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा शैक्षणिक एवं

प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है । प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों को प्रोन्नति से भरे जाने हेतु राज्यस्तरीय वरीयता सूची का अंतिम प्रकाशन कार्यालय पत्रांक-438 दिनांक 23.02.2017 द्वारा किया जा चुका है । वरीयता सूची से प्रोन्नति देते हुए प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा ।

श्री वशिष्ठ सिंह: महोदय, विद्यालय में चूंकि एक बार हम विजिट में गए थे तो वहां के जो कार्यकारी प्रधानाध्यापक हैं, इतना ही, क्या हम कहें सदन में, बिल्कुल ही, बिल्कुल ही तनिक से भी कहीं से नहीं दिखा कि ये प्रधानाध्यापक के पद पर रहने लायक हैं । मैंने माननीय मंत्रीजी से शिकायत किया था, मैंने सदन में इस बात को रखा था, डी.इ.ओ. साहब से भी मैंने शिकायत किया था, डी.इ.ओ. साहब को भी मेरे सामने मंत्री महोदय ने शिकायत किया लेकिन कोई आज तक कार्रवाई उस प्रधानाध्यापक पर नहीं हुआ । मैंने कहा महोदय कि अगर आप उसको हटाने में अक्षम हैं तो वहां प्रभारी को हटा कर वहां कंटिन्यू प्रधानाध्यापक दिया जाए ताकि उस विद्यालय का शैक्षणिक कार्यक्रम ठीक-ठाक से हो, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ ।

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिये न ।

श्री वशिष्ठ सिंह : जी, मैं कह रहा हूं कि शीघ्र प्रधानाध्यापक दिया जाए दोनों विद्यालय में ।

महोदय, मेरे यहां उबुद्धि उच्च विद्यालय है, वहां उबुद्धि उच्च विद्यालय में 10प्लस टू है और मात्र एक शिक्षक है महोदय । हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वहां भी शिक्षक देने का काम पूरा किया जाए ।

अध्यक्ष : ठीक है । प्रश्न संख्या 917 श्री गिरिधारी यादव । श्री दिनेश चन्द्र जी पूछेंगे ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : वह हो गया । जल्दी पूछिये । आप अपना पूरक पूछियेगा ।

श्री ललन पासवान: महोदय, मैं जानना चाहता हूं महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कर्मचारियों को प्रोन्नति करके हम पोस्टिंग करेंगे । यह कब तक ? इसका समय-सीमा निर्धारित करें कि कब तक सभी विद्यालयों में शिक्षक प्राचार्य के अभाव में सब जगह शिक्षा की स्थिति खराब है, इसलिए माननीय मंत्री जी, प्रधानाचार्य को प्रोन्नत करके कब तक स्थायी इनका नियुक्ति करेंगे ? समय-सीमा बताएं ।

श्री अशोक चौधरी,मंत्री: हमने कहा अध्यक्ष महोदय कि प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों को प्रोन्नति से भरे जाने हेतु राज्यस्तरीय वरीयता सूची का अंतिम प्रकाशन कार्यालय पत्रांक 438 दिनांक 23.2.2017 द्वारा किया जा चुका है और वरीयता सूची से प्रोन्नति हेतु प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों को भरा जाएगा । फिफ्टी परसेंट प्रमोशन से भरना है । जल्द-से-जल्द भरा जाएगा । सरकार के प्रायरिटी में है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

टर्न:07/कृष्ण/07.03.2017

तारांकित प्रश्न संख्या : 917(श्री गिरिधारी यादव)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री गिरिधारी यादव । मा0स0श्री दिनेश चन्द्र यादव जी प्रश्न पूछेंगे ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : पूछता हूं ।

श्री विजय प्रकाश,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड 1 : उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड 2 : उत्तर अस्वीकारात्मक है । जमुई जिलान्तर्गत सिमुलतल्ला के आस-पास के दो अनुज्ञप्तिधारी वैध आरा मिल है । दो अवैध आरा मिलों के संचालन की सूचना थी, जिन्हें छापामारी कर जप्त कर लिया गया है । बेतहाशा जंगल कटाई की सूचना अस्वीकारात्मक है ।

खंड 3 : अवैध रूप से संचालित दो आरा मिलों को जप्त कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध केस दर्ज किया गया है ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : महोदय, खंड-1 में माननीय मंत्री जी ने कहा कि उत्तर स्वीकारात्मक है, जिसमें उच्च न्यायालय ने क्षेत्रफल और आबादी के अनुरूप तय किया है कि ...

अध्यक्ष : आप माईक पर बोलिये ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव : हाई कोर्ट ने तय किया कि कितने क्षेत्रफल और कितनी आबादी पर एक आरा मिल होगा । माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि यह बात सही है । लेकिन खंड-2 में माननीय मंत्री जी जवाब दिये हैं कि मात्र दो आरा मिल है लेकिन माननीय सदस्य श्री गिरिधारी जी जो वहीं के हैं, उन्होंने प्रश्न के माध्यम से सूचना दी है कि आधा दर्जन वहां पर आरा मिल काम कर रहा है और वह सब जंगल के बगल में है तो इस तरह से अवैध आरा मिलों को छूट मिलेगी तो सब गाछ ही खत्म हो जायेगा । इसलिए माननीय मंत्री फिर से इसकी जांच गंभीरता से किसी वरीय पदाधिकारी से करायेंगे कि वहां कितने आरा मिल हैं और जो गलत होंगे उस पर कार्रवाई करेंगे क्या ?

श्री विजय प्रकाश,मंत्री : इसकी सूचना हम वरीय पदाधिकारी को देंगे और हम इसकी सूचना लेंगे कि वहां की क्या स्थिति है ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

माननीय सदस्यगण,आज दिनांक 07 मार्च,2017 के लिये निम्न माननीय सदस्यों से कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें प्राप्त हुई है :-

श्री संजय सरावगी, श्री विजय कुमार खेमका, श्री विद्या सागर केशरी, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव, श्री अरूण कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार सिन्हा ।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये वार्षिक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांग पर वाद-विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है। अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 172(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री प्रेम कुमार,नेता,विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हमारे एनडीए के माननीय विधायकों ने आज कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है ..

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्यों ने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दिये हैं उनको तो अमान्य कर दिय गया है । अमान्य होने के बाद माननीय प्रतिपक्ष के नेता उस पर डिबेट क्यों कर रहे हैं ? क्या नियम है, क्या नियमावली है ? इसी तरह से सदन को चलाने की मंशा है ? जब आसन ने उनको अमान्य कर दिया तो क्या उस पर डिबेट होगा ?

श्री प्रेम कुमार,नेता,विरोधी दल : महोदय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, वित्त रहित शिक्षक जो हैं, शिक्षकेत्तर कर्मचारी हैं, उनको समान कार्य समान वेतन देने के संबंध में है । इसको लागू करने के लिये कार्य-स्थगन का प्रस्ताव लाया गया महोदय । साथ ही, महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब प्रश्नोत्तरकाल शुरू हो रहा था तो आपने कहा था कि आप जीरो आवर में उठाईयेगा । महोदय, हम ने इस विषय को लाया है । महोदय, रात भर क्या हालत रहा गर्दनीबाग धरना स्थल पर । महोदय, मछुआरा समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं, निषाद विकास मंच है, उसके अध्यक्ष मुकेश सहनी हैं, 9 सूत्री मांगों को लेकर वे आंदोलन कर रहे हैं । महोदय, हमारा आग्रह होगा कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करें । हम चाहेंगे कि सरकार इस पर वक्तव्य दें । समान कार्य समान वेतन के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

<u>शून्यकाल</u>

श्री अमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी रीगा प्रखंड अन्तर्गत बिहार महादलित विकास मिशन के तहत प्राथमिक विद्यालय मुसहरटोला के टोला सेवक के पद पर पुण्यदेव सदा की मृत्यु हो गयी, परन्तु आजतक उनकी विधवा इन्दु देवी को प्रावधानानुसार कोई सरकारी लाभ नहीं मिला, प्रभावित महादलित परिवार को शीघ्र लाभ का भुगतान कराया जाय ।

(इस अवसर पर भाजपा के कुछ माननीय सदस्यगण वेल में आ कर बोलने लगे)

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी स्कल्पचर, मधुबनी पेंटिंग, सीकी पेंटिंग, दलित पेंटिंग के कलाकारों से भरा है परन्तु उनके लिये ट्रेनिंग सेंटर नहीं रहने, नियमित अंतराल पर प्रदर्शनी आयोजित नहीं होने के कारण उनकी प्रतिभा देश-विदेश तक नहीं पहुंच पा रही है ।

मधुबनी में ट्रेनिंग सेंटर तथा प्रत्येक वर्ष प्रदर्शनी हो ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय,कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखंड के ढट्ढा गोव के धूम टोला की सड़क अभी भी कच्ची है, जिससे 500 की आबादी वाले इस टोले की जनता का मुख्य सड़क पथ निर्माण विभाग की सड़क एस0एच0 98 से संपर्क टूट चुका है । मैं इस सड़क की पक्कीकरण की मांग करता हूं ।

श्री मो0 नेमातुल्लाह : अध्यक्ष महोदय,गोपालगंज जिलान्तर्गत मांझा प्रखंड के एन0एच0 28 से ग्राम सिक्कमी अजीज अखतर मास्टर के घर होते हुये दुलदुलिया तक जाने वाली सड़क काफी खराब हालत में है जिसमें पैदल चलना भी मुश्किल है ।

अत: जनहित एवं राज्यहित में उक्त सड़क का निर्माण सरकार शीघ्र करायें।

श्री शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय,पूर्वी चम्पारण जिला के बनकटवा प्रखंड अन्तर्गत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का पद विगत एक वर्ष से रिक्त है । फलस्वरूप प्रखंड में विकास कार्य बाधित हो रहा है ।

अत: सरकार जनहित में शीघ्र उक्त प्रखंड मं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को पदस्थापित करें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग प्लेकार्ड क्यों ले कर आये हैं ? माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र जी, इसको नीचे रखिये ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय,रोहतास जिलान्तर्गत नौहट्टा प्रखंड के चुनहट्टा एवं बौलिया के बीच महादेव खोह नाला में चेक डैम नहीं होने से 1000 एकड़ जमीन किसानों का बंजर रह जाता है ।

सरकार से मांग करते हैं कि उक्त नाला पर चेक डैम निर्माण करावें ।

श्री श्रवण कुमार ,मंत्री : अध्यक्ष महोदय,नेता, प्रतिपक्ष खड़े हैं, बार-बार आसन से कहा जा रहा है बैठने के लिये और सदन को औौर्डर में लेने के लिये कहा जा रहा है, यह एनडीए का पार्ट है महोदय । माननीय सदस्य ललन पासवान शून्यकाल पढ रहे हैं, इनको तो खुद विचार करना चाहिए, एनडीए में भी फूट हो रहा है । एनडीए के मेम्बर भी इनकी बात को मानने के लिये तैयार नहीं हैं । चूंकि ये अपनी बात सदन में रखना चाहते हैं और एनडीए का जो पार्ट है, उन मेम्बरों को सेव नहीं करना चाहते हैं तो इनसे सबक लेना चाहिये, एनडीए में दरार पैदा हो रहा है, माननीय सदस्य ललन पासवान जी अभी शून्यकाल पढ़े हैं ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत आमस प्रखंड के अनुग्रह नारायण सहदेव प्लस टू उच्च विद्यालय, सुग्गी में वर्ग कक्ष की कमी रहने के कारण छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन में काफी कठिनाई होती है ।

अत: जनहित में अविलंब वर्ग कक्ष का निर्माण की मांग सरकार से करता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

श्री बेबी कुमारी : अध्यक्ष महोदय,मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बोचहा प्रखंडान्तर्गत मंझौल पंचायत, भुसाही को वृद्धावस्था पेंशनभोगी दिलीप मांझी को 10 महीने से पेंशन नहीं मिल और इलाज के अभाव में मर गये । कबीर अंत्येष्टि का पैसा नहीं मिलने के कारण शव को गाड़ दिया गया ।

अविलंब कार्रवाई की मांग करती हूं ।

टर्न-8/राजेश/7.3.17

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, नालंदा जिलान्तर्गत चण्डी प्रखंड के अरौत प्रचायत के मध्य में स्थित विरनावॉ ग्राम में पावर सब स्टेशन लगाने से आस-पास के 50 गॉव के लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में 10 किलोमीटर दूर से बिजली आने के कारण समयानुसार विद्युत आपूर्ति नहीं होती है । अत: पावर सब स्टेशन बनाने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार सिंह ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री विद्यासागर केशरी ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री मिथिलेश तिवारी ।

श्री मिथिलेश तिवारी: महोदय, गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट प्रखंड के कालामटिहनिया में गंडक नदी कटाव निरोध हेतु पायलट चैनल निर्माण प्रारंभ करने की मांग को लेकर विगत 19 दिनों से दियारावासी जल सत्याग्रहरत है । अब आंदोलनकारियों के पैर भी सड़ रहे हैं, सरकार अविलंब आंदोलन वापस कराने हेतु पायलट चैनल का निर्माण प्रारंभ करें।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री यदुवंश कुमार यादव ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद ।

श्री सुदामा प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के पीरो प्रखंड के हसन बाजार से तेतरडीह चिमनी होते हुए कटरिया तक आवागमन की समुचित व्यवस्था नहीं होने से आम जन को खासकर बरसात में काफी परेशानी होती है, कच्ची सड़क ही आवागमन का साधन है । अत: आमजन के हित में इस सड़क के पक्कीकरण की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम ।

श्री सत्यदेव राम: अध्यक्ष महोदय, सिवान जिलान्तर्गत प्रखंड दरौली, ग्राम दरौली में नाग मठिया मंदिर के बगल में खाता नम्बर 312, खेसरा नम्बर-1258 गैर मजरुआ जमीन लगभग सात बिगहा है । फिर भी सामुदायिक भवन नहीं बनता है ।

मैं सरकार से उक्त जमीन में सामुदायिक भवन बनाने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा ।

(सूचना नहीं पढ़ी गयी)

अध्यक्ष: अब शून्यकाल समाप्त हुआ । ध्यानाकर्षण-सूचनाएं ली जायेंगी ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री श्याम रजक, अशोक कुमार सिंह एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (समाज कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री श्याम रजक जी की सूचना पढ़ी हुई है । माननीया मंत्री, समाज कल्याण विभाग ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय सरकार नेत्रहीन दिव्यांग शिक्षा के प्रति संवेदनशील है । तत्काल राज्य में तीन सरकारी नेत्रहीन विद्यालय है यथा-(1) राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय, कदमकुआँ, पटना जहाँ कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है । (2) राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय, दरभंगा जहाँ कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है तथा (3) राजकीय नेत्रहीन मध्य विद्यालय, भागलपुर जहाँ कक्षा 08 तक की पढ़ाई होती है ।

नेत्रहीन विद्यालय में कुल मिलाकर 14 रिक्तियाँ है । जिसकी नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया था । जिस पर माननीय उच्च न्यायालय में C.W.J.C NO-12513/2014- सूरज कुमार बनाम अन्य के मामला में दायर याचिका के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में मामला विचाराधीन रहने के कारण चयन की प्रक्रिया स्थगित है । राज्य में अभी तक नेत्रहीनों के लिए +2 स्तर के विद्यालय अलग से नहीं है ।

अन्तर्ज्योति बालिका विद्यालय, कुम्हरार, पटना एक गैर सरकारी संस्था बिहार नेत्रहीन परिषद्, कुम्हरार, पटना द्वारा संचालित विद्यालय है । उक्त विद्यालय के अनुदान की वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2007-08, 2008-09, 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दीन दयाल पुनर्वास योजना के तहत अनुदान हेतु अन्तर्ज्योति बालिका विद्यालय से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए है। उक्त प्रस्तावों को राज्य सरकार की अनुशंसा के साथ केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को अनुदान की स्वीकृति हेतु भेजा गया । वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 का प्रस्ताव संस्था से अप्राप्त रहने के कारण केन्द्र सरकार को अनुदान स्वीकृति हेतु अनुशंसा नहीं भेजा जा सका ।

वर्ष 2014-15 से मंत्रालय द्वारा योजना का प्रस्ताव आवेदन को ऑन-लाईन पद्धति से देने का प्रावधान कर दिया गया । उक्त संस्था का प्रस्ताव वर्ष 2014-15 में ऑन-लाईन अप्राप्त रहा । वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में संस्था के ऑन-लाईन प्रस्ताव का विभागीय स्क्रीनिंग कमिटि की बैठक की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई अनुदान स्वीकृति का प्रावधान नहीं है । दीन दयाल पुर्नवास योजना के तहत अनुदान की स्वीकृति की शक्ति केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में निहित है ।

नेत्रहीन दिव्यांग जिनका 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता है, को उनकी मांग पर राइटर उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जिसका अनुपालन केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये निदेशानुसार पालन किया जायेगा ।

राज्य में भी नेत्रहीन दिव्यांग बालिकाओं के लिए विद्यालय तथा +2 स्तर तक के नेत्रहीन विद्यालय तत्काल नहीं है । ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है जिसके प्रति सरकार संवेदनशील तथा सकारात्मक है ।

श्री श्याम रजक:- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम बहुत संवेदनशील है और मैं मानता भी हूँ कि यह सरकार संवेदनशील है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संकल्प है कि हम नारी सशक्तिकरण करेंगे लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक जो नेत्रहीन दिव्यांग बच्चियॉं हैं, उनके लिए कोई भी आवासीय विद्यालय नहीं हैं और +2 का एक भी स्कूल नहीं है, जिसको माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है, तो हम जानना चाहते

हैं कि कब तक आवासीय विद्यालय बच्चियों के लिए और +2 का एक भी विद्यालय नहीं है, तो क्या दिव्यांग बच्चियॉं सिर्फ गाना बजा करके और रेलवे में सिर्फ भिक्छुक बनकर रहेंगे, अगर ऐसी मंशा नहीं है तो कब तक +2 स्कूल खोलने की मंशा सरकार रखना चाहती है ? दूसरी बात इन्होंने कहा है राइटर का, तो राइटर ये 100 प्रतिशत नेत्रहीनों को देते हैं, जबकि भारत सरकार का सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का पत्रांक संख्या-एफ-16110/2003 है कि 40 प्रतिशत जहॉं है, उनको भी राइटर देना है लेकिन राइटर नहीं देते हैं और अगर देते भी हैं, तो अति जुनियर को देते हैं, जबकि ग्रेड-1 क्लास का राइटर रहना चाहिए लेकिन नहीं देते हैं, जिसके कारण बच्चियॉं ठीक से परीक्षा नहीं दे पाती है और वे अनुत्तीर्ण हो जाती हैं, तो सरकार इस बारे में क्या कहना चाहती है ?

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, मंत्री: महोदय, ग्रेड-1 क्लास का राइटर ही उपलब्ध कराया जायेगा, उनके मांग के आधार पर । जहॉं तक माननीय सदस्य की चिंता है +2 के लिए तो +2 के लिए विभाग विचार करेगी ।

श्री श्याम रजक: इन्होंने कहा है कि कुम्हरार को जो अन्तर्ज्योति परिषद् के द्वारा चलता है अनुदान के आधार पर, वहॉं 2008 के बाद अनुदान नहीं मिला है और जो नेत्रहीन बच्चे हैं, वे चंदा करके उस स्कूल को चला रहे हैं । इसलिए मेरा आग्रह है कि तत्काल, ठीक है कि भारत सरकार क्या देगी, नहीं देगी, लेकिन यह राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है, उस स्कूल को चलाना, तो क्या अनुदान देने के लिए निर्णय लेने का काम करेगी ?

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, मंत्री: सर, अनुदान जो है वह भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दीन दयाल पुर्नवास योजना के तहत ही यह अनुदान मिलती है, राज्य सरकार तो अभी अनुदान नहीं दे रही है, भले ही माननीय सदस्य की चिंता है, तो बिहार सरकार उसपर विचार करेगी ।

श्री विनोद प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, हमारा भी इसमें हस्ताक्षर है, हम भी पूछना चाहते हैं ।

अध्यक्ष: पूछिये ।

श्री विनोद प्रसाद यादव: महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूँ कि मात्र तीन ही विद्यालय हैं तो और जो बड़े जिले हैं राज्य में, तो उन जिलों में भी विद्यालय खोलने का सरकार का विचार है ?

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, मंत्री: महोदय, सरकार इसपर विचार करेगी ।

अध्यक्ष:- ठीक है ।

माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार सिंह, आप अपनी ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़ें ।

(ध्यानाकर्षण सूचना नहीं पढ़ी गयी)

टर्न-9/सत्येन्द्र/7-3-17

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप लोग तो सब मिलकर तय किये थे कि प्ले कार्ड नहीं लायेंगे, आज आप अकेले ऑड मैन क्यों बने हुए हैं ?

(व्यवधान)

वह लाना मना है, आप लेकर नहीं आईए ।

(व्यवधान)

अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न-10/मधुप/07.3.2017

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : जल संसाधन विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा ।

इसके लिये 3 घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिये भी समय दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	- 59 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	- 52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	- 39 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	- 20 मिनट
सी0पी0आई0 (एम0एल)	- 02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	- 02 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	- 02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	- 01 मिनट
निर्दलीय	- 03 मिनट
कुल	-180 मिनट

प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग, अपनी माँग प्रस्तुत करें ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''जल संसाधन विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 38,14,06,61,000/- (अड़तीस अरब चौदह करोड़ छः लाख एकसठ हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस माँग पर माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा, श्री संजय सरावगी, श्री तारकिशोर प्रसाद, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री मिथिलेश तिवारी एवं श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह से कटौती-प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जो व्यापक हैं । इसपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा अपना कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''इस शीर्षक की मांग 10/- रूपये से घटायी जाय, राज्य सरकार की जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श के लिये ।''

अध्यक्ष महोदय, कृषि की भाँति जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण विषय को भी मुख्यमंत्री सात निश्चय में शामिल नहीं किया गया है । महोदय, जल संसाधन विभागीय बजटीय आंकड़ा दर्शाता है कि प्रत्येक वर्ष बजट में राशि बढ़ायी जाती है परन्तु उसे उसी अनुपात में सरेन्डर भी किया जाता है, यह विभाग के नकारापन को साफ दर्शाता है । महोदय, हम यह कह सकते हैं कि जल संसाधन विभाग अपने निर्वाह योग्य कार्यों की परवाह नहीं करती है, यह साफ दिखता है ।

महोदय, बरसात के पूर्व बाँधों की सुरक्षा का समुचित इंतजाम नहीं किया जाता है जिससे कि बाढ़ का तांडव प्रत्येक साल होता है । महोदय, बाढ़ पीड़ितों को राहत शिविरों में मूलभूत सुविधाओं राशन एवं मुआवजा भी नहीं मिल पाता है । नहरों की उड़ाही, तटबंधों का पक्कीकरण एवं वर्त्तमान नहर प्रणाली को दुरूस्त विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है जिससे बड़ा भू-भाग पटवन से वंचित हो गया है ।

अब चूंकि महोदय, राज्य सरकार जल संसाधनों को दुरूस्त एवं जनोपयोगी बनाने में असफल हो रही है तब यह आवश्यक है कि कटौती-प्रस्ताव लाया जाय । इसीलिये महोदय, मैंने कटौती-प्रस्ताव लाया ताकि सरकार इस पर गौर करे और बजट में इसका प्रावधान करे । मुझे आपने कटौती-प्रस्ताव पढ़ने को कहा, बोलने को कहा इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ ।

अध्यक्ष : श्री भोला यादव ।

श्री भोला यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, महागठबंधन की सरकार के मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी एवं श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में और हमारे नेता गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद जी के निर्देशन में सफलता पूर्वक चल रही है, इसके लिये मैं अपने मुख्यमंत्री जी को, पूरे महागठबंधन के सभी सदस्यों की तरफ से बधाई का पात्र मानता हूँ, बधाई देता हूँ और हम सभी लोग उनके प्रति संकल्पित हैं ।

आज मुझे आपने जल संसाधन विभाग के माँग पर सरकार के पक्ष में बोलने के

लिये अवसर दिया है, इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूँ, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ ।

महोदय, कृषि आधारित हमारा बिहार राज्य है । सब कुछ कृषि पर ही निर्भर है, 80 प्रतिशत लोग कृषि पर जी अपना ही अपना जीवन-यापन और गुजर-बसर कर रहे हैं । इस कृषि कार्य के लिये सिंचाई की अहम भूमिका है । यदि सिंचाई की पूरी तैयारी नहीं रहे, पूरी तरह से इसकी व्यवस्था नहीं रहे तो कृषि पर प्रतिकूल असर पड़ता है और इससे हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है । महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि कृषि के लिये सिंचाई उतनी ही जरूरी है जितना हमारे मानव शरीर के लिये जल की जरूरत है, यदि हम पानी नहीं पीते हैं तो होठ सूखने लगता है उसी तरह से कृषि में जल की उतनी ही आवश्यकता है । मैं इसके लिये धन्यवाद देता हूँ अपने जल संसाधन मंत्री जी को जिन्होंने जो बजट लाया है, इन्होंने जो बजट पेश किया है, वह एक अपने-आप में आईना की तरह है और राज्य को विकास की तरफ अग्रसर करने के लिये बहुत ही कारगर है ।

मैं यह बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जल संसाधन विभाग को दो श्रेणी में विभक्त किया है । पहला है सिंचाई का सृजन, दूसरा है बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण। मैं यह बताना चाहता हूँ कि सिंचाई सृजन के मामला में इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है । अभी तक राज्य सरकार द्वारा वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजना से 29 लाख 88 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है । यह अपने-आप में एक माईल-स्टोन है । इस वित्तीय वर्ष में 97 हजार हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन इन्होंने किया है, यह काफी सराहनीय है । वर्ष 2016-17 में 1 लाख 51 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन किया गया है । बेहतर नहर संचालन के द्वारा वर्ष 2016-17 में 19 लाख 31 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल की सिंचाई प्रदान की गई है । मंत्री महोदय ने जो काम किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय, वह कम है । जो पिछले वर्ष से 2 लाख 14 हजार हेक्टेयर अधिक है । मैं यह बताना चाहता हूँ कि उत्तर बिहार का बहुत बड़ा इलाका बाढ़ग्रस्त इलाका है और दक्षिण बिहार का भी प्राय: इलाका बाढ़ से प्रभावित रहता है । कुल मिलाकर यदि देखा जाय तो पूरे बिहार में 73 प्रतिशत भूमि बाढ़ प्रभावित इलाका है और इस बाढ़ प्रभावित इलाका के लिये सबसे जरूरी है जल का निष्कासन और बाढ़ से नियंत्रण । तो इस दिशा में इन्होंने बहुत ही सफलता पाई है, अभी तक राज्य का 68 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है जिसमें से 3746 कि0मी0 तटबंध का निर्माण किया जा चुका है । नेपाल भाग में जो हमलोगों का इलाका है, उसमें 68 कि0मी0 तटबंध का निर्माण किया गया है जिससे 36 लाख 46 हजार हेक्टेयर भूमि सुरक्षित कर लिया गया है ।

...क्रमशः...

टर्न-11/आजाद/07.03.2017

...... क्रमशः ....

श्री भोला यादव : महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि भागलपुर जिला के चांदन नदी के किनारे 101 कि0मी0 तटबंध का निर्माण किया गया है, जिससे कि भागलपुर के इलाकों को सुरक्षित किया जा सके । मुजफ्फरपुर जिला में बागमती नदी पर 70 कि0मी0 बाढ़ प्रबंधन फेज-2 के द्वारा नये तटबंध का निर्माण कार्य काफी प्रगति पर है और हम समझते है कि वह जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा । महानन्दा बाढ़ प्रबंधन फेज-2 के तहत 200 कि0मी0 नये तटबंध का निर्माण कार्य प्रस्तावित है, उसपर भी काम जल्द शुरू होने वाला है । इस तरह से देखा जाय, नये तटबंध के लिए इन्होंने 3814 करोड़ रू0 का उपबंध किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी राशि है और इसके लिए मैं सदन के तरफ से आपके माध्यम से उनको बधाई देता हूँ । महोदय, बिहार में किसानों को पटवन के लिए बहुत से निजी नलकूप लगे हैं और उसकी भी संख्या बहुत बड़ी है 6281 निजी नलकूप हैं, जिसके द्वारा किसानों को अपना बोरिंग में पम्पसेट लगाकर के सिंचाई की व्यवस्था है । इसके अलावा सरकारी स्तर पर बड़े पैमाने पर स्टेट ट्यूबबेल लगा हुआ है, उसमें कुछ में खराबी है, जिसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसका जल्द सुदृढ़ीकरण कार्य कराया जाय । वैसे अधिकांश ट्यूबबेल चालू अवस्था में है, चल रहा है और उससे सिंचाई का बहुत बड़ा काम हो रहा है । महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि 16110 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता का सृजन छोटे नलकूप के द्वारा किया जा रहा है । प्रत्येक जिला में प्रत्येक प्रखंड में 571 ऑटोमेटिक डिजिटल वाटर लेवल रिकोर्डर स्थापित किया जा रहा है । इसके द्वारा यह पता चलेगा कि उस इलाके का किस भाग में वाटर लेवल डाऊन हो रहा है । पिछले वर्ष भी कई इलाकों में वाटर लेवल डाऊन हो गया था । जिसके चलते स्टेट ट्यूबबेल और किसानों द्वारा जो स्वस्थापित ट्यूबबेल है, उसमें पानी का अभाव हो गया था, इसकी जॉंच के लिए इन्होंने जो कदम उठाया है, वह बहुत ही बड़ा कदम है । इन्होंने सतही सिंचाई योजना के तहत 392 योजनाओं को स्वीकृत किया है, उस 392 योजनाओं में से 94 योजनायें पूर्ण रूप से कमप्लीट हो गया है, जिससे 13508 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा रहा है । महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सिंचाई मंत्री जी को इसके लिए आग्रह करना चाहता हूँ, जो उत्तर बिहार का बहुत बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित रहता है । उस इलाके को बाढ़ से त्राण दिलाने के लिए आपने जो कदम उठाया है, वह काफी नहीं है, कुछ और भी कदम उठाने की जरूरत है । मैं विपक्ष के भाईयों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो आपकी सरकार केन्द्र में है । आप केन्द्र की सरकार से वार्ता करे और जो नेपाल से पानी छोड़ा जाता है । अधवारा समूह के द्वारा,

बागमती के द्वारा, गंडक के द्वारा और जितनी भी नेपाल से निकलने वाली नदियां हैं, उससे बिहार की फसलों को नेस्तनाबूद कर देता है । मैं विपक्ष के सदस्यों से मांग करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि अपने नेता से बात करें और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ कि वे भारत सरकार से वार्ता करके नेपाल में बड़े-बड़े डैम का स्थापना करें, जिससे कि उत्तर बिहार के लोगों को पानी का सदुपयोग हो सके और समय पर सिंचाई की सुविधा मिल सके । दिक्कत यह हो रही है, डैम नहीं रहने के कारण जब नेपाल में बारिश अधिक होती है तो पानी छोड़ दिया जाता है और उससे हमलोगों का इलाका खासकर के मिथिलांचल का इलाका पूर्णरूप से नेस्तनाबूद हो जाता है । मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप भी अपने स्तर से अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को और भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी से सदन के माध्यम से जरूर आग्रह करें कि इस दिशा में सार्थक प्रयास हो और डैम का निर्माण हो।

(इस अवसर पर माननीय सभापति, डॉ0 अशोक कुमार ने आसन ग्रहण किया गया)

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार में जो शराबबंदी हुआ, उसका परिणाम सबके सामने हैं लेकिन उससे वित्तीय कठिनाई नहीं हुई । मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहता हूँ, इसके चलते वित्तीय कठिनाई नहीं हुई । लेकिन जो नोटबंदी हुई है, उससे वित्तीय कठिनाई हुई है । उससे राज्य का राजस्व में काफी गिरावट आयी है । नोटबंदी होने की वजह से राज्य के राजस्व में काफी गिरावटें आयी हैं । लेकिन इसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय सिंचाई मंत्री जी के सफल निर्देशन में सिंचाई विभाग का बजट पिछले वित्तीय वर्ष के वनिस्पत 3.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाय, वह कम है ।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय को मैं बताना चाहता हूँ कि नदियों के द्वारा जो कटाव हो रहा है, इसके लिए आपने बहुत सारी योजनाओं को स्वीकृत किया है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में आपने दो-दो योजनायें दी हैं । इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ । सबसे बड़ी योजना आपने दिया है डगरोल गांव और डगरोल गांव का जो सड़क था, हनुमाननगर प्रखंड के डगरोल गांव का जो सड़क था, वह पूर्णरूप से कटने के कगार पर था, उस कटाव को रोकने के लिए आपने जो काम किया है, वह बहुत ही सराहनीय है । इसी तरह से मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे विधान सभा क्षेत्र के नियाम एक गांव है हनुमाननगर प्रखंड में और एक गोरहारी गांव है, इन दोनों गांवों के पास बागमती नदी का कटाव हो रहा है, वह इस तरह से कटाव हो रहा है, यदि उसको रोका नहीं गया तो नयाम गांव संपूर्णरूप से समाप्त हो जायेगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसी वित्तीय वर्ष से इसको प्राथमिकता देकर के इस काम को करवा दें जिससे इस गांव को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जा सके । मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जो उसी हनुमाननगर प्रखंड के बागमती नदी के किनारे सैदपुर गांव बसा हुआ है । उस सैदपुर गांव में भी कटाव इस तरह से बढ़ रहा है, जो धीरे-धीरे मस्जिद के तरफ बढ़ते जा रहा है । आने वाले दिनों में अगर उसको संरक्षित नहीं किया गया तो मस्जिद भी कट जायेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि उस गांव को बचाने के लिए आप एक सफल कार्यक्रम तैयार कर आपने जो एजेन्डा तैयार किया है, उसको मूर्त रूप दे दीजिए । मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो कमलानदी में बहादुरपुर प्रखंड के दरगाहपुर मुशहरी एक कौरनर पर बसा हुआ है । यदि इसको संरक्षित नहीं किया गया, उसको बोल्डर पीचिंग नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में मुशहरी साफ हो जायेगा महोदय । मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दरगाहपुर मुशहरी जो दलित बस्ती है, उसको भी संरक्षित करने की कृपा करेंगे । साथ ही साथ कई चौड़ है, हमारे विधान सभा क्षेत्र में जिसमें सरसरेला चौड़, लेहारी चौड़, सिंहैला चौड़, तेतराही चौड़, ये चारों चौड़ एक ही कन्टीन्यूयेशन में है और उसका लगाव कमलानदी से है । यदि चारों चौड़ को जोड़ दिया जाता है, मैं पिछले सत्र में भी इसपर क्वेश्चन किया था तो उसका भी जवाब आया था कि जोड़ दिया जायेगा लेकिन अभी तक जोड़ने की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है । इंजीनियर लोग गये थे, देखे हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि उस चारों चौड़ को जोड़कर के उस कमलानदी में मिला दिया जाता है तो आने वाले दिनों में हजारों हेक्टेयर भूमि जल प्लावित रहता है, वह खेती के लायक हो जायेगा और उसमें बड़े पैमाने पर खेती होगी, जिससे राज्य का कृषि उत्पादन बढ़ेगा, इस दिशा में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य, कृपया अब आप समाप्त करें ।

श्री भोला यादव : महोदय, एक मिनट । बहादुर प्रखंड के दूरी गांव के पास भूतही बांध है । भूतही बांध हरेक साल टूटता है और उससे बहुत बड़ा क्षति होता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि भूतही बांध पर एक सूलिस गेट दे दिया जायेगा तो वह इलाका भी संरक्षित हो जायेगा । मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहता, मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ अपने विपक्ष के भाईयों से, माननीय देश के मुखिया जी जब चुनाव में आये थे, जब चुनाव में आये थे तो कहे थे कि मैं बिहार को विशेष पैकेज दूँगा । अभी हमें यू0पी0 में राष्ट्रीय अध्यक्ष साहेब के साथ जाने का अवसर मिला तो मैंने देखा कि वहां भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी लोक लुभावना प्रलोभन दे रहे हैं कि यदि मेरी सरकार आयेगी तो मैं किसानों का कर्जा माफ कर दूँगा । यह बताना चाहता हूँ अपने भाईयों से कि आप विपक्ष में हो, सबलोग चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े, बिहार

प्रगति के पथ पर जाय । मैं आपके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को संदेश देना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से बिहार को ठगने का काम किये, उस तरह से उत्तरप्रदेश को ठगने का काम नहीं करेंगे ....

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त करें ।

श्री भोला यादव : बल्कि बिहार को विशेष पैकेज देने का वादा किये थे, वह पैकेज आप उनसे बात करके दिलवाने का कष्ट करें, जिससे बिहार आगे बढ़ सके । इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ । सभापति महोदय, मैं आपको बहुत,बहुत बधाई देता हूँ, चूँकि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । धन्यवाद ।

टर्न-12/शंभु/07.03.17

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : सभापति महोदय, आज राज्यपाल के बजट के अभिभाषण और जल संसाधन विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद में आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं। इसके बाद जल संसाधन विभाग के वाद-विवाद में चर्चा के लिए जो कटौती प्रस्ताव आया है और माननीय मंत्री जी ने जो अपना प्रस्ताव रखा है और इस प्रस्ताव पर वाद-विवाद में हिस्सा लेने के लिए मैं आपको अपने क्षेत्र की जनता की ओर से, महागठबंधन की ओर से धन्यवाद देता हूँ। महोदय, बजट भाषण के बाद बारी-बारी से सभी विषयों पर चर्चा होना है- कल कृषि पर चर्चा हुआ, आज जल संसाधन विभाग पर चर्चा हो रहा है। जल संसाधन विभाग जब देश आजाद हुआ था उस समय जल संसाधन के बारे में कोई नहीं जानते थे कि आखिर इस विभाग में क्या हो रहा है। जब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू बिहार की बागडोर संभालने का काम किया तो जल संसाधन, कृषि उन्होंने सोचा- पूर्व के वक्ताओं ने अपनी बातों को रखने का काम किया कि किसानों के उपर बिहार की 80 प्रतिशत आबादी निर्भर करती है और उस आबादी को कृषि के माध्यम से देखा जाता है। हम कहना चाहते हैं कि जो कृषि विभाग हमारे विरोधी दल के लोग कह रहे थे कि कृषि को सात निश्चय में शामिल करना चाहिए था और शामिल नहीं किया गया तो उन्होंने कटौती प्रस्ताव में जो प्रस्ताव लाया है कि उसमें कटौती किया जाय। हम कहना चाहते हैं कि आज का जो बिहार है उस बिहार को देखिए। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं बिहार के लोगों को खासकर के विपक्ष में जो बैठे हुए हैं उनको कहना चाहते हैं कि जो आज बिहार है उस बिहार की कल्पना आज के रूप में कीजिए। खासकर के जल संसाधन विभाग जो कृषि विभाग से संबंधित है उसको कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ाने का काम करता है। किसानों की समस्या जो पटवन का सवाल है, किसानों का जो फसल डूब जाता है, तबाह हो जाता है उसको जल संसाधन विभाग के माध्यम से

सुरक्षित करने का काम किया जाता है। आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने बजट भाषण में विस्तार से खासकर के जल संसाधन विभाग पर चर्चा करने का काम किया है और खासकर के माननीय मंत्री जी जो सदन में अपने विभाग की ओर से अपनी बात को रखेंगे उसकी ओर हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जाना चाहते हैं कि आज बिहार में सिंचाई के सवाल पर जल संसाधन विभाग ने उसको दो भागों में बांटने का काम किया-बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई। आप भी अपने क्षेत्र में देखने का काम करते होंगे कि बाढ़ जब आता था तो बिहार के लोग सहम जाते थे। जब बाढ़ आता था तो लगता था कि क्या होगा, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार, आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी और सरकार जब बनी तो महागठबंधन ने निर्णय लिया कि जल संसाधन विभाग को इस तरह से सुसज्जित करना है जिससे लगे कि यह सात निश्चय के अलावे अगर कोई एक निश्चय है तो जल संसाधन विभाग है और यह देखने में जो हम देख रहे हैं राज्यपाल जी का बजट भाषण वह एक निश्चय शामिल है, देखने में नहीं लगेगा कि यह निश्चय साथ है, लेकिन सभापति महोदय, आज बिहार जिस तरह से जल संसाधन के क्षेत्र में चाहे सिंचाई का सवाल हो, चाहे नदियों के कटाव का सवाल हो उसको रोकने में जिस तरह से करिश्मा दिखाने का काम किया है, शायद देश का कोई राज्य ऐसा दिखायी नहीं दिया। हम कहना चाहते हैं कि पिछली बार अच्छा मौसम हुआ, उस मौसम में कई नदियां उफान पर थी, गंगा नदी का जल स्तर- हम लिखित भाषण की ओर नहीं जायेंगे, गंगा नदी का जल स्तर बजट में आया है कि यहां पर गया, वहां पर गया, गंडक का जल स्तर बढ़ गया, पुनपुन का जल स्तर पटना को डुबाने के स्तर पर था, इन सब चीजों को देखने का काम करता है, आखिर कैसे ऐसे हो रहा है। हम कहना चाहते हैं कि पहले जब बाढ़ आती थी तो पटना में चलना मुश्किल हो जाता था, लोग घर में रहते थे- विधायक जी कैसे निकलते, विरोधी दल के नेता जी का जो घर है, निकलने में दिक्कत हो जाती है। हम कहना चाहते हैं महोदय कि आज जल संसाधन विभाग ने जो इंतजाम किया नदियों के तटबंध को मजबूत करने का, नदी के किनारे जो नेपाल से निकलनेवाली नदियां हैं, चाहे पहाड़ से झारखण्ड से निकलनेवाली नदियां हैं, उन सभी नदियों को पक्कीकरण करवाने का काम किया-पक्कीकरण मतलब उसको मजबूत तटबंध देने का काम किया और यह दिखायी पड़ा कि अच्छा मौसम के बावजूद भी इस बार बाढ़ तो आया, लेकिन कोई क्षति बिहार में नहीं हुआ यह हम आज दावा करना चाहते हैं। जहां तक सिंचाई का सवाल है, सिंचाई के सवाल पर जल संसाधन विभाग ने अच्छा इंतजाम किया, पटवन का अच्छा सृजन किया, लाखो लाख हेक्टेयर में पटवन जल संसाधन विभाग के माध्यम से हुआ और इस बार देखने को मिला कि अगर पटवन बिहार के किसानों का हुआ है तो जल संसाधन विभाग की कृपा है। इस कृपा की बदौलत जो बिहार में धान का फसल हुआ, जो गेहूं का

फसल हुआ और जो पैदा आनेवाला है वह बिहार को चौंका देगा देश में- हरियाणा, पंजाब को पता चलेगा कि आखिर बिहार में कैसे इतना उत्पादन हुआ। हम कहना चाहते हैं कि यह उत्पादन का जो मूल मंत्र होगा यही जल संसाधन विभाग होगा। इसलिए महोदय, हम लिखित की ओर नहीं जा रहे हैं, हम डाटा की ओर नहीं जा रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि गंगा का पानी पटना तक ढंक गया, गंगा का पानी कैसे ढंक गया- जब चुनाव में आये थे चुनाव हुआ था खतम तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी कहे थे कि गंगा का एक अलग ही विभाग हम बना देते हैं- गंगा की सफाई होगी, गंगा का पानी रास्ता से आयेगा, रास्ता से जायेगा, लेकिन गंगा का पानी बिहार में उसका जल जमाव हो रहा है। यह जल जमाव कैसे समाप्त होगा ? गंगा का पानी आदरणीय मुख्यमंत्री जी बराबर बोल रहे हैं कि जल संसाधन विभाग अपना काम कर रहा है, लेकिन गंगा का पानी फरक्का बांध जहां से डैम्प पानी करता है और पानी निकल नहीं रहा है........क्रमशः।

टर्न-13/अशोक/07.03.2017

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : क्रमशः आदरणीय प्रधान मंत्री जी को...

सभापति(श्री अशोक कुमार) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : बराबर कहा जाता है लेकिन इस बात की ओर ध्यान नहीं रख जाता हैं । हम विपक्ष में बैठे हुये सदस्यों को कहना चाहते हैं कि वे आवाज को बुलन्द कीजिए कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी, जो चुनाव में कहे थे वह चुनाव के वायेदे को बिहार की धरती पर उतारने का काम करेंगे यही हम कहना चाहते हैं और हम कहना चाहते हैं कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में आज बिहार सात निश्चय के साथ, पूर्ण शराबबन्दी और जल संसाधन किसानों को मुहैया करके बिहार को विकास की ओर ले जा रहे हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : सभापति महोदय, कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, पंचतत्व में एक तत्व 'जल' है । महोदय, हमारा वेद, हमारा शास्त्र साफ कहता है कि "क्षिति जल पावक गगन समीरा
पंचतत्व से बना शरीरा "

महोदय, आज पंचतत्व में सबसे महत्वपूर्ण जल को इसलिये माना गया आज हमारी सृष्टि पर, हमारे पृथ्वी पर दो तिहाई जल है, शरीर के अन्दर हाड़ ओर मांस के शरीर के अन्दर दो तिहाई जल भरा हुआ है । हम अनुमान लगा सकते हैं महोदय कि जल कितना महत्वपूर्ण है । यह विभाग कितना महत्वपूर्ण है महोदय,

आज जल के अन्दर महोदय, 16 अव्यव पाये जाते हैं, जल इतना महत्वपूर्ण है महोदय कि संहार के देवता महादेव को जल से प्रसन्न किया जाता है और महोदय, जल से संकल्प लेकर वरदान और श्राप भी दिया जाता है । यह जल वह तत्व है, लेकिन आज संयोग से महोदय सदन के अन्दर जो दृश्य उत्पन्न है, आज तीन विभाग है महोदय, जल संसाधन विभाग, योजना विकास विभाग और लघु जल संसाधन विभाग । दो विभाग के माननीय मंत्री एक ही हैं उपलब्ध हैं और वे यहां उपलब्ध हैं लेकिन लघु जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री जल के महत्व को जल के तत्व को लघु सिंचाई को समझते ही नहीं हैं, इनकी अनुउपलब्धता सरकार की संवेदहीनता को भी प्रदर्शित करता हैं महोदय । महोदय, आज जो विभाग का, वित्तीय विभाग के अन्दर बजट जो आया है महोदय, 2015-16 में 2323 करोड़, 2016-17 में 2279 करोड़ और संशोधित 230 करोड़ भी आया था महोदय, इस बार 2017-18 में 3814 करोड़ का । जो माननीय मंत्री जी ने बताये महोदय ,बिहार को केन्द्र के द्वारा दिये गये अनुदान 2015-16 में 564 करोड़, 2016-17 में 583 करोड़ और 2017-18 में 945 करोड़ । महोदय, बजट कटौती, बजट करोड़ो में है महोदय, करोड़ों में इस बार बजट दिया गया, खर्च कितना परसेंट होता हैं महोदय? 30 से 35 परसेंट मात्र खर्च होता है महोदय । इस विभाग में अच्छे इंजीनियर आना नहीं चाहता हैं महोदय, और जो आता है वह जाना नहीं चाहता है । क्या कारण है विभागीय मंत्री ही अच्छी तरह से समझते हैं और बतलाना भी चाहेंगे । माननीय हमलागों की उत्सुकता भी है आखिर ऐसा क्यों हैं ? महोदय,माननीय मंत्री जी बताना चाहेंगे कि जल बिहार के लिए महत्वपूर्ण है, सामाजिक और आर्थिक सम्पदा है, जल सम्पदा पर हमें गर्व है, हम इसे अभिशाप क्यों बनने दे रहे हैं और यह कहा भी गया है

" निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, वह नर नहीं पशु के समान है " बिहार को सबसे बड़ा अगर जो कोई वरदान मिला है वह जल के रूप में मिला है। लेकिन यह जल बिहार के लिए अभिषाप बन रहा है, महोदय, कृषि आधारित प्रदेश होने के कारण आज आजीवीका के साथ साथ समर और स्मृद्धि, के लिए बेहतर सिंचाई विकसित करने की आवयकता है, जल का समुचित संरक्षण एवं प्रबन्धन विशेष महत्व रखता हैं । बाढ़ के जल प्लावन से सुरक्षा प्रदान तथा कटाव से रोक थाम इस विभाग का महत्वपूर्ण कार्य है । महोदय, कृषि योग्यजल मग्न क्षेत्रों से जल निकासी की व्यवस्था करना जल संसाधन विभाग का मुख्य दायित्व हैं महोदय। महोदय, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, फतुहा से बड़हिया टाल, पूरे बरसात में जलमग्न रहता है महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं हैं, उसी टाल क्षेत्र की योजना से महोदय उनका राजनीतिक उत्थान और राजनीतिक सिढ़ियों पर चढ़ाव शुरू हुआ

था ? माननीय मंत्री जी उस क्षेत्र से आते हैं महोदय, वह टाल की समस्याओं से अवगत हैं, तीन तीन महीना, चार चार महीना जल में डूबा रहता है महोदय, आज अगर उस टाल क्षेत्र में जल प्रबन्धन का, जल निकासी की व्यवस्था होती तो पटना से जाने में और बड़हिया तक रोड के हाई वे के किनारे किनारे जलमग्न रहता है, वह दाल का कटोरा वह अकेले पूरे बिहार का पेट भर सकता है महोदय। उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, बजट में प्रावधान बनाये हैं, दस वर्ष पीछे भी बीत गया महोदय, बार बार यही कहा जाता था कि हम जल प्रबन्धन के लिए प्राक्कलन बना रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि इससे बेहतर अवसर नहीं आयेगा आप खुद वहां से अवगत हैं, आप उस टाल की समस्या का निदान कर दें ,आप जल को वरदान के रूप में परिणत कर दें, इस अभिशाप को मिटा दें महोदय । अगर इस बार भी नहीं मिटा तो उस अभिशाप का शिकार पूरा बिहार होगा महोदय और उसके रोकने वाले लोग उससे वंचित नहीं होंगे। महोदय, आज इस छोटे छोटे नहर, पोखर, आहर, पैन का हमलोग मनरेगा के द्वारा, हमलोगों दूसरे दूसरे विभाग के द्वारा उसका जीर्णोद्धार करने का कार्य करने का केन्द्र ने भी निर्णय लिया, राज्य सरकार भी पहल कर रही है लेकिन जमीन पर वह हकीकत में नहीं उतर रहा हैं महोदय, कही न कहीं लघु जल संसाधन विभाग बीमार पड़ा हुआ है महोदय, अनुभवहीनता के कारण आज वह जमीन पर साकार रूप नहीं ले रहा है । महोदय, हम कहना चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय से कि संयोग से जल संसाधन और योजना विकास विभाग आपके जिम्मे हैं, आज विधायकों को भी इसमें अधिकार आप देने का कार्य करेंगे योजना विभाग इस तरह लघु सिंचाई विभाग के बहुत सारे छोटे छोटे कार्य में भागीदारी करने का अगर जो आप महत्व रखते हैं, देते हैं विधायकों को तो विधायक जीविका चलाने वाला जो कृषि पर आधरित कार्य हैं उसमें अपनी एक अहम भूमिका निभा सकता है । महोदय, आज आधुनिक तकनीक का उपयोग बिहार के अन्दर होता तो बाढ़ विभीषका से हम बच सकते हैं । बाढ़ पूर्वानुमान, बाढ़ आने की पूर्व सूचना हर जिले के अन्दर उसकी बेहतर प्रबन्धन की व्यवस्था, बाढ़ के बारे में माननीय सदस्य कह रहे थे कि बाढ़ में कोई क्षति नहीं हुआ, हर क्षेत्र के विधायक बैठे हें, इस पवित्र मंदिर के अन्दर, इस सदन के अन्दर इमानदारी से बात रखनी चाहिए, हमारे सामने सरकार बैठी है, बतानी चाहिये कि इस बाढ़ में, इस आपदा में कितनी त्रासदी हुई, कितने लोगों की जानें गई हैं, कितने हजारों एकड़ जमीन का फसल डूब गया, फसल क्षतिपूर्त्ति तक नहीं मिल, अभी बाढ़ राहत का पैसा भी पूरा नहीं मिल सका है महोदय । लेकिन हम चारण के चक्कर में, गुण गान के चक्कर में जनता के सामने अपने को अपराधी के रूप में खड़ा क्यों कर रहे हैं- यह विचार

करने की जरूरत है । सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, जनता की हित की बात पर हमको, आपको सही बात को रखना चाहिए क्योंकि सरकार अगर जो बनी है तो हमारे आपके ताकत से बनी है और सरकार को जब हम सही बात पर पायेंगे तो निदान के लिए अपनी भूमिका निभायेंगे ।क्रमशः

टर्न-14/ज्योति
07-03-2017

क्रमशः

श्री विजय कुमार सिन्हा : अगर सरकार को जब हम सही बात बतायेंगे तो निदान के लिए अपनी भूमिका निभायेंगे लेकिन अगर जो हम गुणगान करने में लगे रहेंगे तो हम कान की पट्टी में सरकार की जनता की समस्या की बलि चढ़ जायेगी । महोदय, आज हम एक चीज जानना चाहेंगे कि पिछले पॉच वर्ष का माननीय मंत्री महोदय, आजादी के बाद जो नहर का विकास किया गया था, श्री बाबू खास करके लख्खीसराय, शेखपुरा, जमुई, ये तमाम सिकन्दरा में, नवादा, नालन्दा के बेल्ट में कितने परसेंट सिंचाई की व्यवस्था में वृद्धि हुई ये बताने का कष्ट करेंगे । पिछले पॉच वर्ष में कितने परसेंट सिंचाई की नयी व्यवस्था बनी कितना डेवलपमेंट हुआ और इस नयी सरकार सोलहवीं विधान सभा में कितना परसेंट डेवलपमेंट आपने किया है । मरम्मती कराकर हम सिंचाई की व्यवस्था को बढ़ती जनसंख्या के ऊपर पर पड़ रहे कृषि पर दबाव को नहीं रोक पायेंगे । हम कितना डेवलपमेंट किए हैं, ये आपको मजबूती के साथ रखना होगा और सरकार के अंदर ..

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : अब समाप्त कीजिये । समाप्त हो गया समय ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : महोदय, अभी नहरों की उगाही और मैं कहना चाहूँगा महोदय, क्या शिक्षा के अंदर कृषि और जल संसाधन को प्राथमिकता देना होगा इस विषय को महोदय, भविष्य के अंधकार से अंजोरा की ओर लाना होगा । केन्द्र सरकार स्वायल हेल्थ कार्ड कृषि और जल का समन्वय बनाकर जो फसल डेवलपमेंट के लिए व्यवस्था बनायी है महोदय, उन तमाम व्यवस्थाओं में आज परिवर्तन करना होगा । अब अंतिम है महोदय, हलसी, रामगढ़ लख्खीसराय के अंदर जो नहर के किनारे सड़क बनायी गयी, बाढ़ में जो क्षतिग्रस्त हो गयी, प्राथमिकता के आधार पर माननीय मंत्री जी उसको जीर्णोद्धार करावें और नहर एवं पैन की उगाही आप करावें ।

श्री सिद्धार्थ : सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । आज हमारे बिहार की आबादी लम्प सम लगभग साढ़े दस करोड़ है मेरे आंकड़ों का मानना है कि इसकी 60 परसेंट जो आबादी है वह कृषकों की है और कोई भी कहीं का किसान हो उसकी खेती उसकी साल

भर की मेहनत जल संसाधन और लधु सिंचाई पर ही आश्रित होती है । मेरा मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश से हमारे माननीय जल संसाधन मंत्री ने इस विभाग को एक नयी दिशा और दशा देने का काम किया है और सही रुप में कृषकों की भलाई के लिए हमारी सरकार जो प्रतिबद्ध है, उस दिशा में आगे काम बढ़ाने का काम किया है । आज आप ले लीजिये तो बिहार के जल संसाधन विभाग के इतिहास में पहली बार ऐक्शन प्लान बनाया गया । विभाग ने कार्यों में गति लाने एवं योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए पहली बार 2016-17 में कार्य योजना तैयार किया गया है, जिस कार्य योजना के तहत 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में पूरी की जाने वाली सारी योजनाओं को चिन्हित कर उन योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है । इस विभाग में वित्तीय वर्ष 2016-17 में पॉच बहुत महत्वपूर्ण सिंचाई की योजनाएं थीं जिनका कार्य पूरा करके उनका आज पटना जिला के अंतर्गत लोआईज रामपुर बराज योजना औरंगाबाद जिलान्तर्गत जगतनाथ वियर जहानाबाद जिलान्तर्गत मोर वियर एवं सोलहण्डर वियर एवं अरवल जिलान्तर्गत पंतित वियर का कार्य पूर्ण करके इसका उद्घाटन किया गया और इस योजना के माध्यम से करीब 10840 हेक्टर में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का श्रृजन तथा 10573 एकड़ सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन हुआ । साथ ही वर्ष 2016-17 में रेकर्ड खरीफ की सिंचाई की गयी । 2016-17 में खरीफ में नहरों में अंतिम क्षोर तक पानी पहुंचा कर 19 लाख हेक्टर में कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी । यह विगत 28 वर्षों में सर्वाधिक है । एक विशेष ध्यान मैं माननीय मंत्री जी, का आपके माध्यम से देना चाहूँगा पटना कैनाल सोन नहर प्रणाली बलिदाद लख से शुरु होता है जिसकी लम्बाई 47 कि0मी0 है तथा जल स्राव 1165 क्यूसेक है पटना कैनाल के वितरणियों एवं मुख्य कैनाल में दो हजार क्यूसेक पानी की खपत है जिसके कारण कैनाल के विभिन्न वितरणियों में अंतिम क्षोर तक मौसम के अनुकूल समय पर पानी नहीं मिल पाता है । बहुत सी ऐसी छोटी छोटी वितरणियॉं हैं जहॉं पर जबतक कि दो हजार क्यूसेक पानी इस कैनाल से नहीं छोड़ा जायेगा तबतक उन छोटी छोटी वितरणियों को जीवित रख पाना संभव नहीं है । पानी अभी जो छोड़ा जा रहा है वह 1165 क्यूसेक है और आवश्यकता दो हजार क्यूसेक की है इस कारण से प्रबंधन के अभाव में पालीगंज प्रखंड दुल्हीनबाजार प्रखंड, बिक्रम प्रखंड, नौबतपुर प्रखंड, फुलवारी, बिहटा यहॉं तक कि मनेर क्षेत्र में खरीफ और रबी में हजारों हेक्टर में लगी फसल बर्बाद हो जा रही है। साल भर मेहनत कर किसान जो फसल उपजाने का प्रयास कर रहे हैं इस जगह पर पानी सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है । वर्तमान स्थिति में यहॉं तातिब

सिस्टम लागू कर दिया गया है 10 दिन किसी प्रखंड में पानी छोड़ा जाता है, दस दिन किसी और प्रखंड में पानी छोड़ा जाता है समय पर पानी हो नहीं पाता है और चूँकि उचित क्षमता के अनुकूल पानी नहीं छोड़ा जाता है किसान आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और कहीं का बांधा कहीं काट कर कहीं का कुछ करके करते हैं इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इसके लिए एक पटना मुख्य नहर में महाबलीपुर लख के पास से सोन नदी में एक हजार क्यूसेक पानी लिफ्ट करने का प्रबंधन कीजिये ताकि इन्द्रपुरी बराज से जलाशय निर्माण की दिशा में त्वरित कार्रवाइ कीजिये । रानी तालाब लख धाना परवेज वितरणी में अंतिम क्षोर तक बेहतर उड़ाही के प्रबंधन के लिए बहुत आवश्यक है । बहुत सी ऐसी छोटी छोटी वितरणियाँ जहाँ कि पानी नहीं पहुंचने के कारण साल भर जो किसान मेहनत कर रहा है, हर साल करीब करीब इसतरह से पटना पश्चिम के इलाके में किसान की मेहनत व्यर्थ जा रही है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस दिशा में सरकार पहल करे और जल संसाधन विभाग एक नया इतिहास रचने का काम करे । दूसरा मैं एक आवश्यक जानकारी देना चाहूँगा कि जिला किशनगंज में हलण्डा पंचायत है उसमें कब्रिस्तान का कटाव हो रहा है और महानंदा नदी के कारण , इसको सुरक्षित करने की आवश्यकता है नहीं तो पूरा कब्रिस्तान बह जायेगा । इसी जिला में किशनगंज जिला में पोठिया प्रखंड में देवी चौक से सोनपुर जाने वाली मुख्य सड़क में डौक नदी से कटाव हो रहा है । अगर इसे संरक्षित नहीं किया गया तो इस पूरे गांव को भी बहुत भीषण खतरा हो सकता है । मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि पटना सोन कैनाल प्रणाली बलिदाद लख की जो समस्या है इसपर आवश्यक रुप से कार्रवाई की जाय । बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री राम विलास पासवान : माननीय सभापति महोदय, मैं आज के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए और कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । माननीय सभापति महोदय, आज जल संसाधन विभाग से जो काम हुआ है उसकी कितनी भी प्रशंसा की जाय तो वह कम पड़ेगी । माननीय सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग से दो भाग बंटते हैं एक तो जल से कटाव और दूसरा है जल से कृषि भूमि में जो उपज होती है तो वह आज दोनों विषय पर जो काम हुआ है वह सराहनीय है । आज सभापति महोदय, जो गंगा नदी से जो कटाव हुआ है चाहे वह वीहपुर हो , नवगछिया हो , भागलपुर विश्वविद्यालय कट रहा था, तमाम जगह काम हुआ है और काम चल रहा है। काफी मात्रा में काम चल रहा है । गंगा नदी

से जो कटाव हो रहा था सिंचाई की जो व्यवस्था थी वह किसान का जो सिंचाई का साधन था उसमें भी काम हो रहा है ।

क्रमशः

टर्न-15/07.3.2017/बिपिन

श्री राम विलास पासवानः क्रमशः महोदय, बहुत तेजी में काम हो रहा है और आज जो वह मांग किया गया है 38अरब 14करोड़ का, मैं समझता हूं कि यह भी अगर देखा जाए तो यह भी कम पड़ेगा । इसलिए विपक्ष के लोग इस पर कटौती का प्रस्ताव लाने का काम करते हैं । लेकिन मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से विपक्ष के साथी को बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीतिश जी, तेजस्वी जी, गठबंधन सरकार के सभी मंत्रीगण जो बिहार में काम कर रहे हैं, शायद विपक्ष के लोगों को वह विकास अच्छा नहीं लग रहा है, उनको खल रहा है । इसलिए वह बार-बार एक-एक मुद्दा को उठा कर और यहां पर यह करते हैं लेकिन मैं माननीय सभापति महोदय, आज बिहार के मुख्यमंत्री जी चुनाव के पहले जो उन्होंने वायदा किया था, जो उन्होंने बात कही थी, आज उसपर खड़े उतरने का काम किये है लेकिन यह नहीं कहे कि आज बोल दिया कुछ, कल बोल दिया कुछ । ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी और गठबंधन की सरकार नहीं किया है ।

माननीय सभापति महोदय, आज घोषणा किये थे, आज प्रधानमंत्री जी ने घूर-घूर कर घोषणा किया था कि दो से पांच करोड़ लोगों को नौकरी प्रत्येक साल देंगे लेकिन एक भी बात नहीं सत्य निकला । आज इन्होंने कहा था सभापति महोदय कि प्रत्येक गरीबों के घर में, प्रत्येक किसानों के घर में 15-15 लाख रूपया, खाता भी खुलवा दिया, खाते पर आ जाएगा । लेकिन माननीय सभापति महोदय, हमारी बिहार सरकार ने ऐसा नहीं किया है । हमारे गठबंधन की सरकार ने ऐसा नहीं किया है । वह जो कहा है, वही कर रहा है । कहा था, मैं शराबबंदी कर दूंगा । शराबबंदी जो है बिहार में पूर्णरूपेण करके दिखाने का काम किया है माननीय सभापति महोदय, और यही सब जो है विपक्ष के हमारे साथी को खलता है कि बिहार की सरकार, गठबंधन की सरकार ने जो कहा है, वह हो रहा है । लेकिन केन्द्र की सरकार ने जो कहा है, वह कर नहीं रहा है, वह असत्य, दिग्भ्रमित करके बिहार के भोले-भाले जनता को ठगने का काम किया है, चाहे वह 15 लाख रूपया खाता में देने की बात हो, चाहे नौजवानों को नौकरी देने की बात हो, वह सारी बात इनका असत्य-ही-असत्य हो रहा है ।

माननीय सभापति महोदय, जो जल संसाधन से विकास हुआ है और हो रहा है, जल संसाधन से, वह एक भी असत्य नहीं है और चल रहा है लेकिन हमारे गठबंधन

की सरकार असत्य नहीं बोलती है । अब असत्य बात ये लोग उठकर कुछ-से-कुछ बोलना शुरू करते हैं लेकिन एक-एक उदाहरण है जो बिहार सरकार ने कहा है, सात निश्चय का बात कहा है । सभापति महोदय, बिहार सरकार ने सात निश्चय को लाने का काम किया है और सात निश्चय के तहत वह सारे बिजली, नल से शुद्ध पानी देने का, तमाम जो सात निश्चय लाने का काम किया है । यही चुनाव के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालु प्रसाद जी ने जनता को कहा था कि मैंने जो कहा था वही करने का काम करेंगे । आदरणीय लालु प्रसाद जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था वही कर रहे हैं । माननीय सभापति महोदय, उसमें एक भी बात अगर विपक्ष के लोग कहें कि असत्य है तो हम उनकी गुलामी करेंगे । लेकिन जो केन्द्र की सरकार ने असत्य वायदा करने का काम किया है, हर समय बिहार की जनता को, भोली-भाली जनता को ठगने का काम किया गया है । अभी आप सुने होंगे सभापति महोदय, गंगा जी ने बुलाया है । अरे, गंगा जी कब बुलाते हैं, गंगा जी तब बुलाते हैं, जब अंतिम होता है । मैं आपका शुभकामना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, कि मैं उनके दीर्घायु के लिए शुभकामना चाहता हूं । भगवान न करे कि गंगा जी मोदी जी को बुलावें । जब गंगा नदी से पानी आता है महोदय, तब बहुत ज्यादा हमलोग का क्षति हो जाता है । हमलोगों को, जब फरक्का बनाने का काम किया गया है सभापति महोदय, तब से हमारी गंगा माता का जल स्तर ऊंचे पर आ गया है । मलवा भीतर में जमने के कारण पानी हमारे उपर से जब वेग से आता था तो पटना से लेकर भर झारखंड सीमा साहेबगंज तक नदी पूरा खलखलाते हुए पानी निकल जाता था। लेकिन सभापति महोदय, अभी यह हो गया है कि गंगा जी में मलवा भरने के कारण अभी नदी भर गया है और हमलोगों के तमाम पटना से लेकर भागलपुर तक चारों बगल पानी छिड़िया जाता है, उसके कारण हम किसानों को काफी दिक्कत होती है लेकिन माननीय मंत्री जी ने उस पर काफी पहल कर, मैं दावा के साथ कहता हूं सभापति महोदय, कि आज तक ऐसा हमने नहीं देखा था कि जिस घर में पानी घुस गया, घर में जो खाना खाता था उससे बढ़िया खाना बनाकर खिलाने का काम किया है सभापति महोदय यह गठबंधन की सरकार ने । सभापति महोदय, सभी जगह मैं घूम-घूम कर देखा था जहां-जहां भोजन का शिविर चल रहा था, गरीब-दुखिया जिसके घर में पानी आया था लेकिन मैं विश्वास के साथ आँखों देखा मैं कह रहा हूं सभापति महोदय कि हमलोगों के घर में जो खाना बनता था तो वही खाना, उससे बढ़िया बनाकर जिसके घर में पानी घुसा था उसको खिलाने का काम किया था । सभापति महोदय, यह सब देखकर विपक्ष के लोगों को खलता है, अच्छा नहीं लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री और गठबंधन के सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे काम कर रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये लोग गणेश जी को दूध पिलाने वाले हैं, पत्थर की मूर्ति को

दूध पिलाते हैं सभापति महोदय, हमलोगों के गठबंधन की सरकार में पत्थर की मूर्ति को दूध नहीं पिलाया जाता है । मैं इसी पर एक कहानी कहता हूं सभापति महोदय । झूठ का एक कहानी कहता हूं महोदय ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार):माननीय सदस्य, आप झूठ शब्द बार-बार नहीं कहें । असत्य कहें । अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, मैं चंद ही मिनटों में समाप्त करता हूं । सभापति महोदय, एक चतुरबुद्धि नामक और चपलबुद्धि नामक दो सियार था । दोनों का रोजगार था सभापति महोदय । पहाड़ पर रहता था और रात में उतर कर दोनों गृहस्थ के यहां भोजन के लिए ढूढ़ता था शिकार के लिए । शिकार ढूढ़ने के दरम्यान एक दिन उन्होंने एक धोबी के घर में घुस गया और धोबी के घर में घुसने पर नील का पूरा नाद घोरा हुआ था तो उसमें चतुरबुद्धि और चपलबुद्धि नामक सियार उस नाद में डूब गया सभापति महोदय । जब घोबी कपड़ा पीटने वाला लेकर जब रगेदा तो भागा सभापति महोदय, तो पूरा ...

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार):अब समाप्त कीजिए आप ।

श्री राम विलास पासवान: एक मिनट में समाप्त करता हूं । सभापति महोदय, ...

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार):अब समाप्त कीजिए । श्री निरंजन कुमार मेहता ।

टर्न-16/कृष्ण/07.03.2017

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता, आप अपना भाषण प्रारंभ करें ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय सभापति महोदय ।

(व्यवधान)

सभापति (डा0अशोक कुमार) : शांति,शांति । माननीय सदस्य निरंजन कुमार मेहता, आप बोलिये ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2017-18 के व्यय विवरणी पर सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांग के समर्थन में बोलने के लिये मैं खडा हुआ हूं ।

(व्यवधान)

सभापति (डा0अशोक कुमार) : आप अपना भाषण चालू रखिये ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, लोकतंत्र के इस पवित्र सदन में सबसे पहले मैं माननीय सभापति महोदय, आपने आज मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, मैं आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं, उस विकास पुरूष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, आभार व्यक्त करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का, मैं आभार व्यक्त करता हूं जल संसाधन मंत्री जी का, मैं आभार

व्यक्त करता हूं संसदीय कार्य मंत्री महोदय का । महोदय, मैं आपके माध्यम से जिसने इस सदन में जहां की जनता मुझे भेजी है, मैं आभार व्यक्त करता हूं इस सदन से बिहारीगंज की तमाम महान जनता का, उन्हें मैं हार्दिक बधाई देता हूं । महोदय, एक साल के दौरान महागठबंधन सरकार ने जो काम किया है, हमारे मुख्यमंत्री महोदय चुनावी झण में 218 चुनावी सभा को संबोधित किये थे । उन्होंने जो भी वादा किया आम जनता से, आज उन्होंने एक साल में करके दिखा दिये । सात निश्चय में शराबबंदी ऐसे काम को उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लेकर अपना काम करके दिखा दिया है और 38 जिलों के निश्चय यात्रा के दौरान दौरा कर के हर काम का लोकापर्णय इन्होंने करके दिखा दिया है । आज महागठबंधन की सरकार में ऐतिहासिक कदम उठाकर शराबबंदी जैसे काम को तथा सात निश्चय के हरेक प्रोग्राम को जमीन पर उतार दिया तथा 38 जिलों के निश्चय यात्रा के दौरान पूरी समीक्षा के साथ सात निश्चय में हरेक प्रोग्राम को लोकार्पण करने का काम किया है । आज हरेक ग्राम पंचायत में सिलसिलेवार काम हो रहा है, जो कि धैर्य रखने की बात है । मात्र दो साल में काम दिखने लगा है आईने की तरह । अब हम जिस विषय पर बोलने के लिये खड़ा हुये हैं, जल संसाधन विभाग पर बोलने के लिये खड़ा हुये हैं, उसके संबंध में कुछ कहना चाहता हूं । महोदय, मैं कोसी क्षेत्र से आता हूं, जल संसाधन विभाग हमलोगों का बहुत ही अहम विभाग हैं । हर बरसात के मौसम में हमलोगों को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ता है । जब 2008 में भीषण बाढ़ आई थी, उस दिन मैं यहां नहीं आया था । इस सदन में तो आज मैं आया हूं । लेकिन 2008 की विभीषिका में हमलोगों को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा देखा गया था, उस क्षण को आज भी कोसी की तमाम जनता उसको भूलाने का काम नहीं किया है । वहां की तमाम जनता इस महागठबंधन की सरकार को एक-एक वोट देने का काम किया है । कोसी कमीशनरी से कितने सदस्य जीत कर आये हैं, वह तो सब के सामने हैं । बाढ़ की विभीषिका में 2008 में बहुत से काम किये थे, जिसे हमलोग जन्म-जन्मांतर भूलनेवाले नहीं हैं । जल संसाधन विभाग की अनुदान की मांग पर सरकार के समर्थन में बिहार का सकरात्मक कार्य का विवरण पेश कर रहा हूं । जल संसाधन विभाग राज्य में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं जल नि:सरण के जनोपयोगी कार्य को सम्पादित करता है । भौगोलिक एवं जलवायु जनित स्थिति के कारण वर्षा ऋतु में जब राज्य की नदियों में एक तरफ भीषण कटाव एवं बाढ़ की परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो दूसरी तरफ खेतों में सिंचाई के लिये खरीफ फसल के लिये सिंचाई की भी आवश्कता होती है । दो पृथक खडों सिंचाई सृजन तथा बाढ़ नियंत्रण एवं जल नि:सरण के पुनर्गठित किया है । ऐसे में अभियंताओं का दल बाढ़ के कटाव से आवश्यक संरचनाओं को सूचित करने में संघर्षरत रहते थे तो दूसरी तरफ खेतों में सिंचाई प्रदान करने हेतु निर्मित नहरों में टूटान की स्थिति में सिंचाई कार्य में

बाधा होने के कारण आज जल संसाधन विभाग के माननीय मंत्री महोदय द्वारा दोनों को कार्य संचालन में कोई दिक्कत न हो, खेत में पानी पटाने में दिक्कत नहीं हो और बाढ़ के काम में भी कोई दिक्कत न हो, इसके लिए विभाग द्वारा अभियंताओं को इस तरह पुनर्गठित किया गया कि जिस दल को बाढ़ नियंत्रण का काम करना है, वह बाढ़ नियंत्रण का काम करेगा और जिस दल को सिंचाई का काम करना है, वह केवल सिंचाई का काम करेगा । दोनों को अलग-अलग विभाग का पुनर्गठित करके माननीय मंत्री ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है । वे पूरी तरह सिंचाई का कार्य कराने में ही संलग्न रहे । जल संसाधन विभाग वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं को किर्यान्वित कर खेतों में पानी पहुंचाने एवं बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं का पूरा कर बाढ़ से जान-माल को सुरक्षित करने हेतु दृढ़ संकल्पित है । राज्य में बृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से दिसंबर,2016 तक 29 लाख 88 हजार वृहद् क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है । चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक 1 लाख 18 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सृजन का लक्ष्य किया है । योजनाओं को द्रूतगति से पूरा करने के लिये एक्शन प्लान तैयार किया गया है । वर्ष 2016-17 में 5 अदद सिंचाई की कार्य योजनाओं के तहत पटना जिलान्तर्गत लराईच रामपुर बराज योजना, औरंगाबाद जिलान्तर्गत जगरनाथ बीयर जहानाबाद जिलान्तर्गत मा ेर बीयर का कार्य पूर्ण कर इसका उद्घाटन भी कराया गया । इससे औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, पटना एवं प0चम्पारण के किसान आज इससे लाभान्वित हो रहे हैं । इन योजनाओं को 10,840 हे0 में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन तथा 10,573 हे0में ह्रासित सिंचाई का पुनर्स्थापन किया गया है । गाद एवं सर्वेक्षण के कारण सिंचाई योजनाओं की क्षमता में ह्रास होने लगता है । 2016-17 में 22,740 हे0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन वर्ष 2016-17 में पूर्ण हो चुकी 5 अदद योजनाओं के अतिरिक्त अन्य योजनाओं सहित उदेरा स्थान बराज, नसेदपुर बीयर योजना, कचरावा बीयर योजना, सिवान बीयर योजना आदि के कार्यान्वयन से कुल 22,740 हे0 क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है । बेहतर नहर संचालन के द्वारा 2016-17 मे 19 लाख 31 हजार हे0 में खरीफ सिंचाई में नहरों के अंतिम छोर तक प्रदान की गयी, जो गत वर्ष की उपलब्धि से 2 लाख 14 हजार हे0 अधिक है । यह विगत 28 वर्षों में सर्वाधिक है । अभी रब्बी फसल की सिंचाई के लिये नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है । आशा है इस वर्ष रब्बी में भी गत वर्ष की उपलब्धि 3 लाख 818 हजार हे0 से अधिक क्षेत्रों में सिंचाई प्रदान की जा सकेगी । अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन 2017-18 में मुंगेर जिला में चांदकेन सिंचाई योजना ।

सभापति : अब आप समाप्त करें ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, समाप्त करते हैं । जल संसाधन विभाग द्वारा जो भी कार्य कराये गये हैं, वे बहुत ही सराहनीय हैं । अंत में मैं अपने क्षेत्र के संबंध में कुछ कहना

चाहता हूं । मैं पिछले सत्र में भी प्रश्न के द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था । हमारे यहां एक सुरसर नदी है, उसके द्वारा चार प्वायंट पर बहुत खतरा होता है । इस बार भी प्रश्न किये थे, माननीय मंत्री एवं विभाग का सहयोग प्राप्त हुआ था तुरंत उस पर इमरजेंसी वर्क चालू किया गया, उसमें हमने धारा परिवर्त्तन की मांग किये थे । अरार घाट में और हमारे मुरलीगंज प्रखंड में वृन्दावन और ग्वालपाड़ा प्रखंड में है सुखासन बिंदटोली और वृन्दावन और तिलकोरा है, चार जगह का हम दिये हुये हैं, धारा परिवर्त्तन के लिये हम दिये हुये हैं, जमीन काफी मात्रा में उपलब्ध है ।

क्रमशः

टर्न-17/राजेश/7.3.17

श्री निरंजन कुमार मेहता, क्रमशः- विभाग को कहके जब वहॉ धारा परिवर्तन हो जायेगा, तो विभाग भी निश्चिंत रहेंगे और हमारे गॉव समाज के लोग, जो पूरा गॉव का गॉव डूबता है, डूबना भी बंद हो जायेगा और बाढ़ से लोगों को किसी प्रकार का खतरा भी उत्पन्न नहीं होगा, इसी के साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का भी आभार व्यक्त करता हूँ और आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ । जय हिन्द, जय महागठबंधन ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह ।

श्री विनोद कुमार सिंह: सभापति महोदय, आज मैं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य श्री अरुण कुमार सिन्हा जी के द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खडा़ हुआ हूँ । सभापति महोदय, पूर्व के माननीय सदस्य जो अपना विचार प्रकट कर रहे थे, उन विचारों में कहीं न कहीं सत्य से परे बात दिखाई दे रहा था । हम बोलना चाहेंगे सभापति महोदय, की जल के बिना जीना दुर्लभ है और जल ही जीवन है सिर्फ पीने के पानी के लिए मिनरल वाटर नहीं, यह कि बिना पानी का सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण विभागों का जो बॅटवारा किया गया है, उस बॅटवारे में जल संसाधन विभाग और लघु सिंचाई विभाग बड़ा ही महत्वपूर्ण है । आज जो मैं बोलना चाह रहा हूँ सभापति महोदय, बड़ी ही ईमानदारी के साथ इस सदन में हम बातों को रखना चाहते हैं । सभापति महोदय, आज बिहार के अंदर जो बाढ़ की विभिषिका के कारण हमारे राज्य का 38 जिला, जो बाढ़ और सुखाड़ के कारण और यहॉ की जनता और किसान तड़पते रहती है, उस संदर्भ में हम बताना चाहते हैं । जो बचपना के वर्ग में हमलोग पढ़ा करते थे वर्ग-1 से लेकर 7 क्लास तक, मुझे आज भी याद है कि 1971 की बाढ़ जो बिहार की राजधानी पटना में आयी, उस बाढ़ की विभिषिका और उस प्रलयंकारी बाढ़ के कारण जो बिहार का वातावरण बना था, आज भी वह दर्दनाक स्थिति रोंगता खड़ा करने वाला होता है

सभापति महोदय । जब बिहार की राजधानी पटने के अंदर में बाढ़ के कारण और सारे मध्यम वर्गीय और निम्नवर्गीय लोगों का घर जल प्लावित हो गया था, जो दो मंजीला और तीन मंजीला घर था, उस दो-तीन मंजिले घर के अंदर में लोग अपना किसी प्रकार से शरण लिया करते थे और वह भीड़ दिखाता था, उपर से हेलिकॉप्टर के माध्यम से कहीं किसी के छत पर बिस्कुट का पैकेट गिराया जाता था, वह पैकेट छपा हुआ किताब में दिखाई दे रहा था, वह पॉच पैकेट गिराया जाता था और 500 लोग हाथ उठाकर लग रहा था कि लोग जैसे भीख मॉग रहे हैं, एक अनार सौ बिमार की स्थिति सभापति महोदय, आप भी 1971 की बात को याद कीजिये, आप भी उस समय निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बुद्विमान रहे होंगे, हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि 1971 में हवाई सर्वेक्षण और हेलिकॉप्टर के द्वारा जो थोड़ी बहुत बाढ़ पीड़ितों को सहायतार्थ पहुंचायी जाती थी, आज 2016 की बाढ़ में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हेलिकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण करके बिहार में आये 24 जिलों के अंदर बाढ़ की विभिषिका को देखने के लिए मैंने टेलिफोन पर भी दो-दो बार माननीय मुख्यमंत्री जी को आगाह किया कि उत्तरी बिहार के अंदर में कटिहार, पूणियॉ, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, बेगूसराय एवं सहरसा जिलों के अंदर में बाढ़ की विभिषिका बढ़ती जा रही है, इसलिए आइये माननीय मुख्यमंत्री जी और हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से, वहॉ पर देखकर जब लौटकर आये, तो मुआवजा और बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ राशि देने की चर्चा की थी और उसमें यह देखा गया, जिस कटिहार जिले के अंदर, हम बताना चाहते हैं 1987 ई0 के अंदर सभापति महोदय, असामाजिक तत्वों ने महानंदा बॉध, महानंदा नदी के कारण आयी प्रलयंकारी बाढ़ के कारण महानंदा बॉध को काटा गया था 1987 में और 1987 के बाद लगातार 22, 23 सालों तक हमलोगों के द्वारा संघर्ष करने के बाद भी, बीच में कॉग्रेस की सरकार रही और संघर्ष करने के बाद उस कचौरा बॉध की मरम्मति के लिए प्राणपुर विधान सभा कटिहार जिले के अंदर, मनिहारी विधान सभा सालमारी डिवीजन का, कटिहार डिवीजन का 95 किलोमीटर लंबे तटबंध को मजबूत करने के लिए 2010 के मुख्यमंत्री को हृदय से इस सदन के अंदर धन्यवाद देना चाहता हूँ, वे 2010 के मुख्यमंत्री कौन थे, वही मुख्यमंत्री थे, जो आज बिहार के मुख्यमंत्री है लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाईटेड के जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्री बिहार के अंदर में थे, वे मेरी बात को सुनकर 95 किलोमीटर लंबे तटबंध को मजबूतीकरण, ऊंचीकरण, चौड़ीकरण और ईट सोलिंग कराने का काम किया था और उसका शिलान्यास हमारे विधिवत माननीय मुख्यमंत्री और उस समय के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव जी, हलॉकि अभी वे सदन में नहीं है, वे भी वहॉ गये हुए थे, उसकी मरम्मति करायी गयी सभापति महोदय, मरम्मति कराने के बाद पॉच साल बीतने के बाद माननीय सदानंद बाबू से हम अपील करना चाहेंगे, वही कचौरा बॉध के समीप

कुछ असामाजिक तत्वों ने फिर पॉच-छः लोग मिलकर कचौरा और शिवगंज के बीच बॉध को काट दिया और काटने का परिणाम यह हुआ सभापति महोदय कि 200 से 300 मीटर की दूरी पर वहॉ महानंदा नदी का बॉध कट गया और स्थिति ऐसा हुआ कि कदवा प्रखंड का 30 पंचायत, आजमनगर प्रखंड का 12 पंचायत, प्राणपुर विधान सभा क्षेत्र का 12 पंचायत, मनिहारी विधान सभा क्षेत्र का कई पंचायत, डंकखोरा और हसनगंज पंचायत, कटिहार का पंचायत और उधर गंगा नदी के कारण कटिहार, कुर्सेला, बरारी के अंदर में और मनिहारी के अंदर में गंगा नदी के कारण मनिहारी और अमदाबाद का दर्जनों गॉव जल प्लावित हो गया और जल प्लावित होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से हमने अपील किया था कि वहॉ पर मुआवजा की जरुरत है, आप जाइये माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ के लिए छः हजार रुपये प्रति बाढ़ पीड़ितों को देने की चर्चा की थी लेकिन नतीजा यह हुआ कि प्राणपुर विधान सभा क्षेत्र के अंदर प्राणपुर प्रखंड के अंदर 32 हजार परिवार के बीच में मात्र छः हजार परिवारों को मुआवजा दिया गया बाढ़ पीड़ितों के बीच में और 25 से 27 हजार परिवारों को मुआवजा नहीं दिया गया सभापति महोदय, यह बात हम अपील करना चाहते हैं और यह भी हम कहना चाहते हैं कि जो इस वित्तीय वर्ष राशि तैयार हुई है, उसमें 38 अरब रुपये से ज्यादा की राशि का जो डिमांड किया गया है, जिसमें हमारे माननीय अरुण बाबू जी ने जो कटौती प्रस्ताव पेश किया है कि इस शीर्षक की मांग 10 रुपया से घटायी जाय, हम उस संदर्भ में आपको बताना चाहते हैं कि जल संसाधन विभाग के अंदर में प्रक्षेत्र के अनुकूल मुख्य अभियंता, अभियंता का आपने बॅटवारा किया है, आपके अभिभाषण के इस पुस्तक में सारी बाते उद्धरित है लेकिन एक भी बाढ़ पीड़ितों के बीच में और न ही एक भी किसानों के बीच में मजबूर होने नहीं देंगे, उसके लिए हम संघर्षशील हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, आपके प्रतिवेदन में यह सारा चीज छपकर तैयार हो गया है, ये तीन महीना से लेकर 9 महीना तक कान में तेल डालकर सोने का काम मुख्य अभियंता से लेकर कनीय अभियंता तक करता है और जब जून, जुलाई और अगस्त का महीना आता है, तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के अंदर में ये लोग चले जाते हैं और पंप सेट चालू करके और चार गो जेनरेटर खड़ा करके वहॉ पर माननीय विधायक चाहे जिस भी दल के हो, जब जाते हैं तो अस्त-व्यस्त उसकी स्थिति रहती है, कहीं 10 बोरा खाली, कहीं 15 बोरा खाली, स्थिति है कि सारा जगह सिपेज होता रहता है और इसका परिणाम सामने यह आता है सभापति महोदय कि सारा बॉध कट जाता है और कटने के बाद रातों रात लोग जल प्लावित हो जाते हैं, उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनका कमर टूट जाता है और किसानों का बद से बदत्तर हाल होता जाता है, दूसरे तरफ हम कहते हैं कि जल ही जीवन है और नहरों की स्थिति बिहार के अंदर में दिखाई दे रहा है कि किसी भी नहर में समय पर पानी नहीं छोड़ा जाता है ।

क्रमशः

टर्न-18/सत्येन्द्र/7-3-17

श्री विनोद कुमार सिंह(क्रमशः) बंद पड़े 5000 नलकूप चालू होंगे । यह आपके 12-7-2016 का सामने में आया है, त्रिपुरारि जी प्रधान-सचिव हैं, 12-7-16 को वही थे पता नहीं अभी कौन हैं । उसमें लिखा है कि राज्य में 4301 चालू नलकूप संचालन के लिए बनेगी नयी नीति- प्रधान-सचिव। बंद पड़े 5 हजार नलकूप चालू होंगे। उसमें लिखा हुआ है -लधु जल संसाधन विभाग के प्रधान-सचिव त्रिपुरारि शरण ने कहा कि राजकीय नलकूप योजना के तहत अब राज्य में नये नलकूप नहीं लगाये जायेंगे और पुराने नलकूप को ही ऊर्जान्वित करते हुए उसको चालू किया जायेगा । अपने भाषण में वे चर्चा करेंगे कि आखिरकार सुबे के अन्दर कितने नलकूपों को चालू किया गया । महोदय, आज योजना विकास विभाग पर भी चर्चा है । जो तटबंध को काटा जाता है, जो तटबंध क्षतिग्रस्त होते हैं योजना विकास के माननीय मंत्री जी भी हैं, हम सदन के अन्दर सभी माननीय विधायकों की ओर से अपील करना चाहेंगे कि क्यों नहीं 2 करोड़ को 10 करोड़ किया जाय ताकि उसी से हम मरम्मति मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से उन जगहों पर करा दें। सभापति महोदय, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बिहार के किसानों के लिए, बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए आप ठोस ऐसा कदम उठावें जिससे बिहार के अन्दर में जो बिहार की जनता है वह आपका नाम लें लेकिन आने वाला स्थिति अगर इसी तरह बद से बदतर रहा तो बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी और फिर से इस बिहार के अन्दर में नमो नमो के जिन्दाबाद का उद्घोष होगा ।

श्री आनंद शंकर सिंहः महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे प्रतिपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में अपनी बात रखने का मौका दिया । धन्यवाद इसके लिए भी देना चाहूंगा कि अपने देश में जहां 80 प्रतिशत लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं, ठीक हमारे बिहार की भी सरंचना वैसी ही है और यहां भी ज्यादातर लोग ग्रामीण इलाके में ही बसते हैं और वे कृषि पर आधारित हैं । कृषि कार्य में अगर सबसे बड़ी कोई समस्या कुछ हैं तो वह किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने की समस्या है और इन समस्याओं के निदान के लिए महागठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तेजस्वी जी के अशोक चौधरी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मंत्री श्री ललन सिंह जी के नेतृत्व में कृतसंकल्पित है । जहां एक ओर मार्च 2016 तक राज्य में 29.46 लाख हे0 की सिंचाई क्षमता सृजित की गयी वहीं दूसरी ओर वर्ष 2016-17 के अंत तक 1.18 लाख हे0 अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन करने का

लक्ष्य रखा गया है । बेहतर नहर संचालन के द्वारा वर्ष 2016-17 में 19.31 लाख हे0 क्षेत्र की खरीफ सिंचाई सुविधा प्रदान की गयी । नदी जोड़ योजना के अन्तर्गत कोशी में चिलिंग की योजना पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अनुमति मिलने के बाद इस योजना के कार्यान्वयन से अररिया, किशनगंज और कटिहार में 2.01 लाख हे0 से अधिक क्षेत्र सिंचाई उपलब्ध हो सकेगी । महोदय,मैं औरंगाबाद जिले के औरंगाबाद विधान-सभा क्षेत्र से जीतकर आया हूँ और यह इलाका भी कृषि प्रधान इलाका है । यहां के लोगों की आजीविका कृषि ही है और सिंचाई की व्यवस्था के यह सब नितांत आवश्यकता है । देव, कुटुम्बा, औरंगाबाद, रफीगंज और नवीनगर प्रखंड के किसान सिंचाई की समस्या से त्रस्त हैं । महोदय, 2 परियोजनाएं एक तो उतर कोयल परियोजना और दूसरी है बटाने जलाशय परियोजना । महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने प्रतिपक्ष के साथियों का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री जी का संसदीय चुनाव में उनका भाषण हुआ तो उन्होंने बड़े ही जोश खरोश के साथ यह बतलाया कि मैं तबतक मगध की धरती पर दोबारा नहीं आऊंगा जबतक यहां के किसानों के खेतों में पीला पानी न पहंचा दूं। महोदय, यह बड़ा ही खेद जनक है, वे मगध की धरती पर आये भी लेकिन किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने की बात दोबारा उन्होंने नहीं रखी । आज भी जो योजनाएं हैं, चाहे वह वटाने जलाशय परियोजना हो, उतर कोयल परियोजना हो दोनों ही परियोजनाएं झारखंड सरकार के उदासीन रवैया के कारण लंबित पड़ी है जिससे गया, औरंगाबाद अरवल, जहानाबाद आदि जगहों के 25 लाख से ज्यादा किसान उससे प्रभावित हो रहे हैं। आप सोच सकते हैं हमारा जो इलाका है वह बड़ा ही पिछड़ा इलाका है । देव मदनपुर नक्सलवादी इलाका है अगर किसानों के खेत में पानी पहुंचाया जा सका तो इस इलाके का भी सर्वांगीण विकास हो पाता । महोदय, एक ओर जहां ये किसानों के खेतों में पीला पानी पहुंचाने की बात करते हैं दूसरी ओर जिन किसानों को समय पर खेत में होना चाहिए था नोटबंदी कराकर बैंकों के लाईन में लगा देने का काम किया गया । जिस समय धान की फसल की कटाई हो रही थी किसान अपना धान का फसल उपज को बेचकर दलहन, तिलहन की बुआई के लिए खाद बीज खरीदता उस समय किसानों का समय व्यर्थ कराया गया लाईन में लगाकर तो सबसे बड़ा अगर किसानों का कोई विरोधी हैं तो वह माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी हैं इसमें कहीं कोई दो राय है । महोदय, जिस तरह से तुगलकी फरमान जारी कर के विगत सौ दिन से ऊपर हो चुके हैं आज भी जिस प्रकार किसान त्रस्त है, कहीं से भी उनको किसानों का हितैषी नहीं कहा जा सकता है । महोदय, मैं माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके माध्यम से जगन्नाथ वियर और विशुनपुर वियर का निर्माण औरंगाबाद जिला में हुआ और उससे बहुत सारे किसानों को सिंचाई में लाभ मिलेगा। महोदय,बटाने नदी पर खैराबिन पंचायत के रबीकर ग्राम के पास अगर पक्का चैक डैम का निर्माण कराया जाय

तो वहां के आसपास के दर्जनों गांव के किसानों को सिंचाई की व्यवस्था में लाभ मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने जल संसाधन विभाग के मंत्री को मंत्री महोदय को कि आपदा प्रबंधन के तहत सेंडई फ्रेम वर्क एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 2030 तैयार करने वाला बिहार पहला राज्य बना । इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनको साथ ही उतर कोयल परियोजना के तहत महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यह 1975 से ही योजना लंबित है और स्लुईस गेट जो होता वह न लग पाने के कारण यह योजना बिल्कुल ही अधूरी पड़ी हुई है और देखा जाय तो यह बरसाती नहर बनकर रह गयी है । मीटिंग हुई झारखंड और बिहार के पदाधिकारियों की उसमें यह बात झारखंड के तरफ से आयी कि चार मीटर डैम की ऊंचाई को कम कर दिया जाय उस पर भी बिहार सरकार राजी हो गयी लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों झारखंड सरकार का इस ओर उदासीन रवैया है। मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहूंगा विपक्ष के सदस्यों से कि कम से कम बिहार के किसानों, औरंगावाद के किसानों, गया के किसानों की बदहाली को देखते हुए अपने मुख्यमंत्री रघुबर दास जी से इसके लिए अनुरोध करें ताकि बिहार के किसानों का दुख दर्द दूर हो। महोदय, मुहम्मदगंज बराज भी झारखंड में ही अवस्थित है इनकी सरकार है वहां पर जिस प्रकार से उदासीन रवैया रहता है वहां के सरकार का जिस समय पानी देने का समय होगा उस समय वह तटबंध के जो कार्य होते हैं सुचारू रूप से चलाने के लिए वह काम उसी समय करना शुरू करते हैं जिसके चलते पांच दस दिन लेट हो गया लोगों को पानी देने में। धन्यवाद महोदय।

श्री ललन पासवानः सभापति महोदय,सरकार दावा कर रही है और आज जल संसाधन विभाग का बजट है। मंत्री जी मेरे यहां दुर्गावती जलाशय परियोजना को देखने गये थे और पिछले ध्यानाकर्षण के जवाब में मंत्री जी ने उत्तर भी दिया था कि इस साल 2017 के वित्तीय वर्ष में काम को फाईनल करेंगे, निविदा भी निकाली गयी है और काम प्रारम्भ भी है । (क्रमशः)

टर्न-19/मधुप/07.3.2017

..क्रमशः..

श्री ललन पासवान : लेकिन भू-अर्जन का काम जिस गति से होना चाहिये, उस गति से नहीं हो रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि समय अब मात्र दो महीना बचा है, 15 जून के बाद मिट्टी का कार्य नहीं हो पायेगा और 27-28 वितरणी का काम पूरा करना है, आउटलेट से लेकर सब बनना है । जिस गति से सरकार को काम करना चाहिये उस गति से भू-अर्जन का काम नहीं हुआ । किसान जहॉ-तहॉ काम को रोक रहे हैं, विवाद हो रहा है । आग्रह करेंगे कि सरकार जल्दी बनवा दे और 386 गॉव कैमूर और रोहतास

के लोगों को, किसानों की 30 साल से लंबित परियोजना को पानी मिल जाय । एक सवाल है ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : बस, हो गया न ! समय समाप्त हो रहा है आपका ।

श्री ललन पासवान : दूसरा सवाल कि इन्द्रपुरी जलाशय परियोजना को माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी दोनों गये थे, मेरे ही कंस्टीच्यूयेंसी में दोनों योजना है लेकिन दोनों जगह हमलोगों को नोटिस ही मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी किये कि हमलोग भी साथ पहुँचे । इन्द्रपुरी जलाशय परियोजना बड़ी परियोजना है, चार राज्यों की परियोजना है । शीघ्र काम प्रारंभ हो, सिर्फ देखें नहीं माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : धन्यवाद । अब समाप्त कीजिये ।

श्री ललन पासवान : एक मिनट । सभापति महोदय, दलित के साथ न्याय करिये ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : आपने तो अपनी बात कह दी ।

(व्यवधान)

श्री ललन पासवान : खेतों की पानी के साथ-साथ मेरे यहॉ तो पीने का पानी नहीं मिल रहा है । मेरे यहॉ नौहट्टा से रोहतास सोन सटा हुआ गुजरा है जहॉ नहरें नहीं लगती हैं और 100 गॉव इस बार बाढ़ में लगभग 70-75 प्रतिशत किसानों का, सोन का रूट बदल गया था, क्षतिग्रस्त हुआ किसानों का, बांदू में माननीय मंत्री जी ने एक बनवाया है लेकिन पूरा वहॉ से लेकर डेहरी तक, ऐसे तो बहुत दूर तक है लेकिन तुम्बा से लेकर थुम्बा तक, थुम्बा से लेकर यदुनाथपुर मटिऑव तक जहॉ गये थे, सारे गॉव के कटाव इतने हो गये, कई हजार एकड़ भूमि किसानों की चली गई है । चाहे वह तुम्बा हो, थुम्बा हो, चाहे नारायण चक हो, नाम गिना दें, मिल्की हो, रसूलपूर हो, कुसडियरा हो, यदुनाथपुर हो, बनाही हो, वहॉ से लेकर देवीपुर हो, सिंहपुर हो, बगल में गॉव है कमाल खैरवा, वहॉ सारे गॉव एकदम सट गये हैं, सब गॉव बहकर चले जायेंगे सोन की गोद में । इसलिये माननीय मंत्री जी से कहेंगे कि सुरक्षा दीवाल कराइये नहीं तो किसानों की जान चली जायेगी, 2 हजार हेक्टेयर भूमि चली गई है ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : धन्यवाद, अब आप बैठ जायं । श्री यदुवंश कुमार यादव ।

श्री यदुवंश कुमार यादव : सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग द्वारा लाये गये मॉग के समर्थन में तथा विपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिये खड़ा हूँ ।

महोदय, सृष्टि के लिये जल अहम स्थान रखता है । मानव, पशु-पक्षी या जितने भी जैविक प्राणी हैं, जल के बिना नहीं रह सकते हैं और सच ही कहा गया है कि जल ही जीवन है । रहीम ने कहा -

रहीमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून,
पानी गये न उबरे, मोती मानुष चुन ।

महोदय, बिहार के विभाजन के पश्चात् सारी सम्पदा तो झारखंड में चली गई, बिहार में सिर्फ बचा नदी, पानी और बालू । इस नदी, पानी और बालू को अपना संसाधन मानकर यहाँ की हुकूमत ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पानी का जो कुशल प्रबंधन किया है और उस कुशल प्रबंधन के बल पर राज्य में जो नेपाल से पानी आता है, प्रतिवर्ष तकरीबन 3 हजार करोड़ से अधिक राशि की क्षति पहुँचाने का काम करता है, उसको बचाते हुये खेती के संसाधन के लिये सिंचाई की व्यवस्था करने का काम किया है । माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में आज जो व्यवस्था यह जल संसाधन विभाग की है, इसको दो पक्षों में रखा जाता है । प्रथम पक्ष सिंचाई और दूसरा बाढ़ है, जल निस्सरण ।

राज्य में वृहद् और मध्यम सिंचाई योजना के तहत वर्ष 2016 में 29 लाख 88 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया । वर्ष 2016-17 में 1 लाख 51 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की क्षमता को पुनर्स्थापित करने का काम किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल प्रबंधन में बेहतर नहर संचालन की व्यवस्था से वर्ष 2016-17 में 19 लाख 31 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई सुविधा प्रदान की गई है जो विगत वर्ष की उपलब्धि से 2 लाख 14 हजार हेक्टेयर अधिक है । बिहार में बाढ़ से जो क्षति होती है और उस क्षति को रोकने के लिये राज्य सरकार ने 68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो बाढ़ से प्रभावित है, जो राज्य की भौगोलिक स्थिति का 73 प्रतिशत होता है, मार्च, 2016 तक 446 कि0मी0 भारतीय प्रभाग में तथा 68 कि0मी0 नेपाल प्रभाग में तटबंध निर्माण करवाने का कार्य विभाग के द्वारा किया गया है । 36 लाख 46 हजार हेक्टेयर क्षेत्र जो प्रभावित क्षेत्र है जो प्रभावित क्षेत्र का आधा से अधिक होता है, उसको आज बाढ़ से सुरक्षित करने का काम हमारी महागठबंधन की सरकार ने करने का काम किया है । भागलपुर में चानन नदी पर, मुजफ्फरपुर में बागमती पर और महानंदा पर बाँध निर्माण का काम पूरा कराया जा चुका है और जहाँ लम्बित है उसको करवाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में जो विपक्ष के द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण विभाग के बजट पर कटौती लाना, मेरे समझ से उचित नहीं होता है ।

महोदय, आज मैं इसके अतिरिक्त यह ध्यान दिलाना चाहता हूँ, मैं कोशी क्षेत्र से आता हूँ और कोशी को अगर बाँटा जाय तो तीन भाग में बाँटा जा सकता है । आज की तिथि में जो स्थिति है, एक भाग जो दोनों कोशी तटबंध के अन्दर है, जहाँ कोशी आज विचरण कर रही है और उनको बचाने के लिये जो लाखों लोग अपना त्याग किया है उसका भाग, दूसरा है जो तटबंध से सुरक्षित भाग है तटबंध से बाहर का इलाका और तीसरा एक और दुखिया इलाका है जो तटबंध के किनारे-किनारे एक किलोमीटर से लेकर तीन किलोमीटर की चौड़ाई में बसा हुआ जो भू-भाग है । महोदय, तटबंध के बाहर के लोग आज तटबंध के अन्दर के लोगों के त्याग के चलते वहाँ खुशहाली है, जो

वर्षों से पिछड़ा हुआ इलाका था । उसके बाद भी उनके ऊपर कोशी का खतरा बना रहता है । 2008 की त्रासदी में कई प्रखंड के लोगों को इसका कुप्रभाव भोगना पड़ा था और उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल प्रबंधन से लगभग तमाम लोगों को जो सुरक्षा प्रदान करने का काम हमारी सरकार ने की, यह प्रशंसनीय है, सराहनीय है और उन्होंने कहा था कि कोशी को सुन्दर कोशी बनाने का हम काम करेंगे । उस दिशा में काम भी किया जा रहा है, बहुत काम किया भी गया है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि तटबंध के अन्दर बसे लोगों को पुनः सुन्दर कोशी का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि तटबंध के अन्दर जो बसे लोग हैं उसको भी सुन्दर कोशी का भाग मानकर उनके लिये भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है और इसके लिये मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ ।

...क्रमशः ......

टर्न-20/शंभु/07.03.17

श्री यदुवंश कुमार यादव : क्रमशः.........इसके लिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि तटबंध के अंदर पहले एक ही नेपाल प्रभाग में ये कोशी बराज था, लेकिन आज हमारी सरकार ने तटबंध के अंदर कई महासेतु का निर्माण करने का काम किया है। उसमें कोशी महासेतु और कई योजनाएं लंबित है या उसपर कार्य चल रहा है। कोशी बराज- कोशी महासेतु, बलुआघाट का पुल, डुमरी का पुल और कुरसेला का पुल ये तो खड़ा है और उसके अलावे डगमारा का हाइडल प्रोजेक्ट और फिर सुपौल और बलुआहा घाट के बीच भी एक प्रस्तावित महासेतु है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन तमाम जो महासेतु है जिसका अपना एक गाइड बांध बना हुआ है। गाइड बांध को कोशी बराज के गाइड बांध से कोशी महासेतु के गाइड बांध को और कोशी महासेतु के गाइड बांध को बलुआहा पुल के महासेतु गाइड बांध से मिलाकर के डुमरी और कुरसेला में मिलाकर नदी तल की सफाई की जाय तो जो उसके तटबंध के अंदर कोशी से तबाह और पीडित लोग हैं उनका तो कल्याण होगा ही इसके अलावे कोशी से जो होनेवाली क्षति है और कोशी से जो प्रतिवर्ष खतरा होता है उसका भी स्थायी निदान होगा और साथ ही साथ भविष्य में यह समुद्र से मिलता है, वहां से नेपाल को समुद्री मार्ग भी मिलेगा। ये कोशी क्षेत्र में जो आज कोशी दोनों तटबंध के अंदर 7 कि0मी0 से 27 कि0मी0 की चौड़ाई में जो पूर्वी और पश्चिमी तटबंध है, इस बीच हजारों एकड़ जमीन जो आज कोशी से तबाह और बर्बाद है। वह जमीन उपजाऊ भूखण्ड होगा, वहां के लोग खुशहाल होंगे और दोनों तटबंध अगर बन जाते हैं तो इतनी बड़ी भूभाग की रक्षा होगी। इसलिए महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विषय में बृहत रूप से सरकार के तरफ से यह कार्य

हो ताकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बेहतर कोशी बनाने का जो सपना है, जब तक तटबंध के अंदर के लोगों का नहीं होगा तब तक बेहतर कोशी नहीं बन सकता है। इसलिए बेहतर कोशी बनाने के लिए तटबंध के अंदर भी निर्माण कार्य कराने का काम किया जाय। महोदय, इसके अलावे जो तीसरा भाग है- जो दोनों कोशी तटबंध है, पूर्वी कोशी तटबंध के 14 कि0मी0 से लेकर के नीचे जहां तटबंध समाप्त होता है कोपरिया तक ये 1 कि0मी0 से 3 कि0मी0 का भूभाग जल जमाव से प्रभावित रहता है, जहां सालों भर पानी लगा रहता है। उस इलाके से अगर जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ की जाय तो बहुत बड़ा भूभाग जो उपजाऊ, अति उपजाऊ भूखण्ड है उसकी जल जमाव से मुक्ति होगी और इस इलाके का कल्याण होगा, तमाम बिहार में खुशहाली आने का काम होगा। इसलिए महोदय, मैं यह निवेदन करता हूँ कि इस दिशा में बृहत रूप में, व्यापक रूप में विशेष कृपा करके ये काम करने का काम करें। अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूँ मैं कोशी बीच का वासी हूँ और महासेतु से नीचे जो पंचायत है आज कटाव से ग्रसित है। विकास काम हुआ है, रोड बना है, लेकिन आनेवाले बाढ़ में, बरसात में वह कटने की संभावना बनी हुई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि कोशी महासेतु के नीचे के गाइड बांध से लेकर सिसौनी जो पक्की रोड बना हुआ है वहां तक सुरक्षात्मक कार्य शीघ्र प्रारंभ की जाय। मैं उनके प्रति आभार भी प्रकट करता हूँ कि विगत वर्ष उन्होंने बाढ़ के समय में जो कार्य प्रारंभ किया जिसके चलते जितनी सुविधा मिलनी चाहिए, जो सुरक्षा होनी चाहिए उसमें आंशिक रूप से सफलता मिली। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि बरसात से पहले इन तमाम गांवों को जो परसामा दो पंचायत है या सिसौनी पंचायत है इस पंचायत के लोगों को सुरक्षा देने के लिए अविलंब बाढ़ कटाव निरोधी कार्य प्रारंभ करवाने का काम करेंगे।

सभापति(श्री अशोक कुमार) : अब आप समाप्त करें, लक्ष्मेश्वर राय जी प्रारंभ करें। बोलिये।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : आदरणीय सभापति महोदय, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जिसके चलते जल संसाधन विभाग की बड़ी महत्ता है। ये जल बिहार के महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक संपदा है। जल संसाधन विभाग जो बिहार की वर्तमान स्थिति है उसकी बड़ी महत्ता हो गयी है। बिहार में शराब बन्दी के बाद और सात निश्चय के बाद और कृषि के प्रति लोगों की अपेक्षा बढ़ी है, कृषि को रोजगार के रूप में लोग देख रहे हैं- लगता है कि कृषि अब रोजगार और प्रतिष्ठा का विषय होगा। इसीलिए जल संसाधन विभाग की महत्ता बहुत बढ़ गया है। हम तो माननीय मंत्री जी को जो बजट लाये हैं उसके लिए धन्यवाद भी देते हैं और एक आग्रह करते हैं कि बिहार में शराब बन्दी के बाद एक बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए वह जल संसाधन विभाग की ओर से होना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था यदि बिहार में हो जाय तो देश क्या, दुनिया को भी यह बिहार अन्न देने का काम करेगा। हम आग्रह करेंगे कि आनेवाले समय में बिहार एक मजबूत प्रतिबद्ध,

कर्मशील, मजबूत और कठोर परिश्रम करनेवाले बिहारी होते हैं। हम आग्रह करेंगे कि जो भी आपने प्रस्ताव लाया बजट के लिए वह बहुत अच्छा है इसको और मजबूत किया जाय। एक बड़ी बात है, ये दुर्भाग्य या सौभाग्य जो कहिये कि चुनावी घोषणा के समय में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी जैसे सात निश्चय का कि हम सात निश्चय लागू करेंगे, हम बिहार को अमन चैन देंगे, उस समय भी हमारे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं देश के वे भी घोषणा किये थे कि सिंचाई योजना गांव तक हम ले जायेंगे, गांव के हर नहरों में हम सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, वो वर्ड याद करना चाहिए और खासकर हमको विपक्षी मित्रों से उनको याद कराना चाहिए कि बिहार इस देश का बड़ा हिस्सा है, बिहार देश के राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर, सामाजिक आंदोलन और आर्थिक आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाया है- बिहार का विकास होगा तो देश का विकास होगा, बिहार का विकास होगा तो देश की आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक समरसता और मजबूत होगी। हम आपसे चाहेंगे कि आपलोग बड़ा काम करें और बिहार को सुन्दर अवसर दें। आप केवल घोषणा की बात करते हैं, हंगामा करते हैं यह अच्छा नहीं लगता है। बिहार के लिए आप नाइंसाफी कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि बिहार उन्नत हो, सुंदर बिहार बने तो जो प्रधानमंत्री जी घोषणा किये थे चुनावी समय में उनको लागू करना चाहिए जिससे बिहार का विकास बढ़ेगा और बिहार के विकास के साथ-साथ हमारा इतिहास गौरवान्वित होगा पूरा देश और दुनिया में बढ़ेगा। अभी वर्तमान में जो बजट लाया गया है उसमें बृहत् और मध्यम सिंचाई योजनाओं का, परियोजनाओं का जो 53.53 लाख हेक्टयर सिंचाई क्षमता सृजित होने का अनुमान है। इसके विरूद्ध मार्च, 2016 तक 29.40 लाख हेक्टेयर का सृजन हुआ था, जो मार्च 2017 में बढ़कर 29.69 लाख हेक्टेयर हो जायेगा। वर्ष 2017 और 2018 में 2.977 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन का लक्ष्य है। संरचनाओं और क्षरण नदी प्रणाली में गाद जमा होने के कारण इसकी सिंचाई की क्षमता में स्वाभाविक रूप से ह्रास हुआ है..........क्रमशः।

टर्न-21/अशोक/07.03.17

श्री लक्ष्मेश्वर राय : क्रमशः ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित करना आवश्यक है । 2016-17 में मार्च,17 तक 129.372 हजार हैक्टेयर ह्रसित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापण पूर्ण हो जायेगा । वर्ष 2017-18 में 88.883 हजार हैक्टेयर में ह्रसित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य है । नहरों का भी बेहतर संचालन के कारण सिंचाई क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है । खरीफ मौसम में, खरीफ मौसम में 29.31 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रदान किया गया है जो विगत कई वर्षो का सर्वाधिक हैं, नहर के अंतिम छोर तक निर्वाध रूप से ससमय पानी पहुंचने के उद्येश्य से बिहार

का सम्पोषण नीति तैयार किया जा रहा हैं साथ ही सिंचाई एवं बाढ़ एवं जल निस्सरण कार्य पर उचित ध्यान देने हेतु विभाग को पुनर्गठित किया गया हैं । हम आग्रह करेंगे जो पुनर्गठित किया गया हैं वह बहुत ही बेहतर है, बिहार का यह रहा हैं उत्तर का हिस्सा बाढ़ से प्रभावित रहा हैं जब कि दक्षिण का हिस्सा बिहार का यह सुखाड़ का रहा है, यह विपरीत प्रकृति की संरचना के बावजूद बिहार में आपार सम्भावना हैं, हम चाहेंगे कि बिहार में सुन्दर वातावरण हैं और आने वाला समय में देश का सर्वोत्तम राज्य विकसित करने के लिए हमारे बिहार सरकार ने बजट लाया है । विभाग अपने कार्यो के बेहतर परिणाम के लिये बराबर, लगातार आधुनिक तकनीक का प्रयोग भी करता रहा हैं । बाढ़ प्रबन्धन सुधार सहायता केन्द्र के तहत बाढ़ पुर्वानुमान मॉडल, नेशनल हाईड्रोलॉजी परियोजना, कोशी फ्लड परियोजना, कोशी बेसीन विकास परियोजना का कार्य किया जा रहा हैं, इसके अन्दर क्षमता के विकास के कई कार्यक्रम हैं, एक सेक्टर ऑफ इक्सीलेंस करने का प्रावधान है, इस वर्ष पांच अदद सिंचाई परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा सम्पन्न हुआ है । विभाग कठिन महेंनत एवं सतत् प्रयासके द्वारा उसको और आगे बढ़ाना चाहिये साथ साथ हम कहेंगे कि कोशी बेसीन से पूरा महानन्दा बेसीन के बीच में जो नदी है, उसको जोड़ने का काम किया हैं, इसी रूप में बिहार की जो और नदियां हैं उसको भी जोड़ा जाय । केन्द्र सरकार ने घोषणा की थी कि एक नदी को दूसारे को जोड़ कर सिंचाई में उपयोंग करेंगे, हमारे मित्रों ने, हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आये थे चुनाव के समय आये थे तो बोले थे कि गंगा मईया हमको बनारस में बुलाये हैं, याद करना चाहिए घोषणा को, बिहार का उदाहरण लेना चाहिये देश के लोगों को, चाहे बी.जे.पी. के लोग हों या केन्द्रशासित के लोग हों, आदरणीय नीतीश कुमार जी जो घोषणा किये थे उसको लागू किये हैं, वे अपनी मर्यादा को कायम किये हैं, इस देश में आदरणीय नीतीश जी एक मर्यादा कायम किये हैं, जैसे राम का नाम लेने वाले मर्यादा तोड़ रहे हैं, राम का नाम लेने वाले मर्यादा तोड़ रहे हैं, मर्यादा तो उसका नाम है जो अपने विचार पर प्रबिद्धता के साथ इमानदारी और कठोर परश्रिम से उसको निभाये, आदरणीय नीतीश जी राजनीति को, राजनीति के मर्यादा को बढ़ाये हैं, चुनाव में जो घोषणा किये उनको लागू किये, अथक प्रयास करके बिहार का सुन्दर छवि देश और दुनिया में दिये, दूसरी तरफ जो राम नाम लेकर सत्ता में आते हैं, जो राम की बात करता है, गंगा मईया की बात करता है, वह गंगा के साथ छल करते हैं, गंगा मईया आज सूख रहीं हैं, गंगा मईया फरक्का बांध बनने के बाद, गंगा मईया आज सूख रही है, फरक्का बांध बनने के बाद, फरक्का बराज बनने के बाद गंगा की स्थिति और खराब हो गई । महोदय, हम आग्रह करेंगे गंगा मईया सुरक्षित हो, नीतीश कुमार जी को बहुत धन्यवाद देना

चाहिये, देश में मैसेज दिये हैं गंगा मईया सु रक्षित रहे, अविरल गंगा हो । इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं । माननीय नीतीश कुमार, आदरणीय नीतीश कुमार से सीख लेनी चाहिए देश की राजनीति को कि राजनीति मे मर्यादा बड़ी बात है । और आज यदि आदरणी अटल बिहारी बाजपेयी जी यदि स्वस्थ्य रहते तो इन लागों को देखकर बहुत चिंतित होते कहते कि क्या हो गया बी.ज.पी. का, जिस मर्यादा से बी.ज.पी. को कायम किया था आज वह मर्यादा हंगामा और देश में असत्य बोलने पर निर्भर करते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार : सभापति महोदय, कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, आज माननीय मंत्री जी का जो आंकड़ का जाल हैं, मंत्री जी का जो किताब है और जो छपा है, इनका अभियंता प्रमुख सिंचाई सृजन का जो नौ डिवीजन है और दुर्गावती जलाशय योजना अभी तक पूर्ण नहीं हो सका हैं । हमारे ललन भाई बता रहे थे, उसकी गतिविधि । इनके किताब है कि 2016 का लक्ष्य था 53.53 लाख हैक्टेयर, इसके विरूद्ध पूरा हुआ 29.46 लाख हैक्टेयर और सिंचाई क्षमता, इसका सिंचाई क्षमता हुआ और मार्च,2017 तक इनका हुआ 29.69 (व्यवधान)अरे किताव में छपा है और 2017-18 का अतिरिक्त सिंचाई का.....

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : वह लक्ष्य नहीं है, पूरे बिहार में 53.53 लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित होने की सम्भावना है, लक्ष्य कहां से हो गया ?

श्री प्रमोद कुमार : सम्भावना, वही न बता रहे हैं और 2017-18 में सभापति महोदय, 29.77 और आज 73 प्रतिशत पूरे राज्य के हुजूर, बाढ़ प्रभावित इलाका है (व्यवधान)और अभी हमलोग चम्पारण से आते हैं सभापति महोदय, और चम्पारण जो है सर्वाधिक जल प्रभावित इलाका है और चम्पारण में, आपसे बतला दें, चाहें वह 1971 का बाढ़ हो या 2007-08 का बाढ़ हो हर समय बाढ़ प्रभावित रहता हैं और बाढ़ से बचाव के लिए वहां जो सिकरहना नदी है, नेपाली नदी है और बूढ़ी गंडक है तो वहां के बूढ़ी गंडक सिकरहना नदी और गंडक परियोजना के नहरों के सफाई के लिए नागार्जुन कम्पनी, नागार्जुन कम्पनी को सैकड़ो करोड़ रूपया का टेन्डर दिया गया और यह नगार्जुन कम्पनी मुख्य नहर में काम किया, छोटे वितरणी काम नहीं किया और टोटल काम बैठे बैठे मुम्बई का कम्पनी था वही से पेट्टी कांट्रेक्ट थमा दिया, कहीं 80 प्रतिशत काम हुआ, कहीं 75 प्रतिशत काम हुआ और अभी तक, अभी तक दजर्नो वितरणी, उप-वितरणी को नागार्जुन कम्पनी ने छोड़कर चल दिया है । पता नहीं बिल का, पिछले सत्र में हमलोग उस पर तत्कालीन जल संसाधन मंत्री,अपने वर्त्तमान जो माननीय अध्यक्ष हैं यही थे, इन्होंने गया था और बात सुनिये, बात सुनिये भाई और चम्पारण, मोतिहारी पूरे पूर्वी, पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चमपारण घूम कर आये और मोतिहारी परिसदन में मेरे समक्ष प्रेस कॉफ्रेंस में

नागार्जुन कम्पनी के बारे में बताया, और सैकड़ो करोड़ रूपया नागार्जुन जो हैं वह घोटाला किया और उसके काम में कोई गुणवत्ता - जहां बड़ा बड़ा नहर में पानी जा रहा हैं लेकिन एक जगह से, कही न कहीं से गड़बड़ी हो जा रही हैं । छोटी वितरणी अभी चैलाहसपही वितरणी, भवनीपुर उप -वितरणी, मठियासूर्यपुर वितरणी, यह छोटा छोटा दर्जनों से ज्यादा वितरणी हमारे क्षेत्र के अन्दर का है जिसका काम नागर्जुन ने छोड़कर चला गया तो यह है गंडक विभाग के जो हैं, यह भारत सरकार का ही रूपया था, भारत सरकार ने ही इस योजना को जब तत्कालीन जल संसाधन विभाग के जो मंत्री थी अपने परम आदरणीय डॉ सी.पी. ठाकुर जी उन्हेंने सर्वेक्षण करके योजना बनाया थाऔर उसी समय और इसके दो साल में तो इसका टेन्डर में फैसला हुआ हाईकोर्ट से इस नागार्जुन का । क्रमशः

टर्न-22/आजाद/07.03.2017

.... क्रमशः ......

श्री प्रमोद कुमार : और महोदय इसी प्रकार गंडक प्रोजेक्ट की जो नहरें है, नहरों की जो वर्तमान स्थिति है, मुख्य नहर में पानी गया, छोटे वितरणी में पानी नहीं गया । धनौती नदी जो पश्चिमी चम्पारण से चली है और इस धनौती नदी के सफाई के लिए एक योजना बनी और इसी सदन में उसकी निगरानी विभाग से जॉच बैठायी गयी और जॉच का क्या फल आया, अभी तक स्थिति सामने नहीं आयी । यह धनौती नदी हमारे क्षेत्र में है, हर जगह जब थोड़ा सा भी बाढ़ आता है तो धनौती नदी से पूरा हमलोगों का इलाका तबाही और बर्बाद हो जाता है । यह चनपटिया से निकला है और इसी के साथ सिकरहना जो तटबंध है, उसके बायां भाग और दायां भाग दोनों तटबंध के मरम्मती का भी प्रोजेक्ट बना था और उस प्रोजेक्ट को कहां रखा गया, अभी तक सामने नहीं आया, इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे । दो-तीन बार विधान सभा में उत्तर आया कि इसपर काम होगा, प्रोजेक्ट बना है तो गंगा परियोजना में गया है । यहां गया, वहां गया तो तत्कालीन मंत्री रामाश्रय बाबू थे, उन्होंने कहा था कि हम इस योजना को लागू करायेंगे और इस सिकरहना तटबंध के कारण हमारे क्षेत्र के रमगढ़वा, बनावा, बरदाहा, मधुबनी, ठरगटवा, हसुआहा, हरेराज, बरदाहा, सोनपुर यह सब गांव कटाव के कारण, इन गांवों का बहुत ही बुरा हाल है और किसी समय इस नदी का कहर इतना कड़ा बना हुआ है कि जो नेपाली नदी है, उस समय इसका योजना बना था लगभग 300 करोड़ रू0 का, आज से 5-6 साल पहले की बात कर रहा हूँ । उसी तरह जलनि:स्सरण योजना का भी जो सिकरहना नदी है, इसकी भी योजना बनी थी नदी को सीधा करने का, थोड़ा बहुत काम भी हुआ और कुछ सफाई करके इसका हो गया । नेपाल से तिलावे नदी जो नेपाल

का मुख्य नदी है, दुधौरा नदी, गियर नदी, सुहागवन नदी इन सब नदियों का भी कहर समय-समय पर होता रहता है लेकिन अंग्रेज के समय में इन नदियों का जमींदारी बॉध था, इनका एक अपना बहने का रास्ता था लेकिन इनका जो नहरी पईन है, यहां का जो जगह-जगह सुलिस गेट था, वह सब ध्वस्त होने के कारण इन नदियों का जल का जो स्तर है, उसको संरक्षण, संवर्धन नहीं मिलता है, जिसके कारण समुचित सिंचाई की योजना नहीं बन पाती है । इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी को सुझाव होगा कि इस दिशा में पहल करेंगे, इसका भी जमींदारी बांध है, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है । एक बार मनरेगा से रामाश्रय बाबू के समय में तिलावे नदी के बांध की मरम्मती आप ही के सिंचाई विभाग के इंजीनियर लोग गये थे और योजना बनायी गयी थी और मनरेगा के राशि से बना, लेकिन वह अधूरा रहा ......

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त करें ।

श्री प्रमोद कुमार : वह अधूरा रहा लेकिन अभी तक वह पूर्ण नहीं हुआ । महोदय, नलकूप विभाग के बारे में हाईकोर्ट ने कहा है कि 4954 नलकूप बंद पड़े हैं । यही 12.8.16 को, माननीय मंत्री नहीं हैं लेकिन विजेन्द्र बाबू हैं, वे सुन रहे हैं और हाईकोर्ट ने कहा है कि 4 माह में घाट पर आयेगी गंगा । हाईकोर्ट ने कहा कि 4 माह में गंगा को ले आईए और नहरों के लिए कृषि समिति को देख-रेख के लिए दी जायेगी । अभी तक इसकी योजना जमीन पर नहीं दिखती है । एक हमारे मित्र हैं, इनका नेपाल से सटे हुए अररिया जिला के फारबिसगंज क्षेत्र में पड़ने वाला ख्वासपुर में एक तटबंध है, इसपर तटबंध बनाने के लिए कार्रवाई की जाय ।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं अपने क्षेत्र की बात रखा हूँ, मंत्री महोदय से आग्रह है कि चम्पारण शताब्दी वर्ष मना रहा है और वहां के लिए आपके किताब में कोई योजना नहीं है, इसलिए उसमें कोई न कोई योजना उत्तर में दीजियेगा । इन्हीं शब्दों के साथ होली की शुभकामना देते हुए जयहिन्द, जयभारत ।

श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी : सभापति महोदय, आपके द्वारा अतिमहत्वपूर्ण विषय जलसंसाधन विभाग पर बोलने का अवसर मिला, इसके लिए मैं आपका, महागठबंधन के तमाम नेतागण और कार्यकर्त्तागण और इस सदन का आभारी हूँ । सरकार द्वारा प्रस्तुत जल संसाधन विभाग, वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट के अनुदान मांग के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ । पूरा पृथ्वी लगभग तीन तिहाई जल से घिरा हुआ है और जल ही जीवन है और जल ही प्रलय का कारण है । दोनों का प्रबंधन कर जल संसाधन हमें सिंचाई के लिए जल मुहैय्या कराती है और जब जल का भयावह रूप बाढ़ के रूप में आता है तो उसके जल निष्कासन में जल संसाधन विभाग की विशेष भूमिका होती है । जल बिहार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं आर्थिक सम्पदा है । जल संसाधन पानी का वह श्रोत है, जो मानक के लिए उपयोगी हो सके । हमारा राज्य कृषि प्रधान और

कृषि आधारित प्रदेश होने के कारण आजीविका के साथ समग्र समृद्धि के लिए बेहतर सिंचाई विकसित करने का प्रयास हमारे जल संसाधन विभाग के द्वारा किया जा रहा है । बेहतर सिंचाई से बेहतर खेती होगी और जिससे अच्छी पैदावार होगी । ऊपज उत्पाद अच्छा होगा, जिससे किसान खुशहाल होंगे और बिहार की खेती सिंचाई पर निर्भर है । बिहार सरकार जल संसाधन मंत्री जी के सफल भगीरथ प्रयास से निरंतर बहुत काम, बहुत योजनायें की जा रही है । दूसरी ओर अपने प्रदेश विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण बाढ़ की विभीषिका से जान-माल को सुरक्षा प्रदान करना चुनौती है । इस परिस्थिति में जल का समुचित संरक्षण एवं प्रबंधन विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है । सिंचाई परियोजनाओं का विकास, प्रबंधन एवं संचालन बाढ़ के जल का पलावन से सुरक्षा प्रदान करना, कृषि योग्य जलमग्न क्षेत्रों से जल की निकासी की व्यवस्था करना जल संसाधन विभाग का मुख्य दायित्व है । नहरों के बेहतर संचालन से सिंचाई क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है । बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है । बाढ़ से अतिरिक्त क्षेत्रों मे सुरक्षा प्रदान करने हेतु नये तटबंध का निर्माण किया जा रहा है । विभाग अपने कार्यों में बेहतर परिणाम के लिए अपने कार्यों में तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं । इस साल माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी के कर-कमलों के द्वारा 5 अदद सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है । कई एक्शन प्लान पर कार्य किया जा रहा है । माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर सरकार महागठबंधन सरकार बनने के मात्र एक माह के बाद हमारे क्षेत्र सिकन्दरा में माननीय मंत्री श्री ललन बाबू के द्वारा और सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा हमारे क्षेत्र में बहु चर्चित कुण्ड घाट जलाशय योजना का निरीक्षण किया गया और इसी साल जून में उसका कार्य समाप्त होकर उद्घाटन होगा, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ । इससे सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होगा और किसानों को अच्छी खेती के लिए उत्पादन करने के लिए मैं आग्रह करता हूँ कि उसका कुण्ड घाट का एक मुँह पूरब की तरफ नहर बनाया जाय, जिससे 5 पंचायतों को काफी फायदा होगा, किसानों को काफी फायदा पहुँचेगा । सिकन्दरा में ही बहुआर नदी का कैनाल बन्द है, उसको चालू कराने का मैं इनसे नर्म निवेदन करता हूँ । दूसरा मेरे प्रखंड में अलीगंज घोरघट डैम बनवाया जाय, क्योंकि वहां पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है । अगर यह घोरघट डैम बनाया जाता है तो इससे किसानों को काफी फायदा पहुँचता है ।

...क्रमशः...

टर्न-23 /ज्योति

07-03-2017

क्रमश:

श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी : और दूसरा जो कि दो चार दिन पहले माननीय मंत्री जी के द्वारा कैलाश डैम का पुनर्स्थापना का निर्देश दिया गया है मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि इसपर जल्द से जल्द कार्य शुरु हो । इसके लिए मैं पूरे सिकन्दरा और अलीगंज प्रखंड की तरफ से इनका आभार व्यक्त करता हूँ । खैरा प्रखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, मायाथान पहाड़ी क्यूल नदी से बड़ीबाद तक एक पईन का निर्माण कराया जाय पंजिया डैम का निर्माण कराने से खैरा में लगभग 6 पंचायतों को फायदा होगा । अपर क्यूल जलाशय से ऊपर छिलका निर्माण कराकर कैनाल निकालने से अधिक से अधिक खेतों में पानी पहुंचाया जायेगा जिससे कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में खेतों को पानी पहुंचेगा जिससे लोगों को, किसानों को काफी फायदा होगा । महोदय, जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण योजना पर केन्द्र सरकार द्वारा काफी उपेक्षा की जा रही है। न ही राज्य में बाढ़ जैसी विकराल आपदा को रोकने के लिए जल प्रबंधन विगत में कोई योजनाएं कार्य कर रही है न ही बाढ़ के बाद जल निष्कासन पर केन्द्र सरकार का सहयोग जो मिलना चाहिए राज्य सरकार को वह मिल रहा है । राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से बहुत अच्छा बाढ़ नियंत्रण एवं जल निष्कासन की योजनाओं का सफल कार्य कर रही है । सिंचाई के लिए सफल प्रयास किया जा रहा है और लगभग हमारे जो बिहार में जो हर साल उत्तरी भाग में बाढ़ और दक्षिणी भाग में सुखाड़ दोनों को संतुलित बनाकर बिहार सरकार 2016-17 के कार्य योजनाओं में ऐक्शन प्लान तैयार किया गया है मैं आभार व्यक्त करता हूँ बिहार सरकार की जो कि वित्त वर्ष 2016 -17 में पूर्ण हो चुकी योजनाओं को ये पारित किए हैं और 2017-18 में हमारा क्षेत्र जमुई जिला के सिकन्दरा प्रखंड में कुण्डघाट जलाशय योजना को इसमें लिया गया है और इसमें कार्य समाप्ति की ओर है, समापन की ओर है । मैं इसके लिए बिहार सरकार और माननीय मंत्री जी का दुबारा पुन: आभार व्यक्त करता हूँ और सरकार के द्वारा जो वृहद रुप से जल की योजनाएं चलायी जा रही है और साउथ एशियन वाटर इनीसियेटिव और बिहार कोशी फ्लड रिकवरी योजना का कार्य जो सफलतापूर्वक चल रहा है मैं इसके लिए बिहार सरकार और माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय बिहार , जयहिंद ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): माननीय सदस्या श्रीमती रेखा देवी ।

श्रीमती रेखा देवी : माननीय सभापति महोदय जी, आज आपके माध्यम से सदन में बोलने के लिए मौका मिला है जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद । आज जल संसाधन विभाग के बजट सत्र पर सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ । महोदय, हमारी महागठबंधन

की सरकार ने जल संसाधन विभाग वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित कर किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का काम किया है । महोदय, हमारी महागठबंधन की सरकार बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं को पूरा कर बाढ़ से जान माल को सुरक्षित करने के लिए दृढ़संकल्पित है । महोदय, हमारी सरकार के कार्य काल में मार्च 2016 तक राज्य में 53.53 लाख हेक्टर के विरुद्ध 29.46 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का श्रृजन कर लिया गया है । चालू सत्र में भी 1.18 लाख हेक्टर क्षेत्र को सिंचित करने का लक्ष्य है । महोदय, हमारी सरकार इस वित्तीय वर्ष में कुल 14 योजनाओं पर काम कर रही थी जिसमें सभी योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं । रवाईच रामपुर बराज योजना के उद्घाटन समारोह में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश बाबू, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी बाबू तथा जल संसाधन मंत्री ललन बाबू ने भी एक नये बेला बराज बनाने की भी घोषणा की है जिससे किसानों की काफी भूमि की सिंचाई होगी । महोदय, सरकार किसानों के हित में एक बाढ़ से बचाव एवं जान माल की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है एवं तेजी से काम कर रही है । महोदय, भारत सरकार से हमारी सरकार को अच्छा सहयोग नहीं मिलने के कारण हमें कुछ कठिनाईयॉ होती है अगर भारत सरकार सहयोग करे तो जल संसाधन विभाग एक बाढ़ बचाव क्षेत्र में पूरे भारत में बिहार अपना पहचान बनायेगा । महोदय, चालू वित्तीय वर्ष पिछले दिनों मेरे विधान सभा के धनरुआ प्रखंड में आयी बाढ़ से लगभग मेरे तीन पंचायत पूर्ण एवं सात पंचायत आंशिक रुप से क्षतिग्रस्त थे जिसमें भारत सरकार का कोई सहयोग नहीं मिला जिसके कारण किसानों की फसल क्षति का मुआवजे राशि तथा बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाली राशि भरपूर मात्रा में नहीं मिल सकी है । महोदय, हमारी सरकार ने अपने दम पर बाढ़ पीड़ितो एवं किसानों को सहायता राशि देने का काम किया । महोदय, मोदी जी की सरकार सिर्फ असत्य बातें करती है तथा बिहार सरकार के साथ सौतेलापन व्यवहार करती है । बिहार विधान सभा चुनाव के पहले उन्होंने जितना पैसा देने की बात कही थी उतनी राशि भी अगर देती तो बिहार सबसे आगे रहता । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हमारी महागठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, सोनिया जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है । जो भी चुनाव में घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है आज धरती पर उतारने का काम किया है । जो शराबबंदी की है उसके कारण सब हर घर में महिला शांति के माहौल में जीने का काम कर रही है। जो भी मानव श्रृंखला के पूरे बिहार में जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा उससे चार गुणा आगे तक पूरे बिहार के वासियों ने कर दिखाया है । मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार में जितने भी काम हो रहे हैं

वह सब सराहनीय हैं । कम बोलना ज्यादा समझना मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और आपने हमें बोलने का मौका दिया उसके लिए आपके प्रति मैं आभारी हूँ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार) : धन्यवाद । माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम दो मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे ।

श्री सत्यदेव राम : सभापति महोदय, जल संसाधन विभाग पर एवं लघु जल संसाधन विभाग पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ । महोदय, कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल निश्चित तथा सीमित है । बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादकता बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि कृषि योग्य भूमि सीमित है । कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसल सघनता बढ़ाने की जरुरत है।

फसल सघनता बढ़ाने के लिए सिंचाई सक्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है । महोदय, ये बातें सैद्धान्तिक और साहित्यिक है लेकिन हम जब देखते हैं तो हमको लगता है कि ऊंची मकान और फीकी पकवान जैसे लगता है । गांव में जो सिंचाई के साधन हैं महोदय, वह देखकर बातें नहीं पचती हैं । बिहार का सच क्या है ? सच तो दूसरा है कि धान की रोपनी के समय में हम अष्टजाम गाते हैं हरे रामा, हरे रामा, हरे रामा ।

क्रमशः

टर्न-24/07.3.2017/बिपिन

श्री सत्यदेव राम: क्रमशः और कहीं नमो, नमो, नमो, नमो होता है । महोदय, इससे कृषि का विकास नहीं हो सकता है । हमारी कृषि भगवान के भरोसे हो गई है महोदय, जल संसाधन के अभाव के कारण । सरकार आंकड़ों के भ्रमजाल में बिहार की जनता को और सदन को भी गुमराह कर रही है । आंकड़ों का जाल बिछाना छोड़ना चाहिए और सत्य से मुँह मत मोड़िये । मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, सीवान का ही एक रिपोर्ट बताना चाहता हूं कि अभी सीवान में, खासकर छपरा नहर प्रमण्डल, मैरवां में आज 2014-15 में निविदा हुआ महोदय । दो-दो निवदाएं हुई ...

सभापति (डा0अशोक कुमार): आप एक मिनट में पूरा कीजिए । समय समाप्त हो रहा है ।

श्री सत्यदेव राम: और आज वह समुचित रूप से बंद है महोदय । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप जो सिंचाई क्षमता का आंकड़ा दिए हैं, वह असत्य है । सत्य तो यह है कि आपने इस प्रमंडल में निविदा करके काम ही नहीं कराया है तो सारी जमीन सिंचाई क्षमता से बाहर है महोदय । इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि विभागीय पत्रांक 187 दिनांक 26.7.2016 के द्वारा कार्य पूर्ण रूप से जो बंद कर दिया गया है, मैं आग्रह करता हूं कि इसको चालु कराने का आप अपने भाषण में आदेश कर देंगे ।

महोदय, थोड़ा-सा और सुन लिया जाए । महोदय, मैं सीवान के लघु जल संसाधन के बारे में बताना चाहता हूं । यह रेकर्ड है महोदय । जितने नाम की योजनाएं, ट्यूबवेल से लेकर उद्वह योजना तक, जेनरेटर से, सारी योजनाएं एक तरफ से बंद है महोदय । आप देखेंगे, सारा दिखाई पड़ता है । कैसे सिंचाई होगी और किसानों की हालत जर्जर हो गई है । केन्द्र सरकार लगातार डिजल की कीमत बढ़ा रही है और किसानों की माली हालत होते जा रही है । कृषि की खेती घाटे का सौदा बन गई है महोदय । इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि आपकी योजनाएं जो बंद पड़ी है, बड़ी बारीक तरीका से इसमें भी अधिकारी लोगो ने लिखा है, विभिन्न कारणों से, एक बार वह नहीं कह रहे हैं कि सभी टयूबवेल, सारे उद्वह योजनाएं बंद हैं । एक बार नहीं कह रहे हैं, गिनती गिना रहे हैं कि विभिन्न कारणों से, किस दोष से, किस दोष से, किस दोष से, और हम उठा कर देखते हैं तो देखते हैं कि सारी-की-सारी योजनाएं बंद हैं । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आंकड़ों के भ्रमजाल से बिहार को मुक्त करने की जरूरत है और सही बातों को बिहार की जनता के सामने लाने की जरूरत है महोदय ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): समाप्त कीजिए न !

श्री सत्यदेव राम: अच्छे दिन जुमला बन गया और सामाजिक न्याय भी जुमला बन जाएगा तो यह चिंता का विषय है महोदय । चूंकि बिहार जैसे प्रदेश में जहां गरीबी रेखा के नीचे बड़े पैमाने पर लोग रहते हैं, सरकार की जवाबदेही है कि वह अच्छे दिन की तरह सामाजिक न्याय को भी जुमला नहीं बनावें ।

मैं इन्हीं बातों के साथ माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हुए कि सीवान जिले की जितनी योजनाएं हैं उसको तत्काल लागू करने का काम करेंगे । इन्हीं बातों क साथ अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार):धन्यवाद । माननीय सदस्य राजू तिवारी ।

श्री राजू तिवारी : धन्यवाद महोदय । मैं सरकार और सरकार के आदरणीय मंत्री का ध्यान अपने विधानसभा क्षेत्र गोविन्दगंज, मोतिहारी जिला में पड़ता है, वहां ले जाना चाहता हूं । हमारे यहां 2001 में बाढ़ आई थी, उसमें नगदाहा तटबंध टूट गया था और नगदाहा तटबंध के टूटने के कारण वहां एक गांव पूरी तरह नदी के बीच में विलीन हो गया था । आज भी उस गांव के लोग अगल-बगल रोड के किनारे बसे हैं । बहुत बड़ा गांव था महोदय लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुधि नहीं ली गई । मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि उस गांव के जो विस्थापित लोग हैं, सखवा गांव नाम है उसका, उस गांव के लोगों के बारे में सरकार सुधि ले ।

दूसरी बात है महोदय कि वह गांव टूट गया तो सिंचाई के लिए प्रतिबद्ध जो महागठबंधन की सरकार है, उसके ठीक बगल से एक छोटी नहर गुजरती थी, उसी नहर पर बीच में लगभग चार सौ मीटर उसपर बांध बना दिया गया । मैं आगे

भी, इसके पहले भी इस सदन में मामला को उठाया है, चार सौ मीटर का नहर जो बांध बांध दिया गया उस पर, उसके आगे जो सिंचाई की व्यवस्था है, लगभग 10-12 गांव में, उससे टोटल सिंचाई बाधित है । मैं आपके माध्यम से सरकार से और सरकार के मंत्री से आग्रह करूंगा कि उस नहर को चार सौ मीटर बगल में कहीं जमीन लेकर उस पुरानी नहर से जो 10-12 गांव में सिंचाई होता है तो उसको सुचारू करने के लिए कोई व्यवस्था सरकार करे । वहां के किसानों की हालत बहुत खराब है ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, चूंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र 24-25 किलोमीटर है, हमको लगता है कि 30कि0मी0 गंडक तटबंध से लगा हुआ है, बीच में सरकार द्वारा नहर पर ईटीकरण किया गया है लेकिन बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अब तो नहीं लग रहा है कि वहां ईट का नाम है, इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि उसपर कालीकरण की व्यवस्था कराई जाए जिससे आने-जाने के साथ-साथ बांध का रख-रखाव भी हो । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । जयहिन्द ।

श्री नीरज कुमार : माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद । खासकर महागठबंधन सरकार के मुखिया लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार और महागठबंधन के हमारे नेता बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री साथी तेजस्वी यादव और हमलोगों के आदरणीय नेता आदरणीय श्री लालु प्रसाद जी और कांग्रेस के सभी साथियों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है ।

महोदय, जल संसाधन विभाग के बजट सत्र 2017 के राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण के समर्थन में और विपक्ष के द्वारा कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । हम सभी अनुदान मांग के समर्थन में खड़े हुए हैं । आपका आभार प्रकट करते हैं ।

महोदय, हमारे पहले के सभी वक्ताओं द्वारा जितनी बातें कही गई है, इनके द्वारा, पक्ष और विपक्ष में, हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं लेकिन मेरा 14 से 15 महीना का जो विधायी कार्य हुआ है और हमलोगों ने विधायक के तौर पर पहली बार अपने निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ को देखा है काफी नजदीक से और ऐसा संवेदनशील सरकार, इतने उम्र में हमने नहीं देखा आज तक । लोग कहते हैं, हमारे विपक्ष के साथी चले गए, भाषण देकर निकल जाते हैं । इनके नेता अटल बिहारी बाजपेयी बराबर दुश्यंत का कविता पढ़ते थे हंगामा करना मेरा मकसद नहीं है, हंगामा करके बाहर निकल जाते हैं । इन्होंने कहा कि हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, हेलीकॉप्टर के द्वारा सर्वेक्षण किया गया । मैं गवाह हूं पांच घंटा सड़क मार्ग से गांव, गली और बांध और खेत-खलिहानों पर बिहार के मुख्यमंत्री पांच घंटा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में घूमने का काम किया है । हम उनका आभार प्रकट करते हैं बरारी विधान सभा की तरफ से ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इतिहास रचा है । विधायक के तौर पर भी हमको ऐसा लगता था कि भारी जनाक्रोश होगा भयंकर बाढ़ के कारण और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से सीधा संवाद अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के साथ किया था, यह अपने आप में... क्रमशः

..... क्रमशः .....

टर्न-25/कृष्ण/07.03.2017

श्री नीरज कुमार (क्रमशः) लेकिन अब जब हम अपने क्षेत्र में घूमते हैं तो जिस तरह से लोगों का अभिवादन, जिस तरह से स्वीकारिता बढ़ी है, माननीय मुख्यमंत्री जी हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं और उसके बाद बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री आदरणीय ललन बाबू, आपके प्रति हम विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं कि आपने जो काम किया है बरारी विधान सभा क्षेत्र में वह आजादी के बाद आज तक किसी सरकार ने उस जिला में नहीं किया है । हमारे साथी श्री विनोद कुमार जी चले गये, उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाया है हमारी सरकार पर । उन्होंने कहा कि 2010 में जब नीतीश कुमार जी थे और आज जो नीतीश कुमार हैं, वह नीतीश कुमार नहीं हैं । आप के साथ जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, उस समय तक ठीक थे । जब आपने कहा कि राम मंदिर हम बनायेंगे और तारीख नहीं बतायेंगे, तब जा कर आप को नीतीश कुमार जी ने छोड़ा । आप यह कह कर ले गये थे कि अटल बिहारी बाजपेयी जी ने कहा था नरेन्द्र मोदी जी को, आपके प्रधानमंत्री तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री को कि राजधर्म आपने नहीं निभाया । यह दौर था और भारतीय जनता पार्टी उस दौर से निकल चुकी है और आज धरना प्रदर्शन न जाने क्या-क्या । सदन के अंदर कुछ, मीडिया के आगे कुछ, सदन को चलने नहीं देते, 11 करोड़ जनता का प्रश्नकाल लगातार बाधित करते हैं और जो जनसरोकार से विषय जुड़े हैं, जो बिहार के ज्वलंत सवाल हैं, आप अपने कलेजा पर हाथ रख कर पूछिये, आपका भी सवाल है, आपको चूकि दिल्ली से प्रेसर रहता है कि हंगामा करो, यू0पी0 में चुनाव है, सदन को चलने मत दो और जिस तरह से आपने सदन को बाधित किया है । हमारे साथी ने कहा कि बिहार की जनता आप को माफ नहीं करेगी। बिहार की जनता अब आप को माफ नहीं करेगी । आपने जिस तरह से सदन को बाधित किया है और 11 करोड़ जनता के जनहित के सवाल को आपने उससे उसे विमुख किया है, बिहार की

जनता यह सारी चीजों को देख रही है, आपको देख रही है, आपने जो काम किया है, कुकर्म किया है, आनेवाले दिनों में चुनाव में आप को पता चलेगा कि आप कहां खड़े हैं और महागठबंधन की सरकार कहां खडी है ।

(व्यवधान)

बिहार का सर ऊंचा हुआ है, माननीय श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, महागठबंधन की सरकार में । भारत ही नहीं, दुनियां में यह पहली ऐसी सरकार है, जो कहा, सो किया, 14 महीने में 7 निश्चय को सरजमीं पर उतार कर दिखानेवाली पहली सरकार आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रही है । साथ ही, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में काम कर रही है और यह जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है आदरणीय नीतीश कुमार जी का निश्चय का परिणाम आईने की तरह दिख रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन का तीन गुणा से ज्यादा बजट बिहार का बढ़ा कर यह साबित किया है कि यह सरकार कितनी चिन्तित है । आप के नेता ने कहा था कि नदी जोड़ योजना हम लायेंगे । लेकिन आप ने नहीं लाया, हम बधााई देते हैं ललन जी को और मुख्यमंत्री जी को, साथ ही, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कि आपने नदी जोड़ योजना के माध्यम से कोसी लिंक, मेची लिंक को स्वीकृत कराया है । अभी हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं आसन पर, शायद इनके कार्यकाल से यह योजना की शुरू हुई थी । यह मील का पत्थर साबित होगा पूर्णियां प्रमंडल के वासियों के लिये, खेत-खलिहान में रहनेवाले लोगों के लिये । साथ ही, मुझे बताते हुये हर्ष हो रहा है, हमारे गांव में, हमारे इलाके में लोग बोलते थे कि शहर बसे देवता, गांव बसे लोग, टोला टापर वो बसे, ना मानुष, ना लोग । आज बांधों पर सड़कों का जो जाल बिछाया है जल संसाधन विभाग ने, जो स्वीकृति दिलायी है ललन बाबू ने । आज गांवों में लोग बसने के लिये बेताब हैं । वहां घर-घर बिजली पहुंच रही है । बिजली के पोल गाड़े जा रहे हैं । सड़कों का जाल बिछया जा रहा है । आप ने बाजपेयी जी के सपनों को चकनाचूर किया । भारत सरकार की यही एक योजना थी प्रधानमंत्री सड़क योजना । उसको भी आपने 60/40 का अनुपात कर दिया । हमको तो शायद पूरी जानकारी नहीं है लेकिन दावे के साथ कहते हैं कि सिंचाई विभाग ही एक ऐसा विभाग है, जो बिहार में ऊपर कर आया है कि बांधों पर पक्की सड़कों के निर्माण की स्वीकृति इस बार से देना शुरू कर दिया है । बांध पर बसे लोग, चलिये, जब वहां सड़कों पर रॉलर चलेगा, जब बांधों पर पीच बनना शुरू होगा तब आपको पता चलेगा, जब आपको लोग इगनोर करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य नीरज जी, बोल तो अच्छा रहे हैं लेकिन अब समाप्त कीजिये । अब आधा मिनट में आप खत्म कीजिये ।

श्री नीरज कुमार : जी अच्छा । पूर्णियां जिला के धमदाहा प्रखंड के किशनटोली के पास एक कोसी नदी है। 1987 के बाढ़ में उसका मुंह बंद हो गया, जिसके कारण वह ब्रैन्डी नदी के

तरफ मुड़ गया है, उसके कारण समेली, बरारी, फलका के साईड में केला के खेतों में बाढ़ का पानी आ जाता है । हम माननीय मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करेंगे कि उसका मुंह खोलवा दिया जाय । दूसरा, कुरसैला प्रखंड के कटरिया गांव में बांध का ऊंचीकरण और बांध पर सड़क का निर्माण कराया जाय । तीसरा, समेली प्रखंड के डुमर पुल के पास ब्रैन्डी नदी के किनारे ....

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री नीरज कुमार : आधा मिनट । बरारी प्रखंड के हासीमपुर के पास ब्रैन्डी नदी का कटाव हो रहा है, वह करवा दिया जाय।

महोदय, हम विपक्ष के साथियों से कहना चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, साथ ही, तेजस्वी यादव एवं ललन बाबू का जिन्होंने बता दिया है कि देश की चुनौती को अवसर में कैसे बदला जाता है । यह जल संसाधन विभाग ने साबित किया है । बहुत-बहुत धन्यवाद । जय महागठबंधन, जय बिहार ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री,जल संसाधन विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 18 माननीय सदस्यों ने जल संसाधान विभाग की अनुदान की मांग पर चर्चा में भाग लिया । मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनको भरोसा दिलाता हूं कि जो भी रचनात्मक सुझाव उन्होंने दिये हैं, आगे जल संसाधन विभाग जब काम करेगा तो उन रचनात्मक सुझावों पर निश्चित तौर पर ध्यान देकर आगे बढ़ेगा । लेकिन उसके साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया । महोदय, हमलोगों को कभी-कभी लगता है कि कटौती का प्रस्ताव पेश करने पर तथ्यहीन बातें नहीं बोलनी चाहिये । कोई बात कहिये तो तथ्यों पर आधारित बात कहिये । इन्होंने कहा कि जल संसाधन विभाग में पैसा खर्च नहीं होता है। मेरे पास 6 सालों का आंकड़ा है, जो पैसा खर्च होने का और जो आऊट-ले है, उस आउट-ले का कितना परसेंटेज खर्च हुआ, हम 6 सालों का खर्च नहीं बतायेंगे क्योंकि उसमें फिर ये कहेंगे कि तीन साल हम्हीं थे उसमें, 2013 तक तो मेरे समय में भी हुआ । इसलिए हम उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे । हम अंतिम दो साल के खर्च का हिसाब बता देते हैं । महोदय, 2014-15 में हन्डरेड परसेंट खर्च हुआ, 2015-16 में 96 प्रतिशत खर्च हुआ । क्या बात कर रहे हैं ? हम दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं कि जल संसाधन विभाग के अधीन तीन योजनायें हैं, जो भारत सरकार से अनुदान पर

चलती है । एक योजना है ए0आई0बी0पी0, जिसमें 50 प्रतिशत भारत सरकार देती है । हम ए0आई0बी0पी0 में पैसा खर्च कर चुके हैं । लेकिन भारत सरकार अपने हिस्से का 632.21 करोड़ आज की तारीख में भी भारत सरकार के पास बकाया है । भारत सरकार नहीं दे रही है । आर0एम0ए0डब्ल्यू0बी0एफ0 योजना है, जो हम नेपाल प्रभाग में काम कराते हैं उसमें 100 फीसदी भारत सरकार को देना है । उसमें भी हम काम करा चुके है और आज भी हमारा 66.78 करोड़ रूपया भारत सरकार के पास बकाया है, देने का नाम भारत सरकार नहीं ले रही है । फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम जो हम बाढ़ नियंत्रण के लिये काम करते हैं । भारत सरकार को उसमें 50 प्रतिशत पैसा देना है । फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम का काम हम करा चुके हैं, भारत सरकार से स्वीकृत होने के बाद । 248.96 करोड़ रूपया मेरा आज भी बकाया है, भारत सरकार नहीं दे रही है । कुल मिलाकर 947.90 करोड़ रूपया मेरा आज की तारीख में भी भारत सरकार के यहां बकाया है । अरूण बाबू, आप खर्च की बात कर रहे हैं । हम तो खर्च करके बैठे हुये हैं । पैसा मांग रहे हैं, मिल नहीं रहा है । इसलिए तथ्यों पर आधारित बात करनी चाहिए। कई माननीय सदस्यों ने और भी सवाल उठाये हैं, सोन नहर के बारे में, आगे हम चर्चा करेंगे तो उस पर हम उनको बतायेंगे, विनोद जी चले गये थे, बीच में गायब हो गये थे, ये कह रहे थे कि 1971 में पटना में बाढ़ आई थी, 1971 में नहीं 1975 में बाढ़ आई थी । अपने आप को करेक्ट कर लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं ईमानदारी के साथ स्वीकार करता हूं कि सिंचाई सृजन के क्षेत्र में जितनी हमारी संभावनायें हैं, उन संभावनाओं पर हम पूरी तरह काम नहीं कर पाये हैं ।

क्रमश :

टर्न-26/राजेश/7.3.17

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री, क्रमशः- हमारे पास जो संभावना है, 53.53 लाख हेक्टेयर में हमारी संभावना है, जहॉं हमको सिंचाई क्षमता सृजित करनी है लेकिन हम उसमें मात्र 29.69 लाख हेक्टेयर में ही कर पाये हैं, 50 प्रतिशत से थोड़ा सा ज्यादा, उसमें भी जो नहर की स्थिति है, नदियों में जो गाद आता है, उस गाद के कारण जो नहरों में सिल्टेशन हुआ है उसके कारण 8.46 लाख हेक्टेयर में हमारी क्षमता जो विकसित क्षमता है 29.69, उसमें से 8.46 लाख हेक्टेयर में हमारी क्षमता ह्रासित हुई है, सिंचाई विभाग में सिंचाई के क्षेत्र में जो काम होना चाहिए था, वह पूरे तौर पर काम नहीं हुआ और इसलिए हमने बताया, पिछली बार भी अनुदान मांग की चर्चा के दौरान, हमने कहा था और जब पहली बार 2015 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पदभार सॅंभाला, तो पहली बार उन्होंने जो हर विभागों की समीक्षा की, उसमें 15

दिसम्बर, 2015 को उन्होंने जल संसाधन विभाग की समीक्षा की थी और उस समीक्षा के दौरान ही उन्होंने निदेश दिया था और आदेश दिया था जल संसाधन विभाग को कि सिंचाई के क्षेत्र में जल संसाधन विभाग काम करें, क्योंकि पहले जो स्थिति थी, उसमें बाढ़ और सिंचाई दोनों का काम एक ही पदाधिकारी करते थे और सालों भर वे बाढ़ में पड़े रहते थे और उसके कारण सिंचाई का काम प्रभावित होता था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको पृथक कीजिये और दिनांक 1.6.2016 से हमलोगों ने पूरे विभाग को अभियंता प्रमुख से लेकर और प्रमंडल के क्लास थ्री तक के इम्प्लाई का बँटवारा कर दिया और 1.6.2016 से हमलोगों ने इसे कार्यान्वित किया और इसका हमको लाभ मिला 2016 के बाढ़ में, 2016 के बाढ़ की स्थिति को हम बतावें अध्यक्ष महोदय, तो जितनी हमारी मुख्य नदियाँ हैं, गंडक है, कोशी है, सोन है, कोई भी नदी ऐसी नहीं थी जिसमें उच्चतम स्तर पर जलश्राव नहीं आया, कोशी नदी में तो 2 लाख से 3 लाख क्यूसेक के बीच तीन-तीन, चार-चार बार नदी का जलश्राव आया, गंडक नदी में साढ़े चार लाख क्यूसेक का जलश्राव आया, एक हमारा वाल्मीकिनगर जो बराज है, उसपर दबाव भी पड़ा और दबाव के कारण हमारा एक गेट ध्वस्त भी हुआ, हालाँकि उस गेट को हमलोगों ने समय रहते नियंत्रित किया, उसको बचाने का काम किया और वहाँ पर नया गेट लगा देने का काम किया, इसलिए गंडक नदी की वही स्थिति थी, फिर सोन नदी में 12 लाख क्यूसेक तक पानी आया और जब 12 लाख क्यूसेक पानी सोन नदी में आया लेकिन इन सारे के बावजूद पूरे प्रदेश के अंदर हमारा एक ईंच भी तटबंध नहीं टूटा, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और उसका कारण है कि बाढ़ नियंत्रण और जल निस्सरण से संबंधित जितने अभियंता थे, वे 24 घंटा बाँधों की निगरानी में लगे रहे, रात-रात भर उसका पेट्रोलिंग करते रहे, अगर कहीं कोई दबाव हुआ, तो हमलोगों को सूचित करने का काम उनलोगों ने किया । हाँ, एक बाढ़ आयी, मध्य बिहार में बाढ़ आयी और मध्य बिहार में जो बाढ़ आयी, उसके लिए गंगा नदी में जो जलश्राव था, वह उसका कारण बना, 32 लाख क्यूसेक गंगा नदी का जलश्राव था, इस बार रिकार्ड किया गया, कई जगह पर हमलोगों ने चर्चा की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको इन्टर स्टेट कौंसिल से लेकर यहाँ कई बार इस सवाल को उठाया कि जो फरक्का में बराज बना है, उस बराज के कारण अध्यक्ष महोदय हमारी समस्या आज बढ़ती जा रही है, फरक्का बराज के अप-स्टीम में आप जैसे-जैसे बढ़ियेगा, वैसे-वैसे गाद की समस्या बढ़ रही है, इसका कारण है, इस बार हमलोगों ने अध्ययन किया, हमारा गाँधी घाट में हाई फ्लड लेवेल जो एच0एफ0एल0 है, 20 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर क्रॉस कर गया, भागलपुर में 22 सेंटीमीटर क्रॉस कर गया, इसका क्या कारण है ? इसका हमलोगों ने अध्ययन किया कि बक्सर से पटना की दूरी है 110 किलोमीटर, बक्सर से पटना गंगा नदी का पानी पहुंच जा रहा है दो से तीन घंटे में और भागलपुर से फरक्का की दूरी है 170

किलोमीटर और पानी पहुंचने में लग रहा है 22 घंटा, 23 घंटा, क्या कारण है ? हमलोगों ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद हमलोगों ने देखा कि जैसे-जैसे फरक्का के अपस्ट्रीम की ओर आप बढ़ रहे हैं, वह गाद बढ़ता जा रहा है और वह गाद बढ़ने के कारण आने वाले समय में हमारी समस्या और बढ़ने वाली है, अगर उस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया । अब एक बार फिर शुरु हो गया, बीच में बंद हो गया था, फिर अभी भुक-भुकाया है, भारत सरकार उसमें नेशनल वाटर वेज बना रही है, अरे भाई नेशनल वाटर वेज आप बनाईयेगा और जब नेशनल वाटर वेज बनाईयेगा, जगह-जगह गंगा नदी को तालाब में कन्वर्ट कर दीजियेगा, तो गंगा नदी की समस्या और बढ़ेगी न, घटेगी कहाँ से ? आने वाले समय में और हमने पिछली बार भी कहा था, कई माननीय सदस्यों ने इसपर ध्यान दिया होगा, हमने पिछली बार भी कहा था कि नेशनल वाटर वेज हम नहीं बनाने देंगे और उसके लिए अगर आवश्यक होगा, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा करके मुकदमा भी लड़ेंगे लेकिन हम गंगा नदी के साथ और बिहार के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देंगे । तो यह स्थिति है । गंगा नदी की बाढ़ के कारण हमारा 12 जिला प्रभावित हुआ, जो गंगा के किनारे का क्षेत्र है, वह 12 जिला प्रभावित हुआ और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि गंगा नदी की गहराई घट गयी और जब गंगा नदी की गहराई घट गयी, तो कम पानी में भी वह छिछला हो जा रहा है, फैल जा रहा है, क्या कारण है कि हमारा बक्सर का एच0एफ0एल0 नहीं बढ़ा, क्या कारण है कि हमारा पटना का एच0एफ0एल0 बढ़ गया, क्या कारण है कि हमारा भागलपुर का एच0एफ0एल0 नहीं बढ़ा, ये क्या बात करते हैं ? फरक्का का बराज, भारत सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, फरक्का का बराज जो बना है, वह 27 लाख क्यूसेक पर डिजाईन किया हुआ है, हमारा राजेन्द्र सेतु जो मोकामा का पुल है, वह 30 लाख क्यूसेक पर डिजाईन किया हुआ है और गंगा का पानी था 32 लाख क्यूसेक तो कहाँ से निकलेगा पानी और हाथीदह में एच0एफ0एल0 नहीं बढ़ा, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा जो राजेन्द्र सेतु है, वह 30 लाख क्यूसेक पर डिजाईन किया हुआ है, 32 लाख क्यूसेक पानी था, जो धड़-धड़ पानी निकल जा रहा था, आज फरक्का में 109 गेट में अधिकांश गेट काम नहीं कर रहे हैं, तो यह सारी समस्या है, इसलिए अब और हम गंगा नदी के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति केन्द्र सरकार को नहीं देंगे, क्योंकि हमारे लिए राज्यहित सर्वोपरि है और राज्यहित में हमें जहाँ तक जाना होगा, हमलोग वहाँ तक जाने का काम करेंगे । अभी गंगा की अविरलता पर पटना में जल संसाधन विभाग ने एक सेमिनार किया और इस सेमिनार में इस क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, श्री चण्डी प्रसाद भट्ट जी, ये पद्म भूषण से सम्मानित हैं, जल पुरुष श्री राजेन्द्र सिंह जी, श्रीमती वंदना शिवा, श्री जयंत बंद्योपाध्याय, श्री भरत झुनझुनवाला और श्री बलवीर सिंह सुरजेवाला जी, ये सारे लोग आये पूरे देश से और

दुनियॉं के कई देशों से,जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, सब लोग आये, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेषज्ञों से आग्रह किया कि भाई मेरी बात मत मानिये, मैं कह रहा हूँ कि गंगा में गाद जमा है, गंगा की गहराई घटी है, आप मेरी बात मत मानिये लेकिन आपलोग खुद जा करके बक्सर से फरक्का तक देख लीजिये कि गंगा में गाद जमा है कि नहीं, गंगा जी की गहराई घटी है कि नहीं, सभी लोग गये सुबह 8 बजे, सभी लोग हेलिकॉप्टर से, प्लेन से गये और उन लोगों ने बक्सर से फरक्का तक गंगा का निरीक्षण किया और आने के बाद उनलोगों ने कहा कि गंगा नदी और जो उसका किनारा है, वह कई जगहों पर बराबर हो चुका है और अगर इसपर काम नहीं हुआ, तो आने वाले समय में बिहार में भयानक स्थिति पैदा होगी, यह विशेषज्ञों ने माना है, इसको विशेषज्ञों ने स्वीकार किया है, आज डॉलफिन की समस्या बनी हुई है, आज गंगा नदी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आज डॉलफिन जैसी प्रजाति लुप्त हो रही है और आने वाले समय में यह बिल्कुल ही विलुप्त हो जायगी, इसलिए आने वाले समय में जैसा मैंने कहा कि आने वाले दिनों में इसकी अनुमति नहीं देंगे और हमलोगों को इसके लिए जहॉं तक लड़ाई लड़नी होगी, हमलोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और हमलोग मुकदमा भी करने का काम करेंगे । इसके लिए जो तैयारी होती है, उसके लिए हमारा विभाग तैयारी कर रहा है, हमारा विभाग उसपर काम कर रहा है । इसके अलावा बाढ़ 2017 के लिए भी हम बता देना चाहते हैं कि बाढ़ 2017 के लिए जो तैयारी हमलोगों ने किया है, राज्य योजना से हमलोगों ने 249 योजनाओं की स्वीकृति दी है, जो 432.28 करोड़, बाढ़ प्रबंधन के तहत चार योजनाओं की स्वीकृति दी है 370.69 करोड़ का ।

क्रमश:

टर्न-27/सत्येन्द्र/7-3-17

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री(क्रमश:) आर0एम0ए0डब्लू0बी0ए0 के तहत हमलोगों ने 14 योजनाओं की स्वीकृति दी है 103.92 करोड़ और आपदा निधि से हमलोगों ने 50 योजनाओं की स्वीकृति दी है 299.93 करोड़। कुल 317 योजनाओं की स्वीकृति हमलोगों ने 2017 की बाढ़ की तैयारी के लिए दी है और उस पर टोटल खर्च आयेगा 1206.82 करोड़ रू0 और इन सारी योजनाओं की स्वीकृति हमलोगों ने दे दी है और इस योजना में माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से सदन को बताना चाहते हैं कि जो हमलोगों ने योजनाओं की स्वीकृति दी है उसमें कुछ वैसी योजनाएं हैं जो चिन्हित हैं, जहां चिन्हित है जहां समस्याएं होती हैं, उन क्षेत्रों में स्थायी समस्या होगी उसके निदान करने के लिए होगा । उसके निदान का कार्य करेंगे जैसे अभी नीरज जी बोल रहे थे

(व्यवधान)

अब ये लोग जो अपने स्वभाव के अनुसार भगोड़ा स्थिति में हो रहे हैं । ये लोग भागने की तैयारी में है , ये सच सुनने के आदी नहीं हैं, ये सच सुनना नहीं चाहते हैं इसलिए जाने दिया जाय। गुमटी टोला में ...

अध्यक्षः मानननीय सदस्यगण, अभी तो माननीय मंत्री जी आपको अच्छी बात जो इस साल आने वाली बाढ़ की आशंका है उसके मद्देनजर जो सरकार की तैयारी है वह बतला रहे हैं वह तो सुन लीजिये न।

(व्यवधान)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्रीः मेरा समय नहीं बर्बाद कीजिये उनका काम ही यही है इसलिए हमने कहा कि बरारी कटिहार जिला में जो गुमटी टोला है, इस्माईलपुर बिंद टोली है भागलपुर जिला में और पतराहा छरकी है गोपालगंज में इन तीनों संवेदनशील बिन्दु है इसको हमलोगों ने स्थायी समाधान का रास्ता निकाला है।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बाहर चले गये)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्रीः इसलिए अध्यक्ष महोदय,जो कई चिन्हित संवेदनशील स्थान है उस पर काम होगा और एक बात अध्यक्ष महोदय, हम बता देना चाहते हैं कि 2017 के लिए जो भी बाढ़ के लिए हमलोगों ने कटाव निरोधक कार्य स्वीकृत किया है।

अध्यक्षः प्रमोद जी आपको छोड़कर सब चले गये।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्रीः 2017 के बाढ़ के लिए जो भी हमलोगों ने योजनाएं स्वीकृत की है, उन सभी योजनाओं को हर हालत में 15 मई तक हमलोग पूरा करेंगे, यह हमने निर्णय किया है । इसके अलावा अध्यक्ष महोदय उसकी गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक हमलोगों ने फैसला किया है सभी कार्यस्थल पर आई0 पी0 कैमरा लगायेंगे और पटना से बैठकर हम उसकी गुणवत्ता की निगरानी करेंगे । इसलिए समय और गुणवत्ता इन दो चीजों के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे और गुणवत्तापूर्ण काम कराने का काम करेंगे। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय,मैं आपको बतलाना चाहता हूँ सिंचाई- जो सिंचाई के बारे में हमने बतलाया कि जो हमारी क्षमता है उस क्षमता का उपयोग हमलोगों ने अबतक नहीं किया है लेकिन जो विभाग का बंटवारा हुआ है उस बंटवारा के बाद सिंचाई के क्षेत्र में हम काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उसका कारण है कि जो सबसे पहला काम हमलोगों ने किया कि कार्य योजना बना दिया कि 2016-17 में आपको कौन-कौन योजना पूरी करनी है, 2017-18 में कौन-कौन योजना पूरी करनी है, 2018-19 में कौन-कौन योजना पूरी करनी है और जो कार्य योजना हमने बनाया है उसके हर 15 दिनों पर प्रधान सचिव के स्तर पर एक-एक बिन्दु की मोनेटरिंग होती है उसकी भौतिक और उसका जो आर्थिक दोनों के प्रगति की समीक्षा प्रधान-सचिव के स्तर पर होती है और उसको हमलोग मोनिटर करते हैं । यही कारण है कि जो हमलोगों ने 2016-17 के लिए पांच योजनाएं चिन्हित किया था उन योजनाओं का

उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने रामपुर लबाईच में जाकर उसको कर देने का काम किया और इसके अलावा जून, 2017 में पांच चार और बड़ी योजनाओं को हमलोगों ने चिन्हित किया है जिसका हमलोग उद्घाटन करायेंगे । वह है वटेश्वर स्थान जो भागलपुर में 1977 से वह योजना चल रही थी । हमने उसको चिन्हित किया और चिन्हित करके वटेश्वर स्थान कहलगांव की जो योजना है, उसको हमलोगों ने लक्ष्य किया है कि जून, 2017 में पूर्ण कर के उसका उद्घाटन करायेंगे। कुंड घाट जलाशय योजना, जो जमुई जिला में है उसको भी हमलोगों ने चिन्हित किया है । सेंधवा चेक डैम जो जहानाबाद और मगध इलाके के लिए योजना है बराज का उसको भी हमलोगों ने चिन्हित किया है कि जून, 2017 में उसका उद्घाटन करायेंगे और एक सिन्धवा चेक डैम है उसको भी हमलोगों ने चिन्हित किया है कि हमलोग उसका उद्घाटन जून में करायेंगे । इसके अलावा सोन नहर योजना, अपर क्यूल जलाशय योजना, हिरम्बी जलाशय, लखीसराय जिलान्तर्गत कोढ़नी बीयर योजना, रोहतास जिलान्तर्गत परहुती वितरणी, कोशी नहर प्रणाली ये सबों को भी पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य हमलोगों ने निर्धारित कर दिया है और उस पर हमलोग रेगुलर मोनेटरिंग कर रहे हैं उसको हमलोग पूरा करेंगे तो इस प्रकार अध्यक्ष महोदय,मैंने आपको बतलाया कि जो पुनर्स्थापन का काम है और सिंचाई के क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सृजन का काम है उसको हमलोग पूरा कर रहे हैं और इस बार कई माननीय सदस्यों ने बताया हम उस पर चर्चा कर के समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं लेकिन रबी के समय में हमलोगों ने जो सिंचाई का लक्ष्य था उसको 100 फीसदी हमलोगों ने पूरा किया है बल्कि पिछले 20 साल का रेकार्ड हमलोगों ने तोड़ देने का काम किया है और सिंचाई की सुविधा इन्द्रपुरी जलाशय सोन इलाके के कई माननीय सदस्य है और सोन इलाका का जो नहर प्रणाली है, उसको स्थायी तौर पर उसमें स्थायित्व देने के लिए हमलोगों ने इन्द्रपुरी जलाशय योजना की स्वीकृति प्राप्त कर ली है, आने वाले 15 महीने के अन्दर मैं सदन को आश्वस्त करता हूँ उस पर काम शुरू करेंगे और उसका शिलान्यास कराने का काम करेंगे तो इस तरह से हमलोगों ने सारी योजनाओं पर काम किया है। नदी जोड़ योजना हमारा जो कोशी मेची लिंक योजना है उस योजना की स्वीकृति हमारी हो गयी है । उसमें इंभायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए भी हमलोगों ने आगे कदम बढ़ा दिया है और एक साल के डाटा पर हमको इंभायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मिल जायेगा सर्टिफिकेट और हम समझते हैं कि जून में हमको कोशी मेचीलिंक का इंभायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का क्लीयरेंस वन एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय से मिल जायेगा और जून के बाद हम उस नदी जोड़ योजना की ओर आगे बढ़ेंगे और उससे जो हमारा पूर्वांचल है उस पूरे क्षेत्र में उससे लगभग लाखों हे0 जमीन हमलोग अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित कर पायेंगे । इसके अलावा सकरी नाटा एक योजना है जो अब स्वीकृति के अंतिम चरण में है और

उस योजना पर भी हमलोग केन्द्रित कर रहे हैं और उस योजना का भी हमलोग करेंगे और उसके अलावे कोशी तटबंध का काम बहुत दिनों से पेंडिंग था उसके लिए भी हमलोगों ने 578.42 करोड़ रू0 का जो रिभाईज्ड स्टीमेट था उसकी प्रशासनिक स्वीकृति देने के बाद उसके निविदा का काम भी हमलोगों ने पूरा कर लिया है और अब शीघ्र उस पर निविदा के निष्पादन कर के और आगे उस पर काम होगा । यह अपने सभी साथियों को बताना चाहते हैं लेकिन एक बात की हम चर्चा जरूर करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि जो भारत सरकार की एजेंसी है जी0एफ0सी0सी0 हो या सेंटर वाटर कमीशन हो, वहां काम उसका दफ्तर पटना में भी है, उनका दफ्तर पटना में इसलिए है कि राज्य सरकार को वह मदद करेगी । मदद करने के बजाय जितना वह अड़ंगा लगा सकते हैं उसी काम में वह सुबह से शाम तक लगे रहते हैं और उनके कारण हमारी योजनाएं जो सिंचाई की है यह बाढ़ की है वह कई योजनाओं में झंझट होता है तो इसलिए हम उस पर ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि समय कम है और उस पर और भी कुछ बिन्दुओं पर चर्चा होनी है । अब गैर संरचनात्मक क्षेत्र में जो बाढ़ के प्रबंधन के बारे में हमने चर्चा किया और उसके बाद एक जल नीति के बारे में चर्चा है वह हम दो मिनट में आपको बता देना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, SAWI के तहत हमलोग 4.75 लाख डालर मने 308.75 लाख से मॉडलिंग क्षमता सुदृढ़ीकरण योजना पर हमलोग काम कर रहे हैं जिस पर उससे हमको लाभ होगा, जल प्रल्लावन क्षेत्र में मॉडलिंग से विकास कर बाढ़ का पुर्वानुमान अर्ली जो सिस्टम है जो हमको पूर्वानुमान देता है उसको हम और बाढ़ के फलस्वरूप संभावित जो जल प्रल्लावन क्षेत्र को चिन्हित करके इसे सामुदायिक स्तर तक कैसे पहुंचाया जा सकेगा उस क्षेत्र पर हमलोग काम कर रहे हैं । नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार विश्व बैंक की सहायता से हमको अभी नेशनल हाईड्रोलौजी प्रोजेक्ट की स्वीकृति की मिली है इस पर हमलोग सैद्धांतिक सहमति राज्य सरकार ने दिया है और राज्य सरकार ने उसको सूचित किया है Real Time Data Acquisition System को हमलोग डेवलप कर रहे हैं उससे गंडक बेसिन का तटबंध जो Embankment Asset Management System है उसको हम विकसित करेंगे और पटना में जल ज्ञान केन्द्र का निर्माण होगा जिससे डाटा सेंटर अवस्थित रहेगा जिसमें डाटा हम स्टोर कर के रख सकते हैं । इसके अलावा सोन कैनाल ऐसेट मैनेजमेंट सिस्टम है और इस तरह से कई अन्य जो सिस्टम है उन सिस्टम को हम इसके तहत जो गैर परम्परागत वह है उसको हम आगे स्ट्रक्चरल जो है नन स्ट्रक्चरल उसको हम उस क्षेत्र में काम कर रहा है जल संसाधन विभाग इसके अलावा हम एक बात कहकर के अध्यक्ष महोदय अपनी बात समाप्त करेंगे कि (क्रमशः)

टर्न-28/मधुप/07.3.2017

...क्रमशः...

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : इसके अलावा हम एक बात कहकर अध्यक्ष महोदय, अपनी बात समाप्त करेंगे कि राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के प्रारूप पर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की 28 दिसम्बर, 2012 की बैठक में हमलोगों ने राय दिया था कि राज्य के अन्दर जल को राज्य के मुद्दे के रूप में शामिल किया जाय, हमारे राज्य में अन्दर जो जल है उसको शामिल किया जाय । हालाँकि भारत सरकार ने उसपर सहमति तो दिया है लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिये वह कोई कमिटी, कमीशन या कोई इस तरह से बनाना चाहते हैं जिसका अभी हमलोग विरोध कर रहे हैं और हमलोग कह रहे हैं कि जब आप एक बार अधिकार दे दिये तो फिर वह राज्य पर छोड़िये, उसपर आप कोई अपना अप्रत्यक्ष नियंत्रण मत रखिये । यह हमलोगों का स्टैंड है । तो इन्हीं शब्दों के साथ में जल संसाधन विभाग के संबंध में जो स्थिति है, उसके बारे में अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से सदन को बताया ।

मैं आशा करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि मेरे इस बात के बाद कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य वापस लें और अध्यक्ष महोदय, हम आपसे आग्रह करते हैं कि जितनी बात छूट गई है, वह इसमें अंकित है, वह इस बजट भाषण का जो उत्तर है, उसका पार्ट बने, यह आप आदेश देने की कृपा करेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने जो लिखित कागजात सदन पटल पर रखा है, उन्हें कार्यवाही का हिस्सा बना दिया जायेगा ।

(परिशिष्ट द्रष्टव्य)

क्या माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा, अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

‘‘इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटायी जाय ।’’

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"जल संसाधन विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्त्ति के लिये 38,14,06,61,000/- (अड़तीस अरब चौदह करोड़ छः लाख एकसठ हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।"

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मॉग स्वीकृत हुई ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन में आगमन हुआ)

अध्यक्ष : आज दिनांक 7 मार्च, 2017 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 32 (बत्तीस) है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

शोक - प्रकाश

माननीय सदस्यगण, आज सभा के अंत में मुझे आप सभी सदस्यों को दुखद सूचना भी देनी है कि चलते सत्र के दौरान दो ख्याति प्राप्त जन-प्रतिनिधियों के निधन की सूचना हमें मिली है जिनके प्रति शोक प्रकट करना हमारा फर्ज है ।

स्वर्गीय सैयद शहाबुद्दीन

लोक सभा एवं राज्य सभा के पूर्व सदस्य श्री सैयद शहाबुद्दीन का निधन दिनांक 04 मार्च, 2017 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 82 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय शहाबुद्दीन किशनगंज जिला के किशनगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1984 एवं 1991 में लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे जुलाई, 1979 से अप्रील, 1984 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे थे । उन्होंने कई देशों में भारत के राजदूत के पद पर भी कार्य किया था । स्वर्गीय शहाबुद्दीन एक शिक्षाविद्, अध्यापक, राजनयिक एवं अधिवक्ता भी थे । साथ-ही, पत्रकारिता में भी उनकी गहरी अभिरूचि थी । उन्होंने कई सामाजिक संगठनों के माध्यम से समाज के दबे-कुचले एवं अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया था । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय रवि रे

लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष तथा भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्री रवि रे का निधन दिनांक 06 मार्च, 2017 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 90 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय रवि रे उड़ीसा राज्य के पुरी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1967 एवं केन्द्रपाड़ा से वर्ष 1989 एवं 1996 में लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे 03 अप्रील, 1974 से 02 अप्रील, 1980 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे थे । उन्होंने वर्ष 1989 में लोक सभा के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया था । वे भारत सरकार में मंत्री भी रहे थे । वे वर्ष 1977-78 में प्रेस कौंसिल के अध्यक्ष भी रहे थे । प्रख्यात समाजवादी स्वर्गीय रवि रे का जीवन सादगीपूर्ण था । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये प्रार्थना करेंगे ।

(एक मिनट का मौन)

मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भेजवा दूँगा ।

अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 08 मार्च, 2017 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।

....

परिशिष्ट

माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के बजट भाषण हेतु सामग्री (वर्ष 2017–2018)

विभाग का कार्यकलाप (Function of the Department)

जल संसाधन विभाग के मुख्य कार्य के अन्तर्गत राज्य में वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन एवं ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित करना है। वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अर्न्तगत राज्य में Ultmimate Irrigation Potential 53.53 लाख हेक्टेयर है। इसके विरूद्व मार्च 2016 तक 29.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जा चुका है, परन्तु कोशी, गंडक एवं अन्य नदियों में अत्यधिक गाद आने के कारण वर्त्तमान में सिंचाई क्षमता घटकर 21 लाख हेक्टेयर ही रह गई है। अतएव 8.46 लाख हेक्टेयर की ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुर्नस्थापित करने एवं Ultmimate Irrigation Potential के लक्ष्य को हासिल करने के उदेश्य से विभाग को पुनर्गठित किया गया है। इसके तहत् सिंचाई एवं बाढ़ की योजनाओं के लिए अलग–अलग अभियंता प्रमुख के अधीन कनीय अभियंता तक के पदाधिकारी को अलग–अलग स्वतंत्र दायित्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर एक अलग अभियंता प्रमुख का पद सृजित किया गया है, जिसके अन्तर्गत योजनाओं का अनुश्रवण, रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, समग्र योजना, अन्वेषण एवं योजना आयोजन, यांत्रिक के कार्यालय एवं जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) हैं।

➢ **2016–17 का बाढ़**

➢ वर्ष 2016 में राज्य की नदियों में अप्रत्याशित बाढ़ आई, जिसके कारण तीन जगहों पर जल स्तर नई उँचाई को छू लिया। गंगा नदी का जल स्तर गांधी

घाट में दिनांक 21.08.2016 को अधिकतम 50.52 मी० दर्ज किया गया जो पिछले अधिकतम जल स्तर 50.27 मी० (1994) से 0.25 मी० अधिक रहा। इसी प्रकार हाथीदह में दिनांक 22.08.2016 को अधिकतम जल स्तर 43.17 मी० दर्ज किया गया जो पिछले उच्चतम जल स्तर 43.15 मी० (1971) से 0.02 मी० अधिक रहा। भागलपुर में गंगा नदी का जल स्तर दिनांक 26.08.2016 को 34.71 मी० दर्ज किया गया जो पिछले उच्चतम जल स्तर 34.50 मी० (2013) से 0.21 मी० अधिक रहा। इसके कारण गंगा एवं इसकी सहायक नदियों यथा गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोशी, महानन्दा, सोन, पुनपुन आदि में लम्बे समय तक बाढ़ की स्थिति बनी रही।

- गंडक नदी के बाल्मीकिनगर में अधिकतम जलश्राव दिनांक 27.07.2016 को 3,50,000 क्यूसेक प्रवाहित हुआ, जिसके कारण बराज का गेट क्षतिग्रस्त हो गया। कई दिनों तक बाढ़ की स्थिति बनी रही। इस बीच खरीफ सिंचाई की अवधि में स्टॉप लॉग का प्रयोग कर सिंचाई की सुविधा जारी रखी गई। इसके अतिरिक्त गंडक तटबंध के कई जगहों पर अत्यधिक दबाव रहा जहाँ हो रहे क्षरण को युद्ध स्तर पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर सुरक्षित किया गया।

- बाढ़ 2016 के दौरान कोशी नदी में अधिकतम जल श्राव दिनांक 13.09.2016 को 2,98,215 क्यूसेक प्रवाहित हुआ। साथ ही कोशी नदी में 2,50,000 क्यूसेक से अधिक का जलश्राव चार बार एवं दो लाख से ढ़ाई लाख क्यूसेक के बीच का जलश्राव नौ बार प्राप्त हुआ, जिसके कारण तटबंध के कई भागों में अत्यधिक दबाव रहा। पूर्वी काशी तटबंध के स्पर सं० 10 पर कटाव को नियंत्रित करने हेतु लागातार बाढ़ संधर्षात्मक का कार्य कराकर स्थल को

सुरक्षित रखा गया। इसके अतिरिक्त पूर्वी बाह्योत्थान बॉध के कि०मी० 26.40, 26.88, 27.10 एवं 27.40 पर स्थित स्पर, पूर्वी कोशी तटबंध के कि०मी० 9.25, 9.50, 19.92, 20.20, 25.14 एवं 78.60 पर स्थित स्पर, पश्चिमी कोशी तटबंध के कि०मी० 38.50 पर स्थित स्पर एवं विस्तारित सिकरहट्टा मंझारी निम्न बॉध के कि०मी० 9.00, 9.40, 11.20, पर स्थित स्टड तथा कि०मी० 8.7 से 9.00 के बीच अत्यधिक दबाव रहा। इन स्थलों को आवश्यक बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर सुरक्षित रखा गया।

- सोन नदी में भी इस वर्ष अप्रत्याशित बाढ़ आई। वाणसागर जलाशय से अचानक अधिक पानी छोड़े जाने एवं उत्तर कोयल नदी बेसिन में भारी वर्षा होने के कारण इन्द्रपुरी में अधिकतम जलश्राव दिनांक 20.08.2016 को 11,67,141 क्यूसेक प्रवाहित हुआ। इसके कारण नदी के दोनों तट पर बाढ़ की स्थिति बन गयी एवं इसका प्रभाव गंगा नदी पर फरक्का तक पड़ा। गंगा नदी के तट पर स्थित राज्य के 12 जिले प्रभावित हुए।

- पुनपुन एवं दरधा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण इसका जल स्तर कई दिनों तक ऊँचा रहा एवं पटना जिला के कई स्थानों पर अत्यधिक दबाव बना रहा। पुनपुन एवं फुलवारी प्रखंड के अर्न्तगत कोली, वघपुर, अलावलपुर, जाहिदपुर, मनौरा, चामुचक इत्यादि स्थलों पर बाढ़ संर्घषात्मक कार्य कराकर सुरक्षित रखा गया।

- **गंगा की अविरलता**

बिहार राज्य में बाढ़ का मुख्य कारण गंगा एवं अन्य नदियों में अधिक सिल्ट का जमाव होना है। फरक्का बराज के दुष्परिणाम के रूप में गंगा नदी के तल

में पटना तक उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वास्तव में गंगा नदी की धारा की अविरलता समाप्त हो गयी है। गंगा नदी की अविरलता को पुनर्स्थापित करने के उदेश्य से हेतु 25–26 फरवरी 2017 को पटना में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश के नदियों के विभिन्न पहलुओ की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों ने भाग लिया। जल पुरूष श्री राजेन्द्र सिंह इस मौके पर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में पद्मभूषण श्री चंडी प्रसाद भट्ट, पद्म श्री संत बलवीर सिंह सीचेवाल, श्री जयंत बद्योपाध्याय, श्री भरत झुनझुनवाला एवं श्रीमती बंदना शिवा द्वारा भाग लिया गया। "गंगा की अविरलता" को राज्य सरकार एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है एवं इसके केन्द्र में फरक्का बराज के साथ–साथ गंगा नदी में हल्दिया से इलाहाबाद के बीच बड़ी संख्या में बराज निर्माण कराये जाने का विरोध रहेगा। केन्द्र द्वारा प्रस्तावित Integreted National Inland Waterways Trasportation Grid (INIWTG) के तहत इलाहाबाद से हल्दिया तक प्रस्तावित बराज श्रृखला के निर्माण को गंगा नदी के निरंतरता, अविरलता और निर्मलता के लिए घातक पाए जाने के कारण उक्त सम्मेलन में विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कराए बिना किसी प्रकार का निर्माण केन्द्र सरकार को स्थगित रखना चाहिए।

- **बाढ़ 2017 की तैयारी**

➢ बाढ़ 2016 के अनुभव एवं सेटेलाईट इमेजरी के आधार पर तटबंध की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक योजनाओं की तैयारी की गई है, जिसे बाढ़ 2017 के पूर्व पूरा किया जायेगा। राज्य योजना के अन्तर्गत रू० 432.28 करोड़ की लागत

पर 249 अदद् कटाव निरोधक योजनाएँ, बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत रू० 370.69 करोड़ की लागत पर 4 अदद, आर०एम०ए०डब्लू०बी०ए० के अन्तर्गत रू० 103.92 के लागत पर नेपाल भाग में 14 अदद एवं आपदा निधि के अन्तर्गत रुपए 299.93 करोड़ की लागत पर 50 अदद् योजनाएँ अर्थात् कुल 317 अदद् योजनाएँ रुपए 1206.82 करोड़ की लागत राशि पर पूर्ण करने का कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड से रुपए 408.23 करोड़ की लागत पर 12 अदद् तटबंध सुदृढ़ीकरण योजनाएँ कराए जाने का कार्यक्रम है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप कई स्थानों यथा कटिहार जिला अन्तर्गत गुमटी टोला, भागलपुर जिला अन्तर्गत इस्माईलपुर–बिन्दटोली एवं गोपालगंज जिला अन्तर्गत पतरहा छरकी पर कटाव का स्थायी समाधान निकल सकेगा। इन सभी बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं को 15 मई, 2017 तक पूरा करने का कार्यक्रम है। इसकी गुणवत्ता और समय के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उच्चस्तर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संवेदनशील स्थलों की निगरानी हेतु आई०पी० कैमरा स्थापित किया जाना है तथा मशीन निर्मित जी०आई० वायर क्रेट एवं मशीन की सिलाई वाले नए बैग का उपयोग किया जाना है।

- **सिंचाई**

➤ वृहद एवं मध्यम सिंचाई के माध्यम से राज्य में Ultmimate Irrigation Potential 53.53 लाख हेक्टेयर है। इसके विरूद्ध अब तक 29.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित की जा सकी है। पुरानी योजनाओं में गाद जमा होने एवं संरचनाओं के क्षतिग्रस्त होने से सिंचाई क्षमता का ह्रास होता है, जिसके कारण सृजित सिंचाई क्षमता में लगभग 8.46 लाख हेक्टेयर

का ह्रास हो गया है। इस ह्रासित क्षमता को पूर्णस्थापित करने के उदेश्य से कार्य योजना तैयार कर उस पर अमल किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 के लिए तैयार किये गये कार्य योजना के अर्न्तगत 5 अदद् योजनाएँ यथा पटना जिलान्तर्गत लवाईच–रामपुर बराज योजना, औरंगाबाद जिलान्तर्गत जगन्नाथ वीयर, जहानाबाद जिलान्तर्गत मोर वीयर एवं सोलहण्डा वीयर तथा अरवल जिलान्तर्गत पंतित वीयर का कार्य पूर्ण कर इसका उद्घाटन किया जा चुका है।

क्रम	योजना का नाम	सृजित सिंचाई क्षमता (हे0)	पुनर्स्थापित सिं0 क्षमता (हे0)	लाभान्वित जिले
1	लवाईच रामपुर बराज	8000		पटना
2	जगन्नाथ वीयर	2140		औरंगाबाद
3	मोर वीयर		2476	जहानाबाद
4	सोलहण्डा वीयर	700		जहानाबाद
5	पंतित वीयर		8097	अरवल, जहानाबाद, पटना
	कुल	**10840**	**10573**	

- वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभिन्न योजनाएँ यथा रोहतास, कैमूर, भोजपुर एवं बक्सर जिला अर्न्तगत सोन नहर योजना, जमुई जिला अर्न्तगत अपर किऊल जलाशय योजना, बांका जिला अर्न्तगत हिरम्बी जलाशय योजना, लखीसराय जिला अर्न्तगत कोढ़नी वीयर योजना, रोहतास जिला अर्न्तगत परहुती वितरणी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, सुपौल, मधेपुरा एवं सहरसा जिला अर्न्तगत पूर्वी कोशी नहर नहर प्रणाली का पुनर्स्थापन कर कुल 1,29,372 हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित होगी।

- विभाग के द्वारा अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन की योजनाओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप **जून 2017 तक** जहानाबाद जिला अर्न्तगत उदेरास्थान बराज योजना, जमुई जिला अर्न्तगत कुण्डघाट जलाशय योजना, जहानाबाद जिला अर्न्तगत सेंधवा चेक डैम का निर्माण कार्य पूर्ण कर एंव भागलपुर जिला अर्न्तगत बटेस्वस्थान गंगा पम्प नहर योजना से सिंचाई प्रारम्भ कर कुल 37,685 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषकों को सिंचाई की सुविधा प्रदान की जायेगी।

- उपर्युक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2017–18 में मुंगेर जिला अर्न्तगत चानकेन सिंचाई योजना, जहानाबाद जिला अर्न्तगत मण्डई वीयर, गया जिला अर्न्तगम ढाढर अपसरण योजना, बक्सर जिला अंन्तर्गत काव जलाशय योजना, रोहतास जिला अर्न्तगत अवशाने जलाशय योजना, मधुबनी जिला अर्न्तगत बलवा घाट योजना एवं अन्य योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर कुल 84,856 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजन कर कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

- वित्तीय वर्ष 2017–18 में ह्रासित सिंचाई क्षमता के पुनर्स्थापन के तहत रोहतास जिला अर्न्तगत सोन समानान्तर लिंक नहर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया एवं कटिहार जिला अर्न्तगत पूर्वी कोशी नहर प्रणाली (ई०आर०एम०), बक्सर जिला अर्न्तगत चौसा पम्प नहर योजना, कैमूर जिला अर्न्तगत सुअरा वीयर योजना, जमुई जिला अर्न्तगत कुन्दर बराज योजना, शेखपुरा जिला अर्न्तगत दरियापुर वीयर योजना एवं अन्य योजनाओं के

पुनर्स्थापन से कुल 1,88,883 हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित किया जायेगा।

- **वर्ष 2016 में रिकार्ड खरीफ सिंचाई उपलब्धि**

वर्ष 2016–17 खरीफ में नहरों के अन्तिम छोर तक पानी पहुंचाकर 19.31 लाख हेक्टेयर में कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह विगत 28 वर्षों में सर्वाधिक है। अभी रब्बी में 8.01 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरूद्ध सिंचाई प्रदान की जा रही है। नहरों के सम्पोषण एवं अंतिम छोर तक सिंचाई सुनिश्चत करने के उद्देश्य से विभाग के द्वारा एक नहर सम्पोषण नीति बनाई जा रही है जो सिंचाई उपलब्धि में उत्तरोत्तर सुधार में मील का पत्थर साबित होगा।

- **इन्द्रपुरी जलाशय योजना**

सोन नदी के जल का संरक्षण कर सिंचाई एवं अन्य उपयोग हेतु इन्द्रपुरी जलाशय योजना का निर्माण लम्बे समय से विचाराधीन है। इस योजना पर फरवरी, 2017 में उत्तरप्रदेश की सहमति प्राप्त हो गई है। कन्सलटेन्ट के माध्यम से योजना का डी०पी०आर० तैयार किया जाना है, जिसके लिए 15 महीने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के पूरा होने से सोन एवं अन्य नहर प्रणालियों की सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी तथा स्थायित्व प्राप्त होगा। इससे रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना एवं नालंदा जिले को लाभ होगा। इस योजना को यथाशीघ्र पूरा करने हेतु सरकार दृढ़ संकल्प है।

दुर्गावती नहर प्रणाली

दुर्गावती नहर प्रणाली का कार्य विभिन्न कारणों से लंबित रहा। अब इस प्रणाली में कोई समस्या नहीं है। इस प्रणाली में मुख्य नहरों का निर्माण हो चुका है। 29 अदद् वितरणियों का निर्माण किया जाना है, जिसका कार्य चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में माह जून 2017 तक दुर्गावती जलाशय योजना के कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। इस योजना से रोहतास एवं कैमूर जिले के किसानों को लगभग 21,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

- **कोशी तटबंध सुदृढ़ीकरण एवं कालीकरण का कार्य**

पूर्वी एवं पश्चिमी कोशी तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण, इसके कालीकरण एवं संरचनाओं के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य की रुपए 578.42 करोड़ की पुनरीक्षित योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्य के कार्यान्वयन से सुपौल जिला के बसन्तपुर, सरायगढ़, निर्मली, किशनपुर, सुपौल एवं मरौना प्रखण्ड, मधुबनी जिला के लौकही, मधेपुर, घोघरडीहा प्रखण्ड, दरभंगा जिला के कीरतपुर प्रखण्ड एवं सहरसा जिला के नवहट्टा, महिषी, सिमरी–बख्तियारपुर तथा सलखुआ प्रखण्ड की एक बहुत बड़ी आबादी को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी साथ ही उन्हें आवागमन हेतु एक वैकल्पिक सड़क की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। इस कार्य को मार्च, 2018 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। इसकी निविदा प्राप्त हो चुकी है, जो निस्तार की प्रक्रिया में है।

महानंदा बाढ़ प्रबंधन योजना

इस योजना के तहत् महानन्दा बेसीन के विभिन्न नदियों पर 1195.871 कि०मी० नए तटबंध निर्माण एवं 95.20 कि०मी० पूर्व से निर्मित तटबंधों के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य का रुपए 603.88 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।

महानन्दा बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–I के तहत् महानन्दा बेसीन के नीचले भाग में पूर्व से निर्मित 95.20 कि०मी० तटबंध के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं ब्रीक सोलिंग का कार्य मार्च, 2013 में पूर्ण कर लिया गया है।

महानन्दा बाढ़ प्रबंधन योजना फेज–II के तहत् 199.95 कि०मी० महानन्दा, रतवा एवं नागर नदी पर नए तटबंध का निर्माण किया जाना है। इससे संबंधित रुपए 762.505 करोड़ की योजना गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को तकनीकी ऐप्रेजल हेतु समर्पित है। इस फेज में नए तटबंध के निर्माण हेतु भू–अर्जन के लिए रुपए 19544. 026 लाख की राशि जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को भुगतान कर दी गई है।

महानन्दा बाढ़ प्रबंधन योजना फेज– III, IV एवं V के तहत् 995.92 कि०मी० नए तटबंध का निर्माण किया जाना है, जिसका विस्तृत योजना प्रतिवेदन एवं भू–अर्जन की कार्रवाई की जा रही है।

- **रीवर इन्ट्रालिंकिंग स्कीम्स**

विभाग राज्य की नदियों को आपस में जोड़कर नई योजनाओं के सृजन एवं कार्यान्वयन पर गंभीरता से कार्य कर रहा है। इन योजनाओं में सिंचाई के साथ बाढ़ प्रबंधन की अपार संभावनाएँ हैं। इस क्रम में कोशी बेसीन से पूर्व महानन्दा बेसीन में

बीच की नदियों को जोड़कर जलान्तरण करने की एक महत्वाकांक्षी योजना – कोशी–मेची–लिंक योजना है। इसके विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर भारत सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। अब इस पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। योजना से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन एवं आवश्यक प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य परामर्शी को सौंपा गया है। विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि योजना की स्वीकृति यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। इस योजना के कार्यान्वयन से अररिया, सहरसा, सुपौल, किशनगंज एवं पूर्णिया जिले के 2,11,400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। दो अन्य योजनाएँ – सकरी एवं नाटा नदी के बीच लिंक योजना तथा बूढ़ी गंडक–नून–बाया–गंगा लिंक योजना केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार के स्तर पर जाँच के क्रम में है। इसके अतिरिक्त 8 अन्य नदी जोड़ योजनाएँ संभाव्यता अध्ययन स्तर पर है।

- **गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग/केन्द्रीय जल आयोग के स्तर पर योजनाओं के क्लीयरेंस में विलम्ब किया जाना एवं क्रेन्द्रांश की विमुक्ति की जटिल प्रक्रिया**

➢ गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, भारत सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में बाढ़ की समस्या के निदान हेतु तकनीकी सहयोग करना है। इसका कार्यालय पटना में अवस्थित है। राज्य के अन्दर गंगा एवं इसकी सहायक नदियों में कटाव निरोधक एवं बाढ़ प्रबंधन की योजनाओं के सूत्रण हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति में इस आयोग के सदस्य होते हैं। उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के उपरांत राज्य तकनीकी सलाहकार समिति (TAC), स्कीम रिव्यू कमिटि (SRC) एवं बाढ़ नियंत्रण पर्षद के अनुमोदन के उपरांत बाढ़ नियंत्रण की

योजनाएँ केन्द्र की स्वीकृति हेतु गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में भेजी जाती है। तत्पश्चात केन्द्र सरकार के स्तर पर Interministrial Committee एवं Investment Clearance के उपरांत राशि की विमुक्ति की जटिल प्रक्रिया निर्धारित है। जिसके चलते राज्य के बाढ़ की योजनाओं का समय पर न तो क्लीयरेंस हो पाता है और न ही केन्द्रांश की राशि समय पर प्राप्त होती है। इसके बावजूद गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग से योजनाओं की स्वीकृति में काफी विलम्ब होता है और योजनाएँ समय पर पूरा नहीं हो पाती। मार्च 2016 तक केन्द्रीय सहायता की बकाया राशि सिंचाई योजनाओं के लिए रू० 632.218 करोड़ एवं बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम की योजनाओं के लिए रू० 248.96 करोड़ है। इसी प्रकार दिसम्बर 2016 तक आर०एम०ए०डब्लू०बी०ए० के अर्न्तगत कुल रू० 66.733 करोड़ का बकाया है।

- राज्य की सिंचाई योजनाओं पर केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से इसे केन्द्रीय जल आयोग के पास स्वीकृति हेतु भेजी जाती है। आयोग में योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया काफी लम्बी एवं जटिल है। इसके कारण स्वीकृति में 2 वर्ष से अधिक का समय लग जाता है। प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु विभाग से कई बार अनुरोध किया गया है किन्तु इसका सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हो सका है।

- **बाढ़ प्रबंधन के गैर–संरचनात्मक उपाय**

- बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का उपयोग कर दक्षता एवं गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करने के प्रति विभाग सदा उन्मुख रहा है। विश्व बैंक एवं

अन्य बाह्य एजेन्सियों के सहयोग से ऐसे कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं जो आने वाले समय में काफी उपयोगी सिद्ध होगा।

- **SAWI** - विश्व बैंक प्रशासित South Asia Water Initiative (SAWI) से प्राप्त निधि, यू०एस० डॉलर 4.75 लाख अर्थात् रु० 308.75 लाख से मॉडलिंग क्षमता सुदृढ़ीकरण योजना पर कार्य किया जा रहा है। प्रस्तावित योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बागमती–अधवारा बेसीन क्षेत्र में बाढ़ पूर्वानुमान एवं जल प्लावन क्षेत्र मॉडलिंग का विकास कर बाढ़ पूर्वानुमान एवं बाढ़ के फलस्वरूप संभावित जल प्लावन क्षेत्र को चिन्हित कर इसे सामुदायिक स्तर तक ससमय पहुँचाना है ताकि बाढ़ से होने वाली क्षति को कम किया जा सके। बागमती–अधवारा एवं कोशी बेसीन क्षेत्र के लिए मौसम सम्बन्धी ढाँचा तैयार कर समवेत वर्षा पूर्वानुमान/ अनुमान (Ensemble Rainfall forecast/ estimate) का कार्य प्रगति में है। साथ ही बाढ़ मॉडलिंग क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण भी दिया जाना है।

- **NHP** - जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार विश्व बैंक की सहायता से संपूर्ण भारत में नेशनल होइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट (National Hydrology Project) का समन्वय कर रहा है। इस परियोजना में बिहार सहित अन्य राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों, केन्द्रीय एजेंसियों एवं नदी बेसीन संगठनों को सम्मिलित किया गया है। जल संसाधन विभाग, बिहार राज्य के सरफेस–वाटर अवयव के लिए उत्तरदायी संस्था है। इस योजना के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार एवं जल संसाधन विभाग, बिहार के बीच Memorandum of Agreement हस्ताक्षरित हो चुका है। विश्व बैंक एवं भारत सरकार के बीच इस परियोजना

से सम्बन्धित एकरारनामा शीघ्र अपेक्षित है। जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से इस योजना का पूरे आठ वर्ष (2016–2024) के लिए प्रारंभिक बजट रु० 105.00 करोड़ संसूचित किया गया है। NHP के तहत मुख्यतः निम्नांकित कार्य प्रस्तावित है –

(i) Real Time Data Acquisition System (RTDAS) के अंतर्गत पाँच बेसीनों (गंडक, महानन्दा, सोन, पुनपुन एवं किउल–हरोहर) तथा अठारह डैम/जलाशयों (चंदन, बदुआ, फुलवरिया, अपर किउल, दुर्गावती, खड़गपुर लेक, कोहिरा, नागी, अमृती, श्रीखंडी, कोल महादेव, मोरवे, कैलाश घाटी, नकटी, बेलहरना, आंजन, ओढ़नी एवं विलासी) में Hydromet instruements की आपूर्ति एवं प्रतिष्ठापन का कार्य।

(ii) गंडक बेसीन का तटबंध परिसम्पति प्रबंधन प्रणाली (Embankment Asset Management System) विकसित करना।

(iii) पटना में जल ज्ञान केन्द्र का निर्माण जिसमें डाटा सेन्टर अवस्थित रहेगा।

(iv) चंदन नदी के क्रॉस–सेक्शन का कार्य।

(v) सोन नहर परिसम्पति प्रबंधन प्रणाली (Sone Canal Asset Management System) विकसित करना।

(vi) केन्द्रीय जल आयोग के सुझाव के आलोक में मॉडलिंग/जलाशय नियमन योजना कार्यों के लिए नदियों के क्रॉस–सेक्शन एवं हाइड्रो–मेटियोरोलॉजिकल आँकड़ों का संग्रहण एवं प्रेषण।

➢ **बिहार कोशी फ्लड रिकवरी परियोजना –**

(i) इस योजना अंतर्गत कोशी नदी बेसीन हेतु तटबंध परिसम्पति प्रबंधन प्रणाली (Embankment Asset Management System) विकसित किया जा चुका है जो तटबंध के बेहतर मॉनिटरिंग में सहायक है।

(ii) कोशी नदी के बाढ़ एवं गाद प्रबंधन कार्य का मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

(iii) कोशी नदी का River Behavioral Analysis का कार्य पूरा कर लिया गया है, जिससे Monsoon के पूर्व Satellite Images के आधार पर नदियों का shifting एवं तटबंध कटाव का आकलन किया जाता है।

(iv) जल संसाधन के प्रबंधन हेतु Center of Excellence की स्थापना कार्य प्रस्तावित है जिसके अर्न्तगत मैथमेटिकल मौडलिंग केन्द्र का स्थापन पटना में एवं फिजिकल मौडलिंग केन्द्र का स्थापन वीरपुर में प्रस्तावित है।

(v) कोशी नदी बेसीन का फ्लड फॉरकास्ट मॉडलिंग कार्य प्रगति में है जिसके आधार पर बाढ़ पूर्वानुमान संभव हो सकेगा।

(vi) इस योजना के अंतर्गत संरचनात्मक कार्यों के अंतर्गत मुख्यतः पूर्वी कोशी तटबंध के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 28.20 तक सुदृढ़ीकरण कार्य के अन्तर्गत कि०मी० 0.00 से 15.50 के बीच spur protection का कार्य प्रगति में है।